दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स टुडे

वर्ष 5 | अंक 9 | कुल अंक 57 | मार्च 2020 | ₹ 120

फैक्टशीट

महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित

इंटरव्यू की तैयारी : क्या हो सही रणनीति?
भाग-1
(द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति)

टारगेट प्रिलिम्स-2020 चौथी कड़ी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

महत्त्वपूर्ण लेख

महात्मा बुद्ध के नैतिक विचार
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ : समग्र विश्लेषण
वर्चुअल तथा ऑग्मेंटेड रियलिटी
क्या दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध की ओर अग्रसर है?

टॉपर से बातचीत

श्रीकांत कोराम
(CGPSC-2018 परीक्षा में द्वितीय रैंक पर चयनित)

संघीय बजट 2020-21

संपूर्ण 'योजना', 'कुरुक्षेत्र' (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) समेत महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का सार

माइंड मैप एवं महत्त्वपूर्ण निबंध	प्रिलिम्स एवं मुख्य परीक्षा के हल सहित अभ्यास प्रश्न-पत्र	मानचित्रों से सीखें (भारत एवं विश्व)

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

प्रिलिम्स-2020 के लिये

करेंट अफेयर्स क्रैश कोर्स

प्रिय विद्यार्थियों,

आई.ए.एस. प्रारंभिक परीक्षा में करेंट अफेयर्स के अत्यधिक महत्त्व को देखते हुए हम पिछले कई वर्षों से इस सेग्मेंट की कक्षाएँ आयोजित करते रहे हैं। हमेशा की तरह इस वर्ष भी ये विशेष कक्षाएँ शुरू की जा रही हैं।

आप जानते ही हैं कि पिछले 5 वर्षों से प्रिलिम्स परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्त्व करेंट अफेयर्स का हो गया है। सिर्फ इस खंड से 25-35 तक प्रश्न (100 में से) पूछे जा रहे हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि प्रिलिम्स परीक्षा में सफलता का मार्ग करेंट अफेयर्स ही है।

करेंट अफेयर्स को समझना और याद रखना तब आसान होता है जब इन्हें आपस में सभी विषयों के साथ लिंक करके पढ़ा जाए। पढ़ाने का यही तरीका दृष्टि की अध्यापन पद्धति के मूल में है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध
कुल **35-40** कक्षाएँ (लगभग **120** घंटे)

आरंभ

20 मार्च	30 मार्च
क्लासरूम कार्यक्रम	ऑनलाइन कार्यक्रम

अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस क्रैश कोर्स से प्रिलिम्स के करेंट अफेयर्स में पूछे जाने वाले 90% + प्रश्न आसानी से कवर होते हैं। आप भी इस अवसर का लाभ उठाइये और प्रिलिम्स के परिणाम में अपनी दावेदारी सुनिश्चित कीजिये।

ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिये आज ही
गूगल प्ले स्टोर से हमारी एंड्रॉएड ऐप Drishti Video Classes इंस्टॉल करें।

अधिक जानकारी के लिये फोन करें : 8448485521 या विज़िट करें : www.drishtiIAS.com

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9 Ph.: 87501 87501, 011-47532596
E-mail: online@groupdrishti.com, info@drishtiias.com, *Website: www.drishtiias.com

दृष्टि The Vision | drishti

Think IAS Think Drishti

अब घर बैठे कीजिये आई.ए.एस. की तैयारी क्योंकि हम आ रहे हैं आपके घर

ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्स

आई.ए.एस. प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स (IAS Prelims Online Course)

प्रिय विद्यार्थियो,

संसाधन की कमी अक्सर हमारी उड़ान को सीमित कर देती है। हममें आगे बढ़ने की तड़प तो खूब होती है किंतु उसे साकार करने वाले साधनों का अभाव हमें मायूस कर देता है। पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों से आप जैसे हज़ारों विद्यार्थियों ने हमें इस आशय के संदेश भेजे कि वो सिविल सेवा में जाने की इच्छा तो रखते हैं किंतु इसकी तैयारी के लिये दिल्ली में रहने का भारी-भरकम खर्च उठा पाना उनके लिये संभव नही है। साथ ही आपने हमसे यह अपेक्षा भी व्यक्त की कि हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जिसमें आप घर-बैठे दृष्टि की कक्षा कार्यक्रम जैसी गुणवत्तापरक क्लास कर पाएँ। आपके इन्हीं निवेदनों को ध्यान में रखते हुए हम अपना पहला 'पेन ड्राइव कोर्स' जारी कर रहे हैं जो आई.ए.एस. प्रिलिम्स के पाठ्यक्रम पर केंद्रित है। इसमें आप सामान्य अध्ययन तथा सीसैट के कोर्स ले सकते हैं। लगभग 2 वर्षों की कठोर मेहनत से तैयार हुआ यह वीडियो कोर्स गुणवत्ता में अच्छे से अच्छे क्लासरूम प्रोग्राम को टक्कर दे सकता है। हमें विश्वास है कि यह कोर्स उस अंतराल को भरने में सफल होगा जो दिल्ली में रहकर तैयारी करने वाले और दिल्ली नहीं आ पाने वाले विद्यार्थियों के बीच बना रहता है। निकट भविष्य में हम IAS मुख्य परीक्षा और विभिन्न राज्यों की PCS परीक्षाओं के लिये भी ऑनलाइन कोर्स शुरू करेंगे।

एडमिशन प्रारंभ

विद्यार्थियों की भारी माँग को देखते हुए ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्स
पर 20% की विशेष छूट अब शुरुआती 1000 विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध

मोड : पेन ड्राइव

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS की प्लेलिस्ट Online Courses में देखें	ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com पर FAQs पेज देखें

IAS प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

1. 500+ घंटे की सामान्य अध्ययन की कक्षाएँ।
2. 120+ घंटे की सीसैट की कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा ताकि आप रिवीज़न भी कर सकें।
4. कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल। इमेज, वीडियो आदि की मदद से कठिन विषय समझाने की शैली।
5. हर क्लास के अंत में उस टॉपिक से IAS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का अभ्यास।
6. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
7. प्रिलिम्स के ठीक पहले करेंट अफेयर्स की 30 ऑनलाइन कक्षाएँ (निशुल्क)।
8. ऑनलाइन प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ (25+5 टेस्ट) की निशुल्क सुविधा।
9. क्विक बुक सीरीज़ की 8 पुस्तकें निशुल्क, जिनके अलावा कोई और स्टडी मैटीरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं।
10. इस कोर्स को करने के बाद अगर आप दृष्टि की किसी भी शाखा में सामान्य अध्ययन (फाउंडेशन कोर्स) करते हैं तो आपकी ऑनलाइन कोर्स की फीस की 50% राशि की छूट दी जाएगी।

हिंदी साहित्य : पेन ड्राइव कोर्स (Hindi Literature : Pendrive Course)

प्रिय विद्यार्थियों,

1 नवंबर, 2019 को हमने अपना पहला पेन ड्राइव कोर्स शुरू किया था जो आईएएस प्रिलिम्स परीक्षा के लिये था। जिस दिन वह कोर्स शुरू होने की घोषणा हुई, उसी दिन से लगातार हमें ऐसे संदेश मिलने लगे कि बहुत से विद्यार्थी विकास सर से हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं किंतु वे कक्षाएँ करने के लिये दिल्ली या प्रयागराज नहीं आ सकते। उन सभी का निवेदन था कि हमें हिंदी साहित्य के लिये भी ऑनलाइन या पेन ड्राइव कोर्स का विकल्प उपलब्ध करवाना चाहिये।

इन निवेदनों को देखते हुए, लगभग दो महीनों तक तकनीकी पक्षों पर कार्य करने के बाद, अब हम हिंदी साहित्य के पेन ड्राइव कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। इस कोर्स में विकास सर द्वारा ली गई कक्षाओं की ही रिकॉर्डिंग (सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता में) उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा दावा है कि इस कोर्स की कक्षाएँ गंभीरता से करने के बाद किसी विद्यार्थी के लिये हिंदी साहित्य में अच्छे अंक लाना मुश्किल नही होगा।

हमें पूरा विश्वास है कि यह कोर्स उस अंतराल को भरने में सफल होगा जो दिल्ली में रहकर तैयारी करने वाले और दिल्ली नहीं आ पाने वाले विद्यार्थियों के बीच बना रहता है। निकट भविष्य में हम आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं के लिये कई नए पेन ड्राइव कोर्स शुरू करेंगे।

एडमिशन प्रारंभ

पहले 200 विद्यार्थियों को 10% की छूट

मोड : पेन ड्राइव

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS की प्लेलिस्ट Online Courses में देखें (डेमो वीडियोज़ 6 जनवरी से उपलब्ध)	ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com पर FAQs पेज देखें

हिंदी साहित्य : पेन ड्राइव कोर्स

1. UPSC के पाठ्यक्रम के लिए 400+ घंटे की कक्षाएँ।
2. UPPCS एवं BPSC के विशिष्ट टॉपिक्स के लिये 30-30 घंटे की पृथक कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा, ताकि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवीज़न भी कर सकें।
4. हर क्लास में उस टॉपिक से IAS, PCS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का विस्तृत अभ्यास।
5. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी, जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
6. पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक्स व नोट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल, जिनके अलावा किसी अन्य अध्ययन सामग्री की आवश्यकता नहीं।

जानकारी के लिये कॉल करें- 9319290700, 9319290701, 9319290702 या सिर्फ मिस्ड कॉल करें- 8010600300

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) : 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) : ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 8750187501

कहाँ क्या है?

संपादक की कलम से... 5

क्योंकि ज़रूरत से कम या ज़्यादा आत्मविश्वास घातक होता है....

टॉपर से बातचीत 7

श्रीकांत कोराम

CGPSC-2018 परीक्षा में द्वितीय रैंक पर चयनित (7)

इंटरव्यू की तैयारी: क्या हो सही रणनीति? (भाग-I) 10

लेख खंड 15

राजनीतिक लेख

- *चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ : समग्र विश्लेषण (16)*

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय लेख

- *वर्चुअल तथा ऑग्मेंटेड रियलिटी (19)*

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित लेख

- *क्या दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध की ओर अग्रसर है? (23)*

एथिक्स संबंधी लेख

- *महात्मा बुद्ध के नैतिक विचार (27)*

ऑडियो लेख

- *इसरो का सफर (31)*

करेंट अफेयर्स 33

- *अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम (33)*
- *संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम (37)*
- *आर्थिक घटनाक्रम (43)*
- *संघीय बजट 2020-21 (48)*
- *अंतर्राष्ट्रीय संबंध (55)*
- *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (63)*
- *पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (68)*
- *भूगोल एवं आपदा प्रबंधन (73)*
- *सामाजिक मुद्दे (77)*
- *कला एवं संस्कृति (83)*
- *आंतरिक सुरक्षा (85)*
- *संक्षिप्तियाँ (88)*

जिस्ट 97

उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं के लेखों का सार

- *संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार (98)*
- *संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार (106)*
- *राजव्यवस्था एवं समाज (114)*
- *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (117)*
- *पर्यावरण (120)*
- *अंतर्राष्ट्रीय संबंध (124)*
- *एथिक्स (126)*

फैक्टशीट 127

- *महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित (127)*

निबंध खंड 132

- *निबंध प्रतियोगिता (132)*

करेंट अफेयर्स से जुड़े संभावित प्रश्न-उत्तर 133

- *मुख्य परीक्षा के लिये संभावित प्रश्न (133)*

माइंड मैप 139

- *भारतीय चित्रकला-1 (139)*
- *भारतीय चित्रकला-2 (140)*

करेंट अफेयर्स पर आधारित प्रिलिम्स अभ्यास प्रश्न 141

मानचित्रों से सीखें 144

मानचित्र-1 (144)

मानचित्र-2 (145)

टारगेट प्रिलिम्स 2020: चौथी कड़ी 147

- *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (147)*

आपके पत्र 208

मार्च 2020 ■ मासिक ■ वर्ष-5 ■ अंक-9 ■ कुल अंक-57

टीम दृष्टि

- **प्रधान संपादक:** *डॉ. विकास दिव्यकीर्ति*
- **डायरेक्टर:** *डॉ. तरुणा वर्मा*
- **कार्यकारी संपादक:** *पुरुषोत्तम 'प्रतीक'*
- **वरिष्ठ संपादक:** *आलोक कुमार अग्रवाल, शशि भूषण तिवारी, निधि सिंह।*
- **समाचार संपादक:** *हरि किशोर यादव, गायत्री, शिवानी सिंह, कवीन्द्र कुमार यादव।*
- **प्रबंधन परामर्श:** *अजय कड़ाकोटी, मो. आफताब आलम, अभिषेक सिंह, विवेक तिवारी, अमृत उपाध्याय, एकता कालिया, मो. साजिद सैफी, अजय शर्मा, चंद्रप्रकाश राय, अमित कुमार श्रीवास्तव, नेहा चौधरी, जितेन्द्र रोहिला, आनंद शुक्ला, दिलीप कुमार, राजू प्रसाद, गोपाल राय।*
- **संपादन सहयोग:** *मुकुल आनंद, सुशांत कुमार, सुरेश पाल सिंह, सूर्य कुमार द्विवेदी, जगदीश पांडेय, पीयूष कांत गांगुली, पुष्पा कुमारी, प्रवेश चौधरी, कृष्ण कुमार सिंह, नीरज कुमार, विवेक सिंह, दीपक तिवारी, आभा प्रजापति, रोहित नंदन मिश्रा, देवेन्द्र कुमार, अमरजीत पासवान, रविकांत, राकेश राजपूत, श्रवण कुमार सुमन, संत विजय, महिमा राजपूत, रेखा, रीना कुमारी, अवनिन्द्र जयसवाल, एजाज़ अनवर, सूर्य प्रकाश, राहुल कश्यप, सिद्धार्थ कुशवाहा, रवि गोले, मनीषा यादव, पंकज तिवारी, निखिल चौहान, कुमार रविशंकर, यशोधरा, स्मिता वर्मा, रामहंस यादव, राहुल गिरी, राम राठी प्रसाद, प्रदीप मौर्या, मो. फैजुल इसलाम, रामबाबू यादव, अजीत कुमार सिंह, प्रियेष कुमार, नीरज कुंदन, विकास कुमार, दीपाली तायडे, रमंत झंड, वशिष्ट नारायण, कृष्ण कुमार साह, विवेक कुमार सिन्हा, निशां शर्मा, प्रियंका सिंह, जितेन्द्र कुमार, रेखा वर्मा, अंकित रावत, श्रद्धा भदौरिया, मो. रिज़वान, खुशबू, संजूर आलम, अर्चना शर्मा, जितेन्द्र, हेमंत गुलपाडिया, धीरेन्द्र कुमार बागरी, अंकित त्यागी, चित्राँशु पांडेय, अजीत कुमार पटेल, अंकुर कुमार, हिमाँशु सिंह, करिश्मा, मनीषा, बबीता, खुशहाल, केवल कृष्ण पांडेय, आशुतोष सिंह, लोकेश कुमार, सलमान अहमद, हरीश कुमार, आभा कुमारी, ज्योति, किशोर कुमार झा, विकास कुमार, निशा शाहीन, शिल्पी सरकार, ऋतुराज कुमार, दिनेश, नेहा कुमारी, अमित कुमार, नेहा लक्ष्यकर, वर्षा तारण्या, उद्याभान सिंह, प्रीति झा, अमित कुमार, विवेक दिवाकर, आशुतोष कुमार यादव, राजेश कुमार, हिमिका, पिंकी कुमारी, निर्मल कुमार राजू, राम प्रवेश यादव, शशाँक श्रीवास्तव, कविता, आँचल वसनीक, आरती सिरोही, राहुल कुमार, सौरभ कुमार गोयल, योगेश कुमार सिंह, आतिफा काजी, राजेश्वर प्रसाद पटेल, मनीष कुशवाहा, विकास तिवारी, अतुल, जंग बहादुर यादव, दीपिका, पूजा उपाध्याय, दीपिका परिहार नेगी, राजदीप चौहान, मनीष कुमार सिंह, प्रेम चंद्र, रोहित सिंह, रोहित कुमार पाठक, मनराज गुर्जर, अक्षय शुक्ला, साधना सनौडिया, विपिन कुमार यादव, मो. रकीब, मधुबाला, जितेन्द्र कुमार राय, नम्रता सिंह, हिमांशु शर्मा, अनुराग सिंह, अखिलेश कुमार पांडेय, सिद्धांत शुक्ला, साहिल कुमार चौहान, अमित सिंह, अल्का दरिया, रोशनी, दिपेश कुमार, आनंद प्रकाश पांडेय, पंकज कुमार वर्मा, जितेन्द्र चौहान, मीत वर्मा, हर्षवर्धन, भावेश द्विवेदी, सिद्धार्थ पटले, अंकित कुमार, कपिल वर्मा, दीपिका जिंदल, कृष्णकांत चौरसिया, पिंकी शर्मा, हरिओम चिहार, गुलअफ़शाँ, जितेन्द्र कुमार पटेल कलाल, प्रियंका, सोनम साहू, राजीवेश कुमार, विश्वनाथ प्रताप सिंह, सुशील कुमार, राजेश कुमार, पीयूष कुमार, शशाँक चौबे, शुभम शुक्ला।*
- **टाइपसेटिंग और डिज़ाइनिंग सहयोग:** *लोकेश पाल, जीतेश, अनिल कुमार, विवेक कुमार पाल, पूनम सक्सेना, करुणा अग्रवाल, मेधा, संजू वर्मा, राजो कामती, चेतन कुमार, अमित कुमार बंसल, अखिलेश कुमार, समरजीत सिंह, अजय गुरंग, संदीप कुमार, तारा कुमारी, सुदीप पाल, लोकेश कुमार, पुनीत मंडल, अनुज कुमार, भुपेंद्र पाल सिंह, आसीन, करण भारद्वाज।*
- **वेब सहयोग:** *अविनाश कुमार, अनु राज, रवि शंकर, विनय प्रकाश श्रीवास्तव, प्रीति अहूजा, सुनील कुमार यादव, प्रतिभा राय, जया जोशी, शिप्रा, रिमझिम, ब्रिजेश कुमार यादव, जसवंत सिंह रावत, सोनाली चौपड़ा, पायल, प्रिया, सरोज शर्मा।*
- **प्रबंधन सहयोग (वरिष्ठ):** *राजेश धस्माना, राजेश कुमार झा, श्रीकांत कुकरेती।*
- **प्रबंधन सहयोग:** *मोहित वालिया, नितेश कुमार झा, मोहित मिश्रा, राकेश सिंह चौहान, कुंदन कुमार, शिव कुमार, वेद प्रकाश, मुकेश कुमार पाठक, असीम करन, अंशुल तिवारी, सुनील शेलके, संजीत कुमार, विपिन गुप्ता, मनीष जैन, संदेश कुमार डोगरा, मनवीर नेगी, शुभम वर्मा, गीता पाल, प्रीति चौधरी, नीतिका शर्मा, राकेश ठाकुर, अनिता जसवाल, गीता शर्मा, किरण मल्होत्रा, नीरज शर्मा, अभिषेक शुक्ला, नितिन बोबल, तब्बसुम मलिक, इरफान खान, श्वेता, रविशंकर, रहमत, अंजलि मिश्रा, अनुराग मिश्रा, यश कुमार मौर्य, सौरभ कुमार, रचना दूबे, रंजीत कुमार कुशवाहा, अर्पित सोनी, सौरभ कुमार, गौरव मिश्रा, रजनीश कुमार त्रिपाठी, सबिता गिरी, कृष्ण कुमार, सौरभ अहिरवार, रवि कुमार, राजेश जॉन, अंकुर कुमार, पूजा द्विवेदी, आशीष गुप्ता दीक्षा केशरवानी, मो. आसीम, सिद्धार्थ तिजौरिया, मोहित कुमार पांडेय।*
- **मीडिया सहयोग:** *राजकुमार कोले, अर्जुन नेगी, सुभाष पाटिल, श्रवण कुमार, संदीप रावल, अतुल सिंह, तरुण ग्रोवर, सुभाष चंद्र, लक्ष्मण कुमार, धीरज कौशिक, क्षितिज साहनी, अनिल स्टिफन, अखिल कुमार, निपेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह, मनोज कुमार (1), मनोज कुमार (2), राहुल अग्रवाल, लवनीत सिंह, गणेश हरिभाऊ अधाने, अनिल कुमार पटेल, विष्णु कांत दुबे, रोहित कुमार, कमलेश कुमार, पवन दुआ, मनदीप रावत, दुर्गश कुमार सिंह, नंद किशोर, कमलेश कुमार कमल, सुनील कुमार सिंह, राम नायक तिवारी, रोहित कुमार, रवीन कुमार जी, शिवकांत शुक्ला।*
- **दैनंदिन सहयोग:** *गजेन्द्र, रवि कुमार, भावेश गिरी, महेश कुमार, दिलीप तिवारी, अमित कुमार, विकेश कुमार, पंचानन मिश्रा, अंकित यादव, पुनीत कांगड़ा, राहुल कुमार, मनोज कुमार, अविनीश श्रीवास्तव, सलमान, मो. शकील, सुरेन्द्र रॉय, अमित कुमार रोहिला, दीपक पाल, ऋषभ कुमार, साहिल, सुभाष कुमार, राम सूरत यादव, राजू शर्मा, मनीष कुमार, दीपक कामती, ज्ञान प्रकाश मौर्या, प्रवीण, सूरज प्रकाश, अजीत कुमार, बलवंत सिंह, विश्वेंदर चौधरी, इम्तियाज़ अंसारी, मनोज सिंह, मन्नु कुमार, मुन्ना, सतीश, वकील, दिनेश कुमार मिश्रा, सुजीत यादव, विनय कुमार, कैलाश मल्होत्रा, नरेश राय, संतोष कुमार कामत, मनु चौधरी, श्रवण कुमार, सुमित कुमार, अभिषेक, सुजीत कश्यप, तरुण, नरेंद्र कुमार, हरे राम, अतुल शर्मा, नेत्रपाल, राजेश कुमार, नीशु रोहिला, शिव शंकर पटेल, मो. अरमान, आशु मिश्रा, सोचिन कुमार यादव, राजेश कुमार, अमित कुमार रे, सौरभ कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार, जशवंत सिंह भकुनी, बेचन चौधरी, पंकज कुमार शर्मा, गौरव कुमार, उमेश, जितेन्द्र कुमार, विपिन कुमार, हिमांशु कुशवाह, ऋषिकेश तोमर, सुनील कुमार शुक्ला, लाल बाबू यादव, मोनू (1), सचिन कुमार, पप्पू कुमार, प्रियांशु, ममता, सचिन लाहुडकर, भीकू, गौतम कुमार, अवधेश कुमार, अमन कुमार, तुलसी कुमार, योगेन्द्र सिंह, मो. अख्तर, हरीनाथ, आशीष, रोहित कुमार, निक्की कुमार, मुकेश कुमार, राजेश कुमार यादव, राम आशीष मिश्रा, सद्दाम हुस्सैन, पप्पू चौधरी, अतुल कुमार, देवेन्द्र सिंह गौर, रंजीत, सचिन कुमार, चंद्र भान, सचिन, गोपाल कुमार, दिगम्बर कुमार पासवान, भावेश कुमार, पवन कुमार साहू, संजय कुमार, बोआ झा, राजबीर, रविन्द्र कुमार, विक्रांत सिंह, परवेज़, किशन कनौजिया, सुरेश चंद्रा, रामकिशन बिंशकर, अंकित मिश्रा, कौशल शर्मा, नीरज कुमार, लीलावती, श्याम कुमार सौराष्ट्रिया, जितेन्द्र कुमार, उमाकांत शर्मा, धर्मेन्द्र कुमार, दिलीप, उदय पासवान, अमरजीत कुमार, मनीष, आकाश चौहान, अनिकेत कुमार साह, पुनीत कुमार मिश्रा, विनय पांडेय, विजय, छाया देवी नरेंद्र, अरविंद द्विवेदी, प्रकाश सिंह, अभिषेक कुमार, अर्जुन, अनिल कुमार, नगेंद्र, पवन कुमार मोदी, योगेश सिंह, सुरेन्द्र, रवि, अंकित, दिलीप चौधरी, ललित मोहन उपाध्याय, मोहित कुमार तिवारी, प्रिंस कुमार, रोहित, अभिषेक, अंकुश, शिवम, मनीष कुमार, अभिमन्यु कुमार, संदीप, संजय कुमार शर्मा, अभिषेक कौशल, कुमार पाल, विष्णु कांत मिश्रा, मनोज कुमार, सूरज कुमार, पवन कुमार, राहुल, सुनील कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, निहाल तिवारी, अंकित कुमार, विनय, सनोज पासवान, अरविंद, अवनीश कुमार, संजीव, विवेक कुमार, नीतू चौहान, सोनू मोहित, शिव बहादुर, सुनील, नवीन कुमार मिश्रा, आदर्श प्रजापति, ब्रिजेश कुमार, धर्मराज सिंह, गौतम राज सिंह, श्याम कुमार वर्मा, अतुल, जय प्रकाश मौर्य।*

संपादकीय पत्र व्यवहार

कार्यकारी संपादक,
दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे,
दृष्टि पब्लिकेशन्स,
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि संपादक या प्रकाशक का दृष्टिकोण भी वही हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लेखकों के लेख शामिल करें ताकि पाठकों को किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिल सकें।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पत्रिका में छपे लेख लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखे गए हैं। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो लेखक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © **कॉपीराइट:** दृष्टि पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पत्रिका की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों व सुझावों तथा वितरण और विज्ञापन के लिये संपर्क (Whatsapp) करें-
अजय कड़ाकोटी (सी.एफ.ओ.)
(8130392355)

पत्रिका के सब्सक्रिप्शन के लिये संपर्क करें-
9599084248

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक
विकास दिव्यकीर्ति द्वारा 641,
प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009 से
प्रकाशित एवं एम.पी. प्रिंटर्स,
बी-220, फेज़-2, नोएडा
(उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।
संपादक- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

संपादक की कलम से...

क्योंकि ज़रूरत से कम या ज़्यादा आत्मविश्वास घातक होता है....

आपने देखा होगा कि कुछ लोग कोई भी काम पूरे आत्मविश्वास से करते हैं। आप उन्हें कोई भी चुनौती देंगे तो वे खुश होकर उसे स्वीकार करेंगे। कठिन-से-कठिन परिस्थिति में भी उन्हें घबराहट नहीं होती। ऐसे लोगों की पूरे ज़माने पर धाक होती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया का इतिहास और कुछ नहीं है, वह सिर्फ उन मुट्ठी भर लोगों की कहानी है जिन्हें खुद पर यकीन था। दूसरी तरफ, आपका सामना ऐसे लोगों से भी पड़ा होगा जो हमेशा आत्मविश्वास के अभाव से जूझते नज़र आते हैं। वे चाहते हैं कि वे हमेशा बने-बनाए रास्तों पर चलते रहें और उनके जीवन में किसी भी तरह के जोखिम का स्थान न हो। ऐसे लोगों के नाम इतिहास में दर्ज नहीं होते। कोई नहीं चाहता कि उसका व्यक्तित्व इसी तरह का आत्मविश्वास-रहित व्यक्तित्व हो।

दरअसल आत्मविश्वास का संबंध 'स्व' या 'Self' की अवधारणा से है। 'सेल्फ' की धारणा मनोविज्ञान का एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग है जिसका सरल अर्थ है कि व्यक्ति की स्वयं अपने बारे में क्या राय है? सीधा-सा नियम है कि अगर व्यक्ति की अपने बारे में राय अत्यंत सकारात्मक होगी तो वह आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा और अगर खुद उसकी राय अपने बारे में सकारात्मक नहीं होगी तो वह आत्मविश्वास की कमी से जूझेगा। इसलिये किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास के स्तर को समझना हो तो उसके 'सेल्फ कंसेप्ट' या 'सेल्फ इमेज' को समझने की कोशिश करनी चाहिये।

ज़्यादा महत्त्वपूर्ण सवाल यही है कि व्यक्ति की 'सेल्फ' की धारणा कैसे बनती है? इस संबंध में एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री चार्ल्स हटन कूले का एक अत्यंत रोचक कथन है- *"मैं वह नहीं हूँ जो मैं समझता हूँ कि मैं हूँ; मैं वह भी नहीं हूँ जो तुम समझते हो कि मैं हूँ; मैं वह हूँ जो मैं समझता हूँ कि तुम समझते हो कि मैं हूँ।" (I am not what I think I am; I am not what you think I am; I am what I think you think I am)*। इस भूल-भुलैया जैसे कथन का सरल अर्थ यह है कि मेरी अपने बारे में छवि या धारणा इस बात से तय नहीं होती कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। वह इस बात से भी तय नहीं होती कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्योंकि मैं वस्तुनिष्ठ रूप से यह जान ही नहीं सकता कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है। अपनी नज़र में मेरी छवि इस आधार पर बनती है कि मुझे दूसरों की निगाह में अपने प्रति कैसा भाव नज़र आता है? अगर मुझे लगता है कि अधिकांश लोग मेरा सम्मान करते हैं तो मेरी नज़रों में भी मेरा सम्मान बढ़ जाएगा और यदि मुझे लगा कि अधिकांश लोग मुझे महत्त्व नहीं देते हैं तो धीरे-धीरे मैं भी खुद को महत्त्वहीन समझने लगूंगा और अल्प-आत्मविश्वास का शिकार हो जाऊंगा।

यहाँ दो और अवधारणाओं को समझने की ज़रूरत है जिन्हें 'सिग्निफिकेंट अदर्स' तथा 'जनरलाइज़्ड अदर्स' कहते हैं। इनसे पता चलता है कि व्यक्ति की 'सेल्फ इमेज' बनाने में किसी व्यक्ति का कितना योगदान होता है। गौरतलब है कि किसी भी व्यक्ति की निगाह में सभी संबंधित व्यक्तियों का बराबर महत्त्व नहीं होता। कुछ लोग उसके लिये बेहद खास होते हैं जिनकी नज़रों में गिरना वह बर्दाश्त नहीं कर सकता; जिनकी नज़रों में उठने के लिये वह एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाने को तैयार रहता है। इन व्यक्तियों को 'सिग्निफिकेंट अदर्स' कहा जाता है। दूसरी ओर, तमाम ऐसे लोग भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं जिनकी राय हमारे लिये महत्त्व नहीं रखती। हमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वे हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा। इन व्यक्तियों को 'जनरलाइज़्ड अदर्स' कहते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि व्यक्ति के आत्मविश्वास का स्तर मोटे तौर पर इस बात से तय होता है कि 'सिग्निफिकेंट अदर्स' की उसके बारे में क्या धारणा है?

हमें दो प्रयास निरंतर करने चाहियें- पहला तो यह कि हम अपनी 'सेल्फ इमेज' को न बिगड़ने दें ताकि अति-आत्मविश्वास या अल्प-आत्मविश्वास हम पर हावी न हो; और दूसरा यह कि जब कभी विकृत 'सेल्फ इमेज' से जूझ रहे व्यक्ति को देखें तो अपने स्तर पर थोड़ी-बहुत ऐसी कोशिश ज़रूर करें जिससे वह विकृति समाप्त या कम हो जाए। अल्प-आत्मविश्वास से जूझ रहे व्यक्ति की बार-बार प्रशंसा करें ताकि आपकी आँखों में अपना सम्मान देखकर उसे खुद पर भरोसा जमने लगे; और अति-आत्मविश्वास से युक्त व्यक्ति को चोट पहुँचाए बिना थोड़ा-बहुत उन चुनौतियों का अहसास कराएँ जिनसे अभी तक उसका सामना नहीं हुआ है और इसी वजह से वह हवा में उड़ रहा है।

अपने आत्मविश्वास को सही स्तर पर बनाए रखना भी ज़रूरी है क्योंकि बिना आत्मविश्वास के कोई बड़ा काम संभव नहीं है। बस यह ध्यान रहे कि आत्मविश्वास ज़रूरत से ज़्यादा न हो। इसका उपाय यह है कि कभी-कभी अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से मिलते रहें, कुछ महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ते रहें ताकि उनकी महानता की तुलना में अपनी लघुता का अहसास बना रहे। कभी-कभी अपने से कमतर व्यक्तियों के साथ भी तुलना करते रहना चाहिये (उन्हें बताए बिना) ताकि अपनी क्षमताओं पर भरोसा भी बना रहे। एक अच्छा उपाय यह भी है कि व्यक्ति ईमानदारी से अपनी डायरी लिखे जिसमें वह सहज होकर खुद से बात कर सके- अपनी कमज़ोरियाँ भी स्वीकार कर सके और अपनी उपलब्धियों पर इतरा भी सके।

एक छोटी-सी पर महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास सभी क्षेत्रों में बराबर विभाजित नहीं होता। बहुत संभव है कि छोटे समूह में अपनी धाक जमाने वाला व्यक्ति बड़े समूह के सामने घबराहट का शिकार हो जाए या किसी खेल का चैम्पियन मानवीय संबंधों की दुनिया समझने के मामले में धूल चाटने लगे। किसी को किसी खास विषय पर आत्मविश्वास से भरा देखकर डरना नहीं चाहिये क्योंकि हो सकता है कि जिस क्षेत्र में आपके पास आत्मविश्वास है, उस क्षेत्र में वह आपके सामने पिद्दी साबित हो।

शुभकामनाओं सहित,

(डॉ विकास दिव्यकीर्ति)

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

Quick Book शृंखला की पुस्तकें

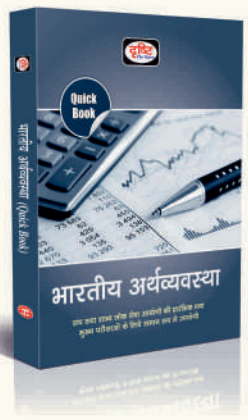

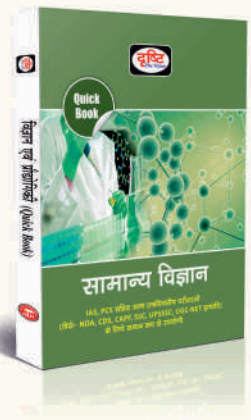

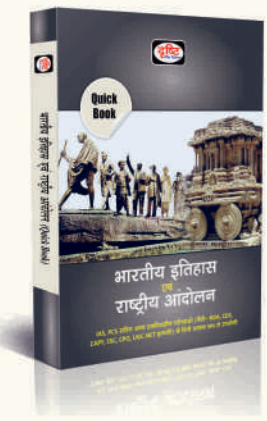

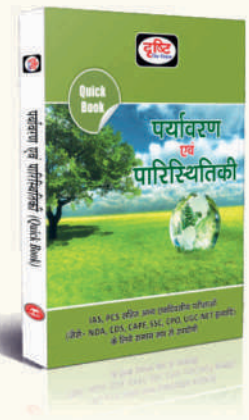

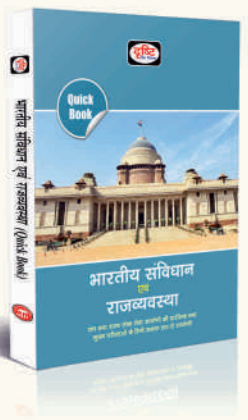

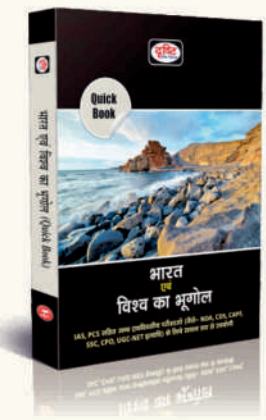

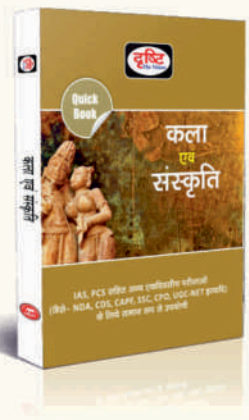

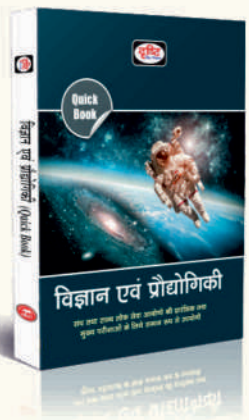

NCERT शृंखला की पुस्तकें

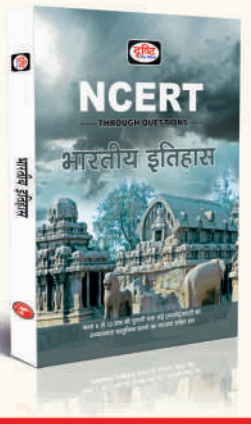

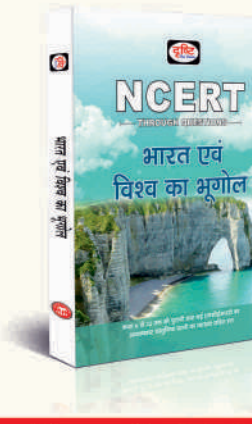

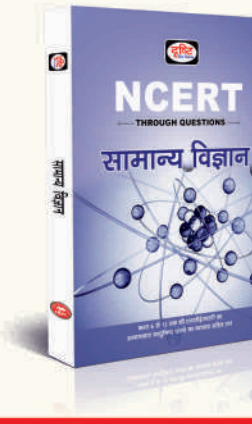

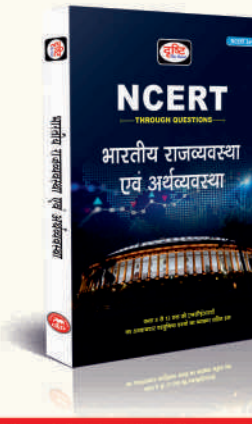

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485516, 87501-87501, 011-47532596

टॉपर से बातचीत

श्रीकांत कोराम

CGPSC-2018 परीक्षा में द्वितीय रैंक पर चयनित

टॉपर का परिचय

नाम: श्रीकांत कोराम
पिता का नाम: स्व. श्री सुकमन सिंह कोराम
माता का नाम: स्व. श्रीमती मनोरमा कोराम
जन्मतिथि: 15 फरवरी, 1993
शैक्षिक योग्यताएँ: Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
आदर्श व्यक्तित्व: मेरे बाबूजी और माँ
व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष: धैर्य, निरंतरता, दृढ़ निश्चयी
व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्ष: भावुकता
रुचियाँ: बस्तरी व्यंजन पकाना

परिणाम से संबंधित कुछ जानकारियाँ

परीक्षा का नाम: CGPSC-2018
अनुक्रमांक: 1807148653
रैंक: 2nd
परीक्षा का माध्यम: English
प्रयास संख्या: तीसरा
मुख्य परीक्षा में कुल अंक: 860.5
इंटरव्यू: 72
कुल अंक: 932.5

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे: सिविल सेवा परीक्षा में उच्च रैंक पर चयनित होने पर आपको 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की ओर से हार्दिक बधाई। चयनित होकर आपको कैसा लग रहा है?

श्रीकांत कोराम: धन्यवाद! मुझे बहुत खुशी हो रही है।

दृष्टि: क्या इस परीक्षा में सफल होना ही आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था? यदि नहीं, तो आगे आपकी निगाह किन उद्देश्यों पर लगी है?

श्रीकांत: इस परीक्षा में सफल होना जीवन का एक लक्ष्य अवश्य था, परंतु सर्वोच्च लक्ष्य नहीं। आगे मैं समाज की सेवा अच्छे से करना चाहता हूँ और निरंतर अपने कार्य को करके संतुष्ट होना चाहता हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने काम और कर्त्तव्य से समझौता किये बिना UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ।

दृष्टि: सिविल सेवाओं में ऐसा क्या है कि लाखों युवा इनकी ओर आकर्षित होते हैं? आपके लिये इन सेवाओं में जाने का क्या आकर्षण था?

श्रीकांत: सिविल सेवाओं की सबसे बड़ी विशेषता उनकी व्यापकता है। सिविल सेवाओं में नई चुनौतियाँ हैं। लोगों से जुड़ने का मौका है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है। और इन्हीं बातों की वजह से युवा इनकी ओर आकर्षित होते हैं। मैं अपने समाज और देश के लिये कुछ करना चाहता था और इन सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठा, सम्मान और संसाधन की वजह से इनकी ओर आकर्षित हुआ।

दृष्टि: अक्सर कहा जाता है कि एक-डेढ़ वर्ष तक कठोर मेहनत करने के बाद भी इस परीक्षा की तैयारी संतोषजनक तरीके से पूरी नहीं हो पाती। क्या यह सच है? क्या आप अपनी तैयारी से संतुष्ट थे एवं सफलता के प्रति आशावान थे?

श्रीकांत: जी नहीं। अगर कोई एक-डेढ़ वर्ष तक इसकी तैयारी अच्छे से करे तो निश्चित रूप से सफलता हासिल की जा सकती है।

दृष्टि: यूँ तो कोई भी सफलता कई कारकों पर निर्भर होती है, पर हर सफल व्यक्ति के पास कुछ विशेष सूत्र होते हैं। आपकी सफलता के मूल में कौन-से सूत्र रहे?

श्रीकांत: मेरी सफलता के मूल में निरंतरता, धैर्य और दृढ़ निश्चय प्रमुख सूत्र रहे।

दृष्टि: आपकी सफलता में निस्संदेह आपके साथ-साथ कुछ अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं का भी योगदान रहा होगा। अपनी योग्यता और परिश्रम के अलावा आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे?

श्रीकांत: मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे गुरुजन, मेरे परिवार, मेरे मित्र, दिल्ली IAS अकादमी, बिलासपुर, सौरभ चतुर्वेदी सर और अपने भाई को देना चाहूंगा।

दृष्टि: प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए इसकी तैयारी के लिये आपने क्या रणनीति अपनाई? कुछ विशेष खंडों पर अधिक बल दिया या सभी पर समान बल? आपकी राय में क्या कुछ खंडों को गौण मानकर छोड़ा जा सकता है?

श्रीकांत: प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखते हुए दोनों की तैयारी एक साथ की जानी चाहिये। मैंने अपनी तैयारी के दौरान अधिक-से-अधिक प्रश्नों का अभ्यास किया तथा अपनी कमियों को दूर किया।

दृष्टि: आपने निबंध की तैयारी कैसे की? परीक्षा भवन में विषय के चयन तथा समय-प्रबंधन को लेकर आपने क्या रणनीति अपनाई? क्या भूमिका और निष्कर्ष लेखन के लिये कोई विशेष रणनीति अपनाई या सामान्य तरीके से ही लिखा?

इंटरव्यू की तैयारी

क्या हो सही रणनीति? (भाग-1)

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

(प्रिय विद्यार्थियो, इस अंक से हम इंटरव्यू की तैयारी से जुड़े इस विशेष कॉलम की शुरुआत कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसके विभिन्न खंडों को आपस में जोड़कर पढ़ें, समझें और जहाँ तक संभव हो, रोज़मर्रा के अभ्यास में उतारने की गंभीर कोशिश करें।)

'इंटरव्यू' शब्द सुनकर कई बार बड़े-बड़े दिग्गज भी घबराहट के शिकार हो जाते हैं। दरअसल यह परीक्षा अपनी प्रकृति में ही ऐसी है कि उम्मीदवार का बेचैन होना स्वाभाविक है। इसमें न तो प्रारंभिक परीक्षा की तरह सही उत्तर के लिये विकल्प दिये जाते हैं और न ही मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्नपत्रों की तरह अपनी सुविधा से प्रश्नों के चयन की सुविधा होती है। हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है और हर उत्तर पर आपसे प्रतिप्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। हर गलत या हल्का उत्तर 'नैगेटिव मार्किंग' जैसा नुकसान करता है और इससे भी मुश्किल बात यह कि परीक्षा के पहले दो चरणों के विपरीत इसके लिये कोई निश्चित पाठ्यक्रम भी नहीं है। दुनिया में जो भी प्रश्न सोचा जा सकता है, वह इसके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और इन सबसे बड़ी कठिनाई यह कि लगभग 25–30 वर्ष के एक उम्मीदवार की परीक्षा लेने के लिये ऐसे पाँच लोग सामने बैठे होते हैं जिनमें से प्रत्येक का कार्य-अनुभव उम्मीदवार की कुल आयु से ज़्यादा होता है। ऐसे अनुभवी व्यक्तियों के सामने न तो बात को घुमाना या टालना संभव होता है और न ही झूठ बोलकर बचना। कई स्थितियों में भारतीय सिविल सेवा का इंटरव्यू बहुत हद तक तुक्के वाला मामला बन जाता है। किसी उम्मीदवार को कौन-सा बोर्ड मिला; उस बोर्ड के सदस्यों की रुचि या पकड़ किन क्षेत्रों में है; वे उम्मीदवार की भाषा में सहज हैं या नहीं; उस दिन उनका मूड कैसा है; उनकी राजनीतिक पसंद उम्मीदवार से मिलती-जुलती है या विरोधी है; बोर्ड के सदस्य सामान्यत: अधिक अंक देना पसंद करते हैं या कम- कई बार ऐसे संयोग ही उम्मीदवार के भविष्य का निर्धारण कर देते हैं।

अक्सर ऐसा होता है कि परीक्षार्थी के सामने बोर्ड में विवादास्पद मुद्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जब भी किसी विवादास्पद मुद्दे पर विचार करें तो तटस्थ होकर उसके दोनों पक्षों की गहराई में जाएँ। विचार करते समय अपने हितों और नुकसानों को चेतना पर हावी न होने दें। कागज़ पर वह विषय लिखकर दो हिस्सों में पक्ष और विपक्ष के तर्क व तथ्य नोट करें। ज़्यादा तर्क न सूझें तो इंटरनेट का सहारा लें। दोस्तों से उस मुद्दे पर वाद-विवाद या विमर्श करें। अंत में दो तीन वाक्यों में अपनी राय लिख लें। जब आप यह प्रक्रिया 15–20 बार दोहरा लेंगे तो खुद पाएंगे कि आपका नज़रिया संतुलित और परिपक्व होने लगा है।

सबसे पहले हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य उम्मीदवार से कैसे नज़रिये की उम्मीद करते हैं? इस चर्चा को हम कुछ सामान्य संशयों के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। वे संशय जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को प्राय: परेशान करते हैं, जैसे- क्या हम इंटरव्यू में सरकारी नीतियों का विरोध कर सकते हैं? क्या हम विवादास्पद मुद्दों पर किसी एक तरफ झुक सकते हैं? हमें आदर्शवादी उत्तर देने चाहिये या व्यावहारिक उत्तर? तथा ऐसे ही कुछ और संशय।

प्रमुख संशय

क्या हम सरकारी नीतियों का विरोध कर सकते हैं?

यह प्रश्न इंटरव्यू देने वाले कई उम्मीदवारों को परेशान करता है। मान लीजिये कि किसी सदस्य ने उम्मीदवार से किसी सरकारी नीति के औचित्य पर प्रश्न पूछा है या उस नीति के सही या गलत होने के संबंध में उसकी राय मांगी है। उदाहरण के तौर पर सदस्य का प्रश्न है कि "जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार कई ज़रूरी मुद्दों पर एक के बाद एक विधेयकों को बहुमत के बल पर संसद से व्यापक विचार-विमर्श के बिना पास करा रही है। आपकी राय में सरकार की यह नीति संविधान की मूल भावना के अनुकूल है या उस पर चोट करती है?"

ऐसे प्रश्नों में उम्मीदवारों की दुविधा यह होती है कि उन्हें सरकार के पक्ष में ही दिखना चाहिये या वे सरकारी नीतियों की आलोचना भी कर सकते हैं? उन्हें भय रहता है कि अगर वे सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार उन्हें अपनी सेवा में क्यों शामिल करेगी?

सच यह है कि इंटरव्यू बोर्ड उम्मीदवार से उसकी राय जानना चाहता है, न कि सरकार की राय। वह उससे सरकार का प्रवक्ता होने की अपेक्षा नहीं करता। इसलिये उम्मीदवार को पूरा अधिकार है कि वह स्वतंत्र विवेक से सरकार की नीतियों की समीक्षा करे। हाँ, उसे सरकार का तीव्र या एकतरफा विरोध नहीं करना चाहिये। विरोध में भी संतुलन, मर्यादा और विनम्रता का बने रहना बेहद ज़रूरी है। वह जो भी विरोध करे, उसके पास अपनी बात के पक्ष में ठोस प्रमाण और तर्क होने चाहिये, विरोध हवाई किस्म का नहीं होना चाहिये।

विवादास्पद मुद्दों पर हमारी राय क्या होनी चाहिये?

अब एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। मान लीजिये कि इंटरव्यू बोर्ड एक बेहद विवादास्पद मुद्दे पर उम्मीदवार की राय पूछता है जिस पर किसी

लेख खंड

शोधपरक, सारगर्भित और परीक्षोन्मुखी लेखों का संग्रह

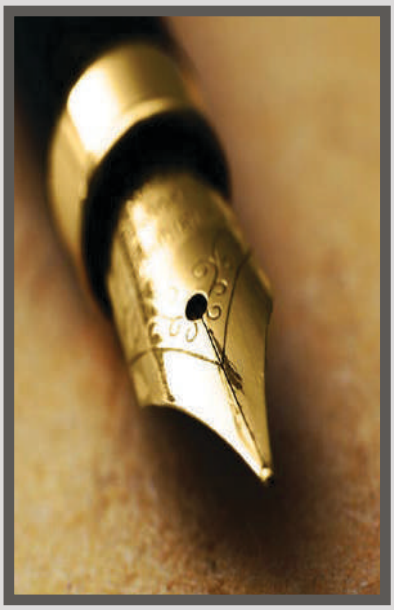

16 राजनीतिक लेख
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ : समग्र विश्लेषण

–अंकित 'ममता' त्यागी

19 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय लेख
- वर्चुअल तथा ऑग्मेंटेड रियलिटी

–निधि सिंह

23 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित लेख
- क्या दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध की ओर अग्रसर है?

–शशि भूषण (विवेक राही)

27 एथिक्स संबंधी लेख
- महात्मा बुद्ध के नैतिक विचार

–डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

31 ऑडियो लेख
- इसरो का सफर

–नम्रता सिंह

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ : समग्र विश्लेषण

अंकित 'ममता' त्यागी

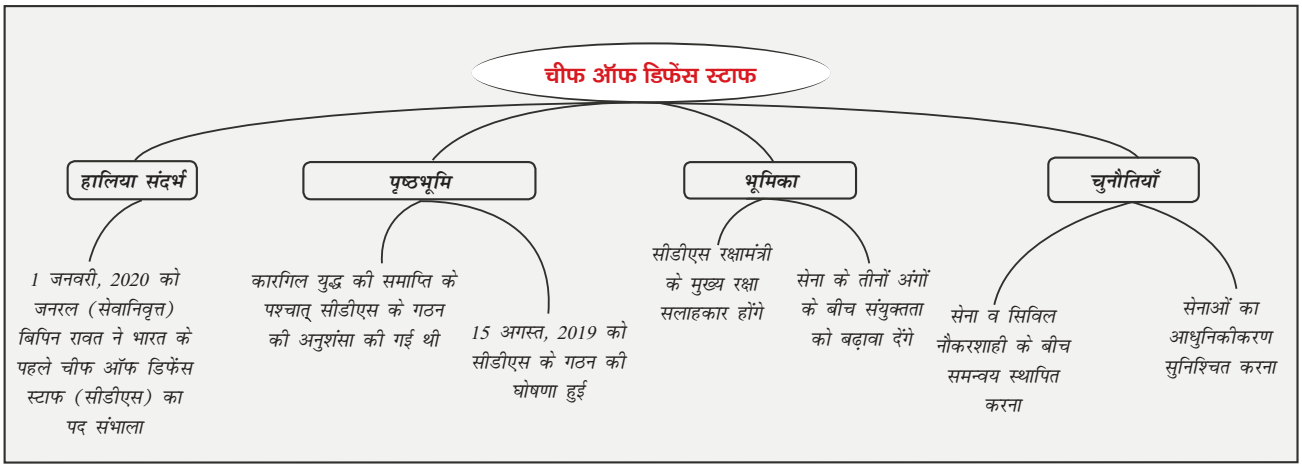

15 अगस्त, 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत कुछ ऐसे हुई, "कई वर्षों पहले हमने नियति के साथ अभिसार (Tryst With Destiny) किया था और अब वह समय आ गया है जब हम अपनी कसम को पूरा करें, पूर्णता में नहीं बल्कि काफी हद तक व आंशिक रूप से।" इसके बाद पहले स्वतंत्रता दिवस से लेकर पिछले महीने के 71वें गणतंत्र दिवस तक भारत कई तरीकों से अपनी कसमें और अपने सपने पूरे करता आया है। चाहे ये सपने या कसमें प्रथमदृष्टया अपनी पूर्णता में पूरे न हों लेकिन शनैः शनैः व आंशिक रूप से हम अपने देश के विकास की नींव को मज़बूत करते जाते हैं। इसी आधार पर हाल ही में देश ने एक और आंशिक ही सही लेकिन मज़बूत कदम बढ़ाया है। 24 दिसंबर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए देश में उच्चस्तरीय रक्षा प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण सुधार करते हुए रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में 4 स्टार जनरल रैंक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित करने की मंजूरी दी। इसके बाद 1 जनवरी, 2020 को थलसेना अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद संभाला। प्रस्तुत लेख में हम नवसृजित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की आवश्यकताओं, संभावनाओं, इस पद के अधिकारों व दायित्वों की विस्तार से चर्चा करते हुए इस पद से संबंधित चिंताओं व चुनौतियों का समग्रता से विश्लेषण करेंगे।

पृष्ठभूमि

भारत में सैन्य बलों के मध्य एकीकरण व समन्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सीडीएस जैसी व्यवस्था हो, यह विषय स्वतंत्रता के पहले और इसके बाद भी विभिन्न समयों पर उठता रहा था। 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल के सैन्य संघर्ष के बाद कारगिल संघर्ष और भारत की सैन्य तैयारी की समीक्षा के उद्देश्य से 'कारगिल समीक्षा समिति (Kargil Review Committee-KRC) का गठन किया गया, इसी समिति ने पहली बार सैन्य बलों के एकीकरण व समन्वयन हेतु गंभीर उपाय सुझाए। सीडीएस जैसी एक व्यवस्था निर्मित करने का पहला औपचारिक प्रस्ताव भी इसी समिति के माध्यम से आया। समिति के द्वारा रक्षा मंत्रालय और सैन्य बलों के मुख्यालयों के बीच उच्चस्तरीय निर्णयन संरचना और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के समूचे परिदृश्य को पुनर्गठित करने की अनुशंसा की गई। हालाँकि समिति ने सीधे सीडीएस की सिफारिश नहीं की थी बल्कि इसने तीन सेवाओं के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो कारगिल संघर्ष के शुरुआती हफ्तों में खराब थी। इसके बाद इस समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों का अध्ययन करने वाले एक मंत्री समूह (GoM) कार्यबल ने यह प्रस्ताव दिया कि एक सीडीएस, जो 5-स्टार अधिकारी होगा, नियुक्त किया जाए। सीडीएस की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए तत्कालीन सरकार ने 2002 के अंत में एकीकृत रक्षा स्टाफ (आईडीएस) बनाया, जिसे अंततः सीडीएस सचिवालय के रूप में काम करना था।

कारगिल समीक्षा समिति रिपोर्ट के एक दशक से भी अधिक समय बाद 2011 में, तत्कालीन सरकार ने रक्षा और सुरक्षा पर नरेश चंद्र समिति की स्थापना की। इस समिति ने सीडीएस के एक नए प्रारूप का सुझाव दिया। इसमें एक चार-स्टार अधिकारी के रूप में चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के अध्यक्ष का ही कार्यकाल दो वर्ष का निश्चित करने का सुझाव दिया (सामान्यतः यह कार्यकाल अध्यक्ष की अपने सैन्य बल के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्ति तक होता था)। साथ ही, यह भी प्रस्ताव दिया गया कि उसके पास चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के अध्यक्ष की तुलना में काफी अधिक शक्तियाँ होंगी। हालाँकि, इस समिति की सिफारिशों पर भी कोई ठोस कार्य नहीं हो पाया क्योंकि 2014 में चुनाव के बाद नई सरकार ने कार्यभार संभाल लिया। इसके बाद मई 2019 में वर्तमान सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के लिये चुनकर आई व 15 अगस्त, 2019 को राष्ट्र के

वर्चुअल तथा ऑग्मेंटेड रियलिटी

निधि सिंह

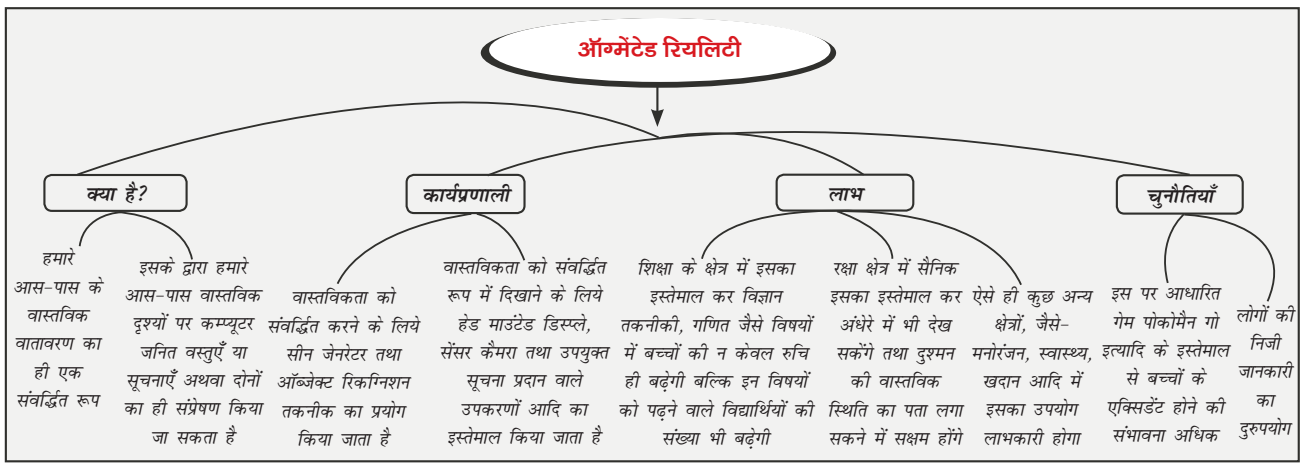

वास्तविक और अवास्तविक पर दार्शनिक बहसें होती रही हैं। दुनिया में क्या वास्तविक है और क्या अवास्तविक, यह प्रश्न जिज्ञासुओं के लिये प्राचीन समय से एक पहेली रहा है। लेकिन जब वास्तविक और अवास्तविक चीज़ों से परिचित होते हुए उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार सटीक अनुपात में प्रयोग कर लिया जा सके तो वाकई यह एक रोमांचक और महत्त्वपूर्ण अनुभव होगा। अगर कम्प्यूटर पर खेले जाने वाले गेम को खेलने के लिये कम्प्यूटर के अवास्तविक कैरेक्टर और खेलने वाले के अलग वास्तविक कैरेक्टर की बजाय हम एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने में सक्षम हों जहाँ इसके लिये अलग से कम्प्यूटर डिस्प्ले की आवश्यकता न हो, बल्कि खेलने वाला स्वयं उस खेल में शामिल हो सके तो यह अनुभव निश्चित ही रोमांचक होगा। सिनेमा देखने वाले और सिनेमा में द्वैत समाप्त हो जाए और यदि देखने वाला भी सिनेमा देखते वक्त स्वयं को उस वातावरण के अंदर महसूस कर सके तो अवश्य ही यह एक अलग अनुभव होगा। तकनीक के द्वारा ऐसा संभव किया जा चुका है, इस वास्तविक और अवास्तविक की दीवार को लगभग समाप्त किया जा चुका है। वास्तविक अनुभव में आभासी अनुभव को मिश्रित करना और आभासी अनुभव को वास्तविक के समान महसूस करना अब संभव है और जिस तकनीक की वजह से यह अनुभव संभव हो सका है, उसका नाम है- वर्चुअल रियलिटी तथा ऑग्मेंटेड रियलिटी। इस लेख में हम इन्हीं तकनीकों के बारे में जानेंगे। हम समझेंगे कि ऑग्मेंटेड तथा वर्चुअल रियलिटी क्या है? दोनों में क्या समानताएँ तथा भिन्नताएँ हैं? इनके तकनीकी पहलू क्या हैं? इस तकनीकी के फायदे और नुकसान क्या हैं? तथा इससे संबंधित चुनौतियाँ क्या होंगी? आदि। सर्वप्रथम हम वर्चुअल रियलिटी को समझते हैं।

वर्चुअल रियलिटी *(Virtual Reality)*

वर्चुअल रियलिटी (VR) से तात्पर्य एक ऐसे वातावरण के निर्माण से है जो अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक प्रतीत हो। इसमें कम्प्यूटर आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर एक आभासी दुनिया का निर्माण किया जाता है। इस आभासी दुनिया को वर्चुअल रियलिटी आधारित उपकरणों के माध्यम से देख, सुन और उसका अनुभव किया जा सकता है।

वर्चुअल रियलिटी में व्यक्ति अपने अनुभवों में वास्तविक दुनिया से अलग एक आभासी दुनिया में प्रवेश करता है जो अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक जैसा महसूस हो। यह आभासी दुनिया प्रयोजन-विशेष के ग्राफिक डिज़ाइनर द्वारा कम्प्यूटर के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की मदद से तैयार की जाती है। इस आभासी दुनिया में उतरने के लिये विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे- हेड माउंटेड डिस्प्ले तथा डाटा ग्लोव आदि। यह आभासी दुनिया जितनी अच्छी डिज़ाइन और उच्चस्तरीय तकनीकों से युक्त होगी अनुभवों की वास्तविकता से समानता उतनी ही अधिक होगी। इस आभासी दुनिया में सभी ज्ञानेन्द्रियों के अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है तथा वातावरण-विशेष के स्पर्श, सुगंध या दुर्गंध, विज़ुअल दृश्य, विशेष साउंड आदि की एक समग्र डिज़ाइनिंग से इसे वास्तविकता के निकट लाया जाता है। इस आभासी दुनिया में प्रवेश का अनुभव जितना अधिक वास्तविकता से निकट होता है, उसके आधार पर इसे विभिन्न स्वरूपों में बाँटा भी जाता है, जैसे- पूर्णरूपेण निमग्न (Fully Immersive), अर्द्ध-निमग्न (Semi-Immersive) तथा अनिमग्न (Non Immersive)। पूर्णरूपेण निमग्न वर्चुअल रियलिटी में इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाता है कि उसमें अधिक-से-अधिक वास्तविकता से निकटता महसूस हो। इसके लिये एक वर्चुअल रियलिटी केव (Cave) में विभिन्न सेंसर्स तथा प्रोजेक्टर्स की मदद से एक वास्तविक लगने वाला वातावरण

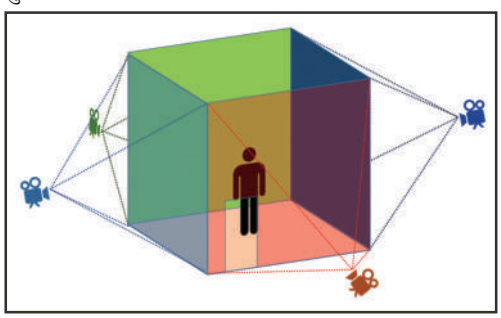

क्या दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध की ओर अग्रसर है?

शशि भूषण (विवेक राही)

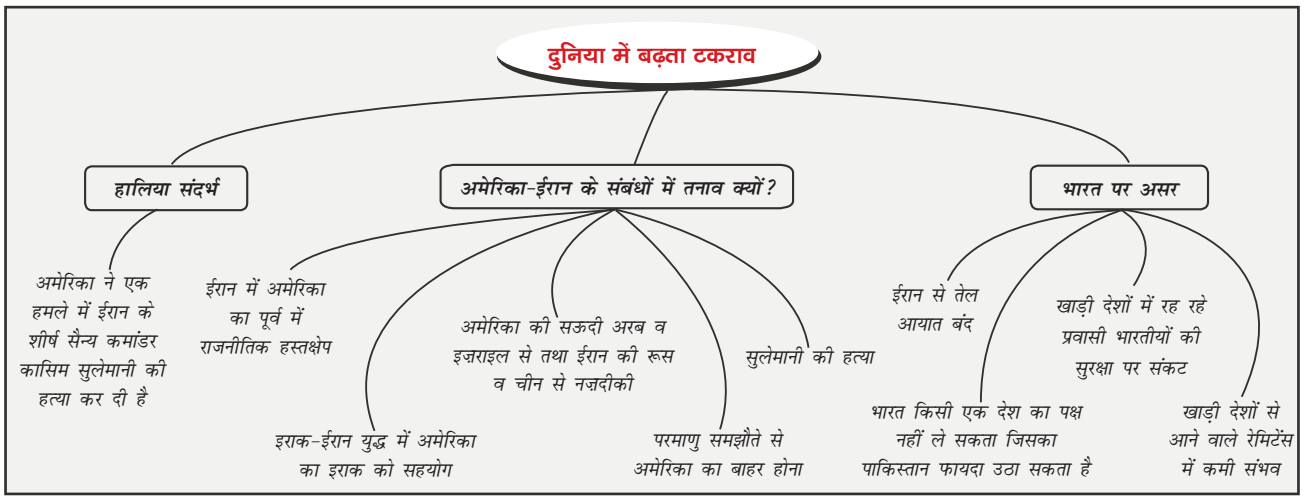

संघर्ष मानव इतिहास का अभिन्न अंग रहा है। धार्मिक, जातीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सुरक्षा आदि कारणों से पनपने वाला संघर्ष क्षेत्रीय व सीमित स्तर पर होता रहा है, तो दुनिया ने यह भी देखा है कि दो बार यह सीमाओं को पार कर विश्वयुद्ध के रूप में भी बदल चुका है। इन कारणों के अतिरिक्त, लगभग सभी संघर्षों में किसी एक या एकाधिक व्यक्तियों से जुड़ा मामला कारणों के केंद्र में रहा है। मसलन, प्रथम विश्वयुद्ध के कारणों के मूल में भले ही साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता, यूरोप के अंदर पनपता उग्र राष्ट्रवाद, गुप्त संधियों का मामला तथा बढ़ता सैन्यीकरण जैसी वजहें थीं, किंतु स्लाव उग्रवादियों द्वारा उनकी मुक्ति में बाधक ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड तथा उसकी पत्नी की हत्या ने युद्ध को अनिवार्य बना दिया। ऐसे ही जर्मन शासक हिटलर की कारगुज़ारियों ने द्वितीय विश्वयुद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। इसी तरह हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिससे संबंधित व्यक्ति मृत्युपरांत भी तीसरे विश्वयुद्ध का कारण बन सकता है। वह व्यक्ति है ईरान का शीर्ष सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी। घटना यह है कि जनवरी 2020 की शुरुआत में ही अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद में एक हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी है। इस घटना के प्रभाव को समझने के लिये पहले हमें अमेरिका-ईरान संबंधों का इतिहास और सुलेमानी की मध्य-पूर्व एशिया में निभाई गई भूमिका को समझना होगा।

अमेरिका-ईरान संबंधों का इतिहास

अमेरिका-ईरान संबंधों में जो तल्खी व्याप्त है उसकी शुरुआत वर्ष 1953 में ही हो गई थी। इस वर्ष अमेरिका ने ब्रिटेन के सहयोग से ईरान के तत्कालीन निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को अपदस्थ करा दिया था। ऐसा करने का मूल कारण 'तेल के खेल' से जुड़ा था। दरअसल द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के उपरांत साम्राज्यवाद के दौर के खात्मे के साथ दुनिया में विकासपरक व औद्योगिक गतिविधियों ने तेज़ रफ्तार पकड़ी। इन गतिविधियों ने ऊर्जा संसाधनों, मुख्यत: क्रूड ऑयल की मांग बढ़ा दी। ऊर्जा संसाधनों की खोज संबंधी नवीन तकनीकियों का विकास हुआ। इन तकनीकों की मदद से पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के भंडार तलाशे गए। ध्यातव्य है, इसके अधिकतर भंडार मुख्यत: मध्य-पूर्व के देशों में पाए गए। इनमें ईरान, इराक और सऊदी अरब मुख्य थे। इन देशों के पास अकूत तेल भंडार था। अमेरिका सहित समूचा पश्चिमी जगत यह समझ रहा था कि तेल अब नया सोना है और सस्ती दर पर तेल की उपलब्धता उनकी अर्थव्यवस्था में तीव्र एवं दीर्घ वृद्धि सुनिश्चित कर सकती है। अत: मुख्यत: अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम के विकसित देशों का मध्य-पूर्व के देशों में हस्तक्षेप बढ़ने लगा। यहीं यह समझ लेना भी ज़रूरी है कि मध्य-पूर्व के देशों में तेल के अकूत भंडारों का पता भले ही लग गया था किंतु इन देशों के पास इसको निकालने की तकनीक नहीं थी, तकनीक पश्चिमी देशों के पास थी, खासकर अमेरिका के पास। ऐसे में पश्चिमी विकसित देशों ने मध्य-पूर्व के देशों के साथ इस रूप में एक कुटिल खेल खेला कि इनकी कंपनियों ने मध्य-पूर्व में रॉयल्टी चुकाने के बदले तेल निकासी संयंत्र स्थापित किये। इन कंपनियों ने बड़ी मात्रा में तेल निकासी की और अपने यहाँ सस्ती कीमत पर तेल आपूर्ति सुनिश्चित की जिससे इनकी अर्थव्यवस्था खूब फली-फूली। किंतु मध्य-पूर्व के देशों को रॉयल्टी की कीमत से बहुत अधिक लाभ होता हुआ नहीं दिखा। साथ ही, उन्हें अपने ऊर्जा भंडार के अतिदोहन से उसकी समाप्ति का खतरा लगने लगा। अत: इन देशों में कंपनियों का विरोध होना शुरू हो गया। इसी विरोध के क्रम में ईरान के धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री माने जाने वाले मोहम्मद मोसादेक अपने देश में तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। उनके इस प्रयास को अमेरिका ने ब्रिटेन के सहयोग से विफल कर दिया और उन्हें अपदस्थ कराकर ईरान में अमेरिका समर्थित राजशाही स्थापित करा दी। यहीं से अमेरिका-ईरान की दुश्मनी शुरू हुई।

महात्मा बुद्ध के नैतिक विचार

-डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

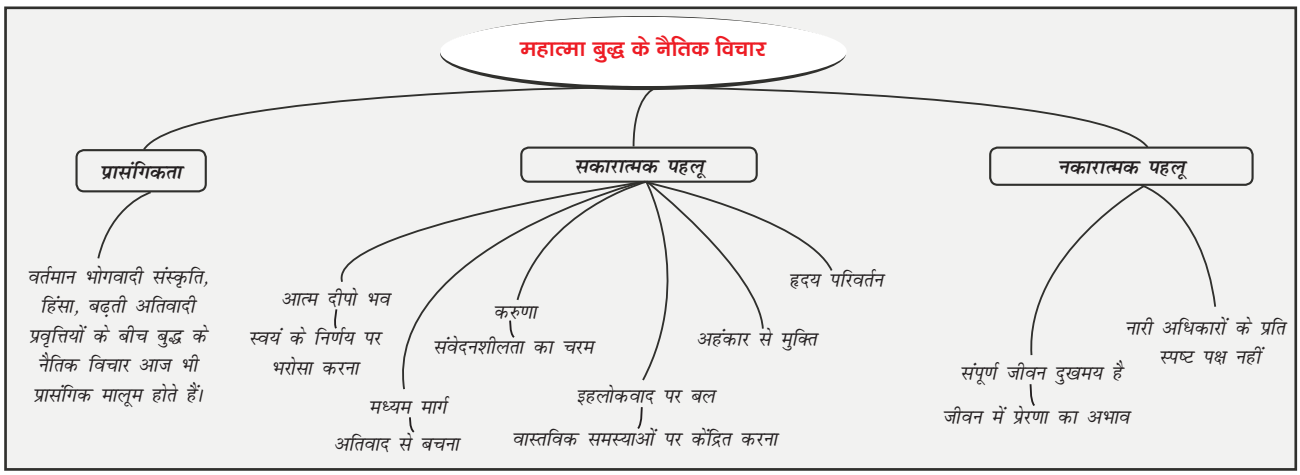

महात्मा बुद्ध भारतीय विरासत की अमूल्य धरोहर हैं। वैदिक परंपरा में धीरे-धीरे जो कुरीतियाँ पनप गई थीं, उन्हें भारत के भीतर पहली ठोस चुनौती महात्मा बुद्ध ने ही दी थी। उन्होंने वैदिक परंपरा के कर्मकांडों पर कड़ी चोट की किंतु वेदों और उपनिषदों में विद्यमान दार्शनिक सूक्ष्मताओं को किसी-न-किसी मात्रा में अपने दर्शन में स्थान दिया और इस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक विरासत को एक बने-बनाए ढर्रे से हटाकर उसमें नवाचार की गुंजाइश पैदा की। मध्यकाल में कबीरदास जैसे क्रांतिकारी विचारक पर महात्मा बुद्ध के विचारों का गहरा प्रभाव दिखता है। आधुनिक काल में डॉ. अंबेडकर ने 1956 में अपनी मृत्यु से कुछ पहले बौद्ध धर्म अपना लिया था और तर्कों के आधार पर स्पष्ट किया था कि क्यों उन्हें महात्मा बुद्ध शेष धर्म-प्रवर्तकों की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक नज़र आते हैं। आधुनिक काल में राहुल सांकृत्यायन और बाबा नागार्जुन जैसे वामपंथी साहित्यकारों ने भी बुद्ध से प्रभावित होकर जीवन का लंबा समय बुद्ध को पढ़ने-समझने में खर्च किया। इन सब बातों से इतना तो तय होता ही है कि बुद्ध अपनी मृत्यु के लगभग 2500 वर्षों बाद आज भी हमारे समाज के लिये प्रासंगिक बने हुए हैं।

यूँ तो बुद्ध के दर्शन में ज्ञानमीमांसा और तत्त्वमीमांसा से जुड़े वे सारे पहलू मौजूद हैं जो किसी व्यवस्थित दर्शन में होते हैं; किंतु अभी हमारा उद्देश्य सिर्फ यह देखना है कि नैतिकता के संबंध में उनके क्या विचार थे। सीधे शब्दों में कहें तो मुद्दा यह है कि हमें बुद्ध से क्या सीखना चाहिये और उनके किन विचारों को तिथिबाह्य या गलत मानकर नज़रअंदाज़ कर देना चाहिये?

बुद्ध नीति के सकारात्मक पहलू

जहाँ तक बुद्ध से कुछ सीखने की बात है, उनका सबसे महत्त्वपूर्ण विचार है- 'आत्म दीपो भव' यानी 'अपने दीपक स्वयं बनो'। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य या किसी नैतिक-अनैतिक प्रश्न का फैसला स्वयं करना चाहिये, किसी दूसरे का मुँह नहीं ताकना चाहिये। यह विचार इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में एक छोटे-से बुद्धिजीवी वर्ग के एकाधिकार को चुनौती देकर हर व्यक्ति को उसमें प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करता है। इस विचार में निहित है कि बुद्ध हर व्यक्ति की क्षमताओं में विश्वास रखते हैं और यही विश्वास तो किसी भी लोकतंत्र के मूल में होता है।

यह विचार आज बेहद प्रासंगिक है। हमारे विद्यालय, जो हर बच्चे को ठोक-पीटकर एक जैसा बना देने के कारखाने बन गए हैं, उन्हें यह समझाना बेहद ज़रूरी है कि हर बच्चे का स्वधर्म या स्वभाव अलग होता है; और उसे खुद ही अपना रास्ता चुनने का मौका दिया जाना चाहिये। इसका एक फायदा यह भी है कि जब समाज का हर व्यक्ति स्वयं विचार करने लगता है तो किसी भी तरह के रूढ़िवाद और व्यक्ति-पूजा के सामने गंभीर चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही समाज में ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति बिना किसी भय और रोक-टोक के अपनी सृजनात्मकता का इज़हार करता है। मशहूर अंग्रेज़ विचारक जे.एस. मिल ने भी कहा है कि चाहे किसी व्यक्ति के विचार समाज के बाकी सभी व्यक्तियों के विचारों के विरोधी हों, तब भी उसे अपनी बात कहने का मौका ज़रूर दिया जाना चाहिये क्योंकि नए विचार पहली बार इसी तरह सामने आते हैं। जो समाज नए विचारों का सम्मान नहीं करेगा, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वाल्टर बेजहॉट ने भी कहा है कि अनुकरण की संस्कृति दुनिया के अधिकांश समाजों में है किंतु स्वतंत्र चर्चा का वरदान कुछ ही समाजों को मिला है और आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ ही समाज विकास के रास्ते पर बढ़ पाए हैं जबकि बाकी नहीं।

बुद्ध के नैतिक दृष्टिकोण का दूसरा प्रमुख विचार 'मध्यम मार्ग' के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म दार्शनिक स्तर पर तो इसका अर्थ कुछ भिन्न है, किंतु लोक नैतिकता के स्तर पर इसका

इसरो का सफर

नम्रता सिंह

(ऑडियो आर्टिकल शृंखला दृष्टि के यूट्यूब चैनल 'Drishti IAS' पर प्रसारित की जाती है जिसमें महत्त्वपूर्ण विषयों पर अंग्रेज़ी अखबारों और पत्रिकाओं में छपे लेखों का सार प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत ऑडियो आर्टिकल The Hindiu में प्रकाशित लेख "More bang for the buck: On why ISRO should go commercial" और प्रकाशित खबर "ISRO launches RISAT-2BR1, nine other satellites successfully" का सार है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं।)

हाल ही में ISRO ने Sriharikota space launch center से RISAT-2BR1 उपग्रह को अन्य नौ उपग्रहों के साथ सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह उपग्रह देश का Radar Imaging Earth Observation satellite है। इससे ठीक पहले ISRO ने अमेरिका के 13 छोटे उपग्रहों के साथ CARTOSAT-3 प्रक्षेपित किया था। ये दोनों ही उपलब्धियाँ भारत के लिये प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर मानी जा रही हैं। इसरो द्वारा नित नए प्रतिमानों को स्थापित करना और वाणिज्यिक गतिविधियों में बेहतरीन प्रदर्शन करना सराहना की बात है, साथ ही आलोचना का विषय भी बनता रहता है। ऐसे में ज़रूरी है कि इसरो के सफर और उसकी तमाम उपलब्धियों पर चर्चा की जाए।

इसरो का अब तक का सफर

इसरो ने अपनी स्थापना के समय से ही अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में बेहतरीन काम करके देश का गौरव बढ़ाया है। साथ ही देश के विकास में भी अहम योगदान दिया है। 21 नवंबर, 1963 को केरल में तिरुवनंतपुरम के करीब थुम्बा में पहले रॉकेट के लॉन्च के साथ भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। यह रोचक बात है कि उस रॉकेट को लॉन्च पैड तक एक साइकिल से ले जाया गया था और उसे एक चर्च से लॉन्च किया गया था। थोड़े समय बाद ही दूसरा रॉकेट लॉन्च किया गया जिसे बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। दरअसल इन लॉन्चिंग के बाद इसरो का गठन हुआ जो कि एक पदसोपानी प्रक्रिया थी। 1965 में Space Science and Technology की स्थापना थुम्बा में की गई, फिर 15 अगस्त, 1969 को Indian Space Research Organisation (ISRO) की स्थापना की गई और आखिर में 1975 में इसरो को पूरी तरह सरकारी संगठन बना दिया गया। इसके तुरंत बाद ही देश का पहला उपग्रह, आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया। इसरो ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक राष्ट्र को मौसम पूर्वानुमान, संचार, प्रसारण आदि प्रदान करने के लिये अलग-अलग मिशनों पर काम किया है और उनके विकास के लिये प्रौद्योगिकी विकसित की है। सबसे पहले इसरो ने Satellite Launch Vehicle विकसित किया, लेकिन उपग्रहों के विकसित होने के साथ ही इसकी उपयोगिता कम होने लग गई। ऐसे में PSLV यानी Polar Satellite Launch Vehicle एक विश्वसनीय वाहक के रूप में विकसित होकर उभरा। अपनी सस्ती लागत और भरोसेमंद होने के कारण यह दुनिया के अन्य देशों का भी पसंदीदा उपग्रह वाहक बन गया। इसी कारण इसे इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है।

एक साथ कई उपग्रहों को लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी इसरो के नाम है। हाल के दिनों में ही इसरो ने एक बार 103 और दूसरी बार 130 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया था। हालाँकि, PSLV की सफलता जगज़ाहिर है लेकिन इस व्हीकल की भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं, जैसे- 1750 किलोग्राम तक के उपग्रह को यह लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित करता है। 1425 किलोग्राम के उपग्रह को जिओ सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। लेकिन, 2 टन से ज़्यादा के उपग्रहों को LEO और GEO कक्षाओं में स्थापित करने में विफल है। इसी कारण इसरो ने सुदूर कक्षा में उपग्रह को प्रक्षेपित और स्थापित करने के उद्देश्य से GSLV का विकास किया।

GSLV मार्क 2 और 3 इसी शृंखला का हिस्सा हैं। भास्कर, इनसैट, कार्टोसैट, रीसैट, मंगलयान, चंद्रयान, एडुसैट, रिसोर्ससैट, नाविक आदि तमाम उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण ने भारत को आधुनिक तकनीकों से लैस राष्ट्र बनने में खासा सहायता की है। वह चाहे कृषि का क्षेत्र हो, खनन का, उद्योग का, शिक्षा या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो भारत आज आधुनिक तकनीकों की बदौलत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सक्षम होता जा रहा है।

इसरो और दुनिया की दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियाँ

अगर हम दुनिया के अन्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तुलना की करें तो बहुत रोचक बातें निकलकर सामने आती हैं। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अमेरिका, रूस, फ्राँस, ब्रिटेन आदि देशों के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों के बहुत बाद में गठित हुआ है। लेकिन, 1960 के दशक से लेकर अब तक इसरो की जो वृद्धि दर रही है वह अन्य देशों के अंतरिक्ष संगठनों की तुलना में कम नहीं है। इसी प्रकार इन देशों के किसी मिशन पर लगने वाली लागत या बजट के बीच भी तुलना करें तो इसरो का पलड़ा बाकी देशों की तुलना में भारी रहता है। इसे उदाहरण के रूप में समझें तो इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है मंगलयान मिशन पर होने वाले खर्च। हम जानते हैं कि भारत मंगल ग्रह पर अपना मिशन भेजने वाला विश्व का चौथा देश था। लेकिन हम दुनिया में पहले प्रयास में ही यह कामयाबी हासिल करने वाले पहले देश हैं। साथ ही, इसरो द्वारा इस अभियान पर किया जाने वाला मौद्रिक खर्च NASA द्वारा खर्च की गई राशि का महज़ 10वाँ हिस्सा है। इसी तरह चाहे बात चंद्रयान मिशन की हो या एस्ट्रोसैट जैसे विभिन्न अभियानों की, इनमें लगने वाला खर्च अन्य देशों के मुकाबले हमेशा ही कम रहा है।

करेंट अफेयर्स

(21 दिसंबर, 2019 - 20 जनवरी, 2020 तक कवरेज़)

अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम 34-36

- आरबीआई : बैंकिंग संबंधी रिपोर्ट ★★★ 34
- भारत-अमेरिका 'टू प्लस टू वार्ता' ★★★ 35
- सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक ★★★ 36

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 37-42

- अनुच्छेद-131 ★★★ 37
- संसदीय समितियाँ ★★★ 38
- सुशासन सूचकांक ★★★ 39
- दल-बदल विरोधी कानूनी ★★★ 40
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ★★★ 41
- निजी संपत्ति का अधिकार ★★ 42
- सोशल मीडिया पोस्ट ★★ 42

आर्थिक घटनाक्रम 43-47

- संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता ★★★ 43
- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, 2019 ★★★ 43
- राष्ट्रीय कार्यनीति: वर्ष 2019-2024 ★★★ 44
- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक ★★★ 45
- अनिवासी सामान्य खाता ★★★ 45
- राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ★★ 46
- GST परिषद ★★ 47

संघीय बजट 2020-21 48-54

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 55-62

- शंघाई सहयोग संगठन के आठ आश्चर्य ★★★ 55
- रायसीना डायलॉग: एक बहुपक्षीय सम्मेलन ★★★ 55
- यातना के विरुद्ध यू.एन. कन्वेंशन ★★★ 56
- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ★★★ 56
- ईरान के सांस्कृतिक स्थल ★★★ 57
- चीन-म्याँमार आर्थिक गलियारा ★★★ 58
- कैलिफोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता अधिनियम ★★ 59
- रक्षा शक्ति ★★ 61
- नेपाली भाषा 'सेके' ★★ 61
- अफगानिस्तान में संघर्ष विराम ★★ 62

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 63-67

- इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम ★★★ 63
- संचार उपग्रह जीसैट-30 ★★★ 64
- TOI 700 d ग्रह ★★★ 64
- वाई-फाई कॉलिंग ★★★ 64
- सेटकॉम तकनीक ★★★ 65
- केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल ★★★ 66
- न्यूमोकोकल वैक्सीन को स्वीकृति ★★★ 66
- H9N2: इन्फ्लूएंज़ा वायरस ★★★ 67

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 68-72

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2019 ★★★ 68
- राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक-2019 ★★★ 69
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ★★★ 70
- गैंडों की पुनर्स्थापना ★★★ 70
- यूरोपीय संघ ग्रीन डील ★★ 71
- हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट ★★ 71
- सतत् विकास प्रकोष्ठ ★★ 71
- प्रतिपूरक वनीकरण ★★ 72
- जलवायु परिवर्तन : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ★★ 72

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 73-76

- भारत में चीनी उत्पादन ★★★ 73
- वलयाकार सूर्य ग्रहण ★★★ 74
- टिड्डियों का आक्रमण ★★ 74
- असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना ★★ 75
- ऑस्ट्रेलिया में वनाग्नि ★★★ 75
- राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी ★★★ 76

सामाजिक मुद्दे 77-82

- मानसिक विकार ★★★ 77
- दलित ईसाई ★★★ 78
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम ★★★ 79
- बाल मृत्यु दर ★★★ 80
- विवाह विच्छेद ★★ 81

कला एवं संस्कृति 83-84

- संस्कृत शिलालेख ★★★ 83
- बोज्जनकोंडा व लिंगलामेत्ता बौद्ध स्थल ★★★ 83
- शास्त्रीय भाषा ★★★ 84
- मोगलमारी मध्यकालीन बौद्ध मठ ★★ 84

आंतरिक सुरक्षा 85-87

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ★★★ 85
- नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियाँ ★★★ 85
- ब्रू-रियांग ऐतिहासिक समझौता ★★ 87
- पुलिस: कमिश्नरी प्रणाली ★★ 87

संक्षिप्तियाँ 88-96

1 अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम

आरबीआई : बैंकिंग संबंधी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारतीय रिज़र्व बैंक** द्वारा भारत में **बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट-2018,19** (Report On Trends And Progress Of Banking In India-2018,19) जारी की गई। यह रिपोर्ट 2018-19 और 2019-20 की अब तक की अवधि के दौरान **सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र** के **कार्यान्वयन** को प्रस्तुत करती है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की विकास दर पिछले छह वर्षों के **न्यूनतम स्तर** (4.5 प्रतिशत) पर पहुँच गई थी।
- भारत में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति व्यापक आर्थिक क्रियाकलापों में परिवर्तन पर निर्भर होती है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- **NPA की स्थिति:** भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों का सकल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्ति (Non-Performing Assets-NPA) अनुपात सितंबर 2019 को **9.1 फीसदी** पर स्थिर रहा।
- **RBI द्वारा बैंकों के प्रदर्शन की निगरानी:** वर्तमान में 6 बैंक (4 सार्वजनिक बैंक एवं 2 निजी क्षेत्र के बैंक) तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action-PCA) फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते हैं। इनकी निरंतर निगरानी विभिन्न वित्तीय संकेतकों के माध्यम से की जा रही है।
- **क्रेडिट ग्रोथ (Credit Growth) में कमी:** वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान बैंकिंग प्रदर्शन में समग्र सुधार के बावजूद बैंकों की **क्रेडिट ग्रोथ में कमी** चिंता के रूप में सामने आई है।
- **सहकारी बैंकों के बीच स्वैच्छिक विलय को प्रोत्साहन:** सहकारी बैंक दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पहली चुनौती न केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों बल्कि सूक्ष्म वित्त बैंकों तथा भुगतान बैंकों से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा है तथा दूसरी चुनौती इन बैंकों द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित घटनाओं को रोकने की आंतरिक अक्षमता है। सहकारी बैंकों को अपने **कॉरपोरेट गवर्नेंस को उन्नत** करने और अपनी **वित्तीय स्थिति** को **मज़बूत** बनाने के लिये सुधारों को शुरू करने की आवश्यकता है।
- **NBFCs क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित:** वित्तीय वर्ष 2018-19 में गैर-बैंकिंग क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों द्वारा भुगतान दायित्वों को समय पर पूरा नहीं कर पाने के कारण **NBFCs क्षेत्र** का सकल NPA अनुपात बढ़कर **6.1 प्रतिशत** पर पहुँच गया है। इसके साथ ही पूंजी गुणवत्ता में भी कमी देखी गई है।
- **NBFCs को ऋण प्रदान करने में चूक:** वित्तीय वर्ष 2019-20 में (सितंबर तक) एक प्रमुख NBFCs द्वारा धोखाधड़ी के मामले तथा उसकी रेटिंग नीचे आने के कारण बैंकों द्वारा NBFCs को ऋण प्रदान करने में कमी आई है। यह सितंबर 2019 के अंत में **26.9 प्रतिशत हो गई।**
- **वृहद आर्थिक परिवर्तन:** वैश्विक स्तर पर नीति निर्माता **नियामक ढाँचे को मज़बूत** करने के साथ बैंकों के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **स्वीकृत मानदंडों को लागू** कर रहे हैं। इन वैश्विक नीतियों का तत्काल परिणाम नहीं देखा जा सकता है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में ये नीतियाँ वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता और लचीलेपन को बढ़ाएंगी।
- **स्वतंत्र निरीक्षण प्रणाली की आवश्यकता:** सहकारी बैंकों में **एक बेहतर आंतरिक नियंत्रण तंत्र** और **निगरानी प्रणालियों की कमी** धोखाधड़ी को रोकने संबंधी क्षमता को सीमित कर रही है। सहकारी बैंकों में सुधार सुनिश्चित करने के लिये एक **स्वतंत्र और प्रभावी निरीक्षण प्रणाली** की ज़रूरत महसूस की गई है।
- **राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के (NCLT) सदस्यों एवं पीठ की संख्या में वृद्धि आवश्यक:** निर्णय प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिये सहायक बुनियादी ढाँचे में सुधार करना एक अपरिहार्य शर्त है। हालाँकि NCLT (National Company Law Tribunal) की दो नई पीठें स्थापित की जा रही हैं, परंतु त्वरित निर्णय के लिये अभी और अधिक पीठ तथा सदस्यों की आवश्यकता है।
- **धोखाधड़ी एवं कमज़ोर कॉरपोरेट प्रशासन की निगरानी की आवश्यकता:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरधारक निदेशकों के लिये तय किये गए **'उपयुक्त एवं उचित'** (Fit and Proper) मानदंडों के संबंध में दिये गए दिशा-निर्देशों की व्यापक समीक्षा अगस्त 2019 में की गई थी। संशोधित दिशा-निर्देशों में **नए निदेशकों के लिये उचित योग्यता** तथा **अधिक परिश्रम** से संबंधित प्रावधान किये गए हैं।
- **वृद्धिशील ऋणों का 69% ऋण निजी बैंकों द्वारा:** वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी बैंकों की **वृद्धिशील ऋणों** (Incremental Loans) में भागीदारी 69% थी, जिससे बकाया ऋण में उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई।
- **धोखाधड़ी हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ज़्यादा ज़िम्मेदार:** वित्तीय वर्ष 2018-19 में दर्ज किये गए **कुल धोखाधड़ी के 55.4% मामले** और इनमें शामिल **कुल राशि का 90.2%** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है। ये आँकड़े इन बैंकों में परिचालन जोखिमों से निपटने के लिये मुख्य रूप से पर्याप्त आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों और प्रणालियों की कमी को दर्शाते हैं।
- **फिनटेक तथा बिगटेक कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा:** ये संस्थाएँ डिजिटल क्षेत्र में नवाचार का लाभ उठा रही हैं एवं नवाचार को बढ़ावा देने और एक समान पर्यवेक्षण और विनियामक ढाँचे को लागू करने के बीच संतुलन स्थापित करने में बैंकिंग नियामकों के सामने कठिन चुनौती प्रस्तुत कर रही हैं।
- **भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (IBC) के तहत वसूली:** वित्तीय वर्ष 2018-19 में IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) के तहत तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली में सुधार आया है, कुल तनावग्रस्त संपत्तियों में से आधी से अधिक की वसूली IBC के तहत की गई हैं। हालाँकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रमुख समाधान तंत्रों (लोक अदालत को छोड़कर) द्वारा वसूली गई राशि में कमी आई है। ■■■

2 संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

अनुच्छेद-131 ★★★

चर्चा में क्यों?

केरल, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल सरकार ने शीर्ष अदालत में यह याचिका संविधान के अनुच्छेद-131 के तहत दायर की है।

प्रमुख बिंदु

- **संविधान का अनुच्छेद-131 सर्वोच्च न्यायालय की मूल/आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है।** इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत के संघीय ढाँचे को लेकर विभिन्न इकाइयों के मध्य होने वाले विवादों की सुनवाई करता है।
- **अनुच्छेद 131 के उपबंधों में निम्नलिखित प्रकार के विवादों को शामिल किया गया है-**
  - **केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या;**
  - **एक ओर केंद्र सरकार और एक राज्य या कई राज्य और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच या;**
  - **दो या अधिक राज्यों के बीच**
- उल्लेखनीय है कि **उपर्युक्त विवाद सर्वोच्च न्यायालय का 'विशेष मूल न्यायक्षेत्र' (Extraordinary Original Jurisdiction) है।** यहाँ विशेष का तात्पर्य यह है कि इन मामलों का निपटारा किसी अन्य न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 131 के तहत योग्य मामले

- अनुच्छेद 131 के तहत आने वाले मामले में याचिककर्त्ता और प्रतिपक्षी के साथ-साथ मामले की प्रकृति भी काफी अहम होती है।
- **अनुच्छेद 131 के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य उन विवादों की सुनवाई की जा सकती है जिनमें कानून या तथ्य का प्रश्न निहित हो और जिन पर राज्य या केंद्र के कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है।**
- उल्लेखनीय है कि संविधान की इस धारा का उपयोग विभिन्न दलों वाली केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक विवादों के बीच निपटारे के लिये नहीं किया जा सकता है।
- अत: केंद्र और राज्य/राज्यों के मध्य कार्यकारी शक्तियों के निर्वहन के मामले में अनुच्छेद 131 को संदर्भित नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच विवाद के मामले में सुनवाई करने पर असहमति जताई थी।
- इस तरह **अनुच्छेद 131 के तहत दर्ज होने वाले मामले में संवैधानिक संबंध के संदर्भ के साथ कानूनी अधिकार का प्रश्न भी निहित होना चाहिये।**

अनुच्छेद 131 से संबंधित मामले

- आरंभिक/मूल अधिकारिता को लेकर पहला मामला वर्ष 1961 में **पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ** का था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने संसद द्वारा पारित कोयला खदान क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 को न्यायालय में चुनौती दी थी।
- वर्ष 1978 में **कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ मामले** में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने निर्णय दिया था कि राज्य को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है लेकिन इसमें कानूनी सवाल मौजूद होने चाहिये।
- पूर्व के मामले में यह कहा गया था कि अनुच्छेद 131 द्वारा कानून की संवैधानिकता की जाँच की जा सकती है लेकिन **वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ मामले** में न्यायालय का निर्णय इससे इतर था। हालाँकि यह मामला भी न्यायालय के तीन जजों वाली पीठ (जिसमें न्यायमूर्ति एन.वी रमणा, संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी शामिल हैं) के समक्ष लंबित है।
- वर्ष 2012 का **झारखंड राज्य बनाम बिहार राज्य** का वह मामला जिसमें अविभाजित बिहार राज्य में अपनी रोज़गार अवधि के लिये झारखंड के कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने के लिये बिहार के दायित्व का मुद्दा शामिल है। यह मामला भी न्यायालय की बड़ी पीठ की सुनवाई के लिये लंबित है।

केरल सरकार का तर्क

नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुपालन हेतु अनुच्छेद 256 के तहत बाध्यता के चलते लोगों के मौलिक, सांविधिक, संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के साथ एक राज्य के रूप में केरल के समक्ष कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी मुद्दे उपस्थित होंगे।

केंद्र की अनुच्छेद 131 के प्रयोग की शक्ति

- केंद्र सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिये कि उसके द्वारा बनाए गए कानून लागू किये जाएँ, पर्याप्त शक्तियाँ मौजूद हैं।
- **संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिये केंद्र सरकार राज्य को निर्देश जारी कर सकती है। यदि राज्य सरकारें केंद्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करती हैं तो केंद्र सरकार राज्यों को कानून के अनुपालन हेतु बाध्य करने के लिये उनके विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय के समक्ष जा सकती है।**
- इस तरह न्यायालय के आदेशों का पालन न करने पर न्यायालय की अवमानना हो सकती है और इसके लिये न्यायालय द्वारा ज़िम्मेदार राज्यों के मुख्य सचिवों को दोषी ठहराया जा सकता है।
- **इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 256 के तहत भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक है जिन्हें भारत सरकार किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक समझती है।**

3 आर्थिक घटनाक्रम

संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित **वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स** (WESP) रिपोर्ट में बताया गया है कि **वर्तमान में आर्थिक मंदी का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर में बढ़ोत्तरी** के लिये **निरंतर संरचनात्मक सुधारों** की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार WESP द्वारा जीडीपी का पूर्वानुमान करते समय **भारत** के **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय** (National Statistical Office-NSO) द्वारा जारी **नवीनतम आँकड़ों** को शामिल **नहीं** किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स (WESP) रिपोर्ट-2020 ने भारत के लिये **जीडीपी संवृद्धि का अनुमान कम** कर दिया है, परंतु यह उम्मीद भी जताई है कि राजकोषीय प्रोत्साहन और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के संयोजन से उपभोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- वर्ष 2018 के 6.8 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2019 में 5.7 प्रतिशत की दर से अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट ने भारत की मौद्रिक नीति के पूरक के रूप में राजकोषीय विस्तार की आवश्यकता को इंगित किया है।
- **राजकोषीय प्रोत्साहन और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के संयोजन**, **निवेश एवं उपभोग को बढ़ावा** देकर जीडीपी में **6.6 प्रतिशत की संवृद्धि दर** हासिल की जा सकती है।
- भारत का वृहद आर्थिक बुनियादी ढाँचा पूर्व की भाँति मज़बूत है और इसमें अगले वित्त वर्ष तक सुधार की उम्मीद है।
- **प्रत्येक पाँच देशों में** से एक देश में **इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय में कमी या गिरावट** होगी, लेकिन भारत को ऐसे देशों में सूचीबद्ध किया गया है जहाँ **वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति जीडीपी संवृद्धि दर 4 प्रतिशत के स्तर से अधिक** होने की संभावना है।
- वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में लंबे समय तक जारी गिरावट सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बाधक बन सकती है, जिसमें गरीबी उन्मूलन और सभी के लिये रोज़गार के अवसरों का सृजन करने जैसे लक्ष्य भी शामिल हैं।
- **पूर्वी एशिया दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता क्षेत्र** है और वैश्विक विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है।
- **वर्ष 2020** में **ब्राज़ील, भारत, मैक्सिको, रूसी संघ और तुर्की सहित** अन्य बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की **संवृद्धि दर में बढ़ोतरी** होने की उम्मीद है।
- **गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य असमानता की समाप्ति की दिशा** में उठाए गए उपायों पर निर्भर करेगा।

वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक कार्य विभाग द्वारा जारी की जाती है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, 2019 ★★★

चर्चा में क्यों?

27 दिसंबर, 2019 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने **वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट** (Financial Stability Report-FSR) का **20वाँ अंक** जारी किया। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) एक **अर्द्धवार्षिक प्रकाशन** है जो **भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का समग्र मूल्यांकन** प्रस्तुत करती है।

प्रणालीगत जोखिमों का समग्र मूल्यांकन (Overall Assessment of Systemic Risks)

कमज़ोर घरेलू विकास के बावजूद **भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर** बनी हुई है। सरकार द्वारा **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के पुनर्पूंजीकरण** (Recapitalisation) के बाद **बैंकिंग क्षेत्र में लचीलापन** आया है। हालाँकि वैश्विक/घरेलू आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से उत्पन्न होने वाले **जोखिम बने** हुए हैं।

वैश्विक और घरेलू समष्टि-वित्तीय जोखिम (Global and Domestic Macro-Financial Risks)

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में **कई अनिश्चितताओं** जैसे ब्रेक्ज़िट समझौते में देरी, व्यापार तनाव, एक आसन्न मंदी की भावना, तेल-बाज़ार में व्यवधान और भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण **वैश्विक अर्थव्यवस्था में** मंदी देखी गई।
- **घरेलू अर्थव्यवस्था** के संबंध में वित्तीय वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में **सकल मांग में आई कमी** के कारण में **संवृद्धि में गिरावट** देखी गई जबकि **पूंजी अंतर्वाह** की **संभावनाएँ सकारात्मक** बनी हुई है। भारत के निर्यात को निरंतर वैश्विक मंदी की स्थिति में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऊर्जा मूल्य के कमज़ोर रहने के कारण चालू खाता घाटे के नियंत्रण में रहने की संभावना है।

वित्तीय संस्थाएँ: कार्य निष्पादन और जोखिम (Financial Institutions : Performance and Risks)

- **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** (Scheduled Commercial Banks-SCBs) की **ऋण वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत** रही, हालाँकि **निजी क्षेत्र के बैंकों** (Private Sector Banks-PVBs) ने **16.5 प्रतिशत की ऋण वृद्धि दर** दर्ज की।
- सरकार द्वारा **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों** (Public Sector Banks-PSBs) के **पुनर्पूंजीकरण के बाद SCBs के पूंजी पर्याप्तता अनुपात में** काफी

संघीय बजट 2020-21

बजट 2020-21

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया जो अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण था। इस बजट का लक्ष्य लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना, कारोबार मज़बूत करना और अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/जनजाति की सभी महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना बताया गया।

प्रमुख बिंदु

- **व्यय:** केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में **₹30.42 लाख करोड़** खर्च करने का प्रस्ताव किया है, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान से 12.7 प्रतिशत अधिक है।
- **प्राप्ति:** वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये केंद्र सरकार ने **₹22.46 लाख करोड़** की प्राप्ति अनुमानित की है जो वित्तीय वर्ष 2019-20 से 16.3 प्रतिशत अधिक है।

2020-21 बजट एक नज़र में (₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-19	बजटीय 2019-20	संशोधित 2019-20	बजटीय 2020-21	% परिवर्तन (RE 2019-20 to BE 2020-21)
राजस्व व्यय	20,07,399	24,47,780	23,49,645	26,30,145	11.9%
पूंजी व्यय	3,07,714	3,38,569	3,48,907	4,12,085	18.1%
कुल व्यय	**23,15,113**	**27,86,349**	**26,98,552**	**30,42,230**	**12.7%**
राजस्व प्राप्ति	15,52,916	19,62,761	18,50,101	20,20,926	9.2%
पूंजी प्राप्ति	1,12,779	1,19,828	81,605	2,24,967	175.7%
जिनमें से:					
ऋणों की वसूली	18,052	14,828	16,605	14,967	-9.9%
अन्य प्राप्तियाँ (विनिवेश सहित)	94,727	1,05,000	65,000	2,10,000	223.1%
कुल प्राप्तियाँ (उधार छोड़कर)	**16,65,695**	**20,82,589**	**19,31,706**	**22,45,893**	**16.3%**
राजस्व घाटा	4,54,483	4,85,019	4,99,544	6,09,219	22.0%
GDP का %	**2.4**	**2.3**	**2.4**	**2.7**	
राजकोषीय घाटा	6,49,418	7,03,760	7,66,846	7,96,337	3.8%
GDP का %	3.4	3.3	3.8	3.5	
प्राथमिक घाटा	66,770	43,289	1,41,741	88,134	-37.8%
GDP का %	0.4	0.2	0.7	0.4	

बजट अनुमान (BE): प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में घोषित बजट आवंटन।
संशोधित अनुमान (RE): वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्तियों एवं व्यय की पेश की गई मात्रा का अनुमान।

स्रोत: *संघीय बजट 2020-21 (वित्त मंत्रालय)*

- **GDP वृद्धि:** केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में सांकेतिक GDP में **10 प्रतिशत की वृद्धि दर** अनुमानित की है।
- **घाटा:** आगामी वित्त वर्ष के लिये राजस्व घाटा **कुल GDP का 2.7 प्रतिशत** निर्धारित किया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 में 2.4 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से **अधिक** है। **राजकोषीय घाटा** कुल GDP का **3.5 प्रतिशत** निर्धारित किया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 में 3.8 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से **कम** है।

कर संबंधी प्रावधान

प्रत्यक्ष कर

- **आयकर:** केंद्र सरकार ने आयकरदाताओं को राहत प्रदान करने तथा **आयकर संबंधी कानूनों को सरल बनाने** के उद्देश्य से **एक नई और सरलीकृत आयकर व्यवस्था** स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिये आयकर दरों को कम किया जाएगा, जो निर्धारित कटौतियों और छूटों का त्याग करेंगे। ध्यातव्य है कि नई व्यवस्था **वैकल्पिक** होगी अर्थात् करदाताओं को पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के मध्य चुनाव का विकल्प दिया जाएगा।

आयकर स्लैब (₹)	मौजूदा दरें (%)	नई दरें (%)
0 से 2.5 लाख	छूट	छूट
2.5 से 5 लाख	5	छूट
5 से 7.5 लाख	20	10
7.5 से 10 लाख	20	15
10 से 12.5 लाख	30	20
12.5 से 15 लाख	30	25
15 लाख से ऊपर	30	30

- **लाभांश वितरण कर (DDT):** वर्तमान में कंपनियों को अपने शेयरधारकों को दिये गए लाभांश पर लागू अधिभार और उपकर सहित 15 प्रतिशत से अधिक लाभांश वितरण कर देना पड़ता है, जो कि कंपनी द्वारा अपने लाभों

4 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अतंर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

शंघाई सहयोग संगठन के आठ आश्चर्य ★★★

चर्चा में क्यों?

आठ देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन **'शंघाई सहयोग संगठन'** (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) ने **'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी'** (Statue of Unity) को **SCO के आठवें आश्चर्य** के रूप में **शामिल** किया है।

मुख्य बिंदु

- नवंबर 2019 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने अमेरिका की 133 साल पुरानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (Statue of Liberty) को **पर्यटकों की आवाजाही के मामले में पीछे छोड़ दिया** क्योंकि गुजरात में आने वाले पर्यटकों की संख्या इस दौरान 15000 से अधिक हो गई।
- SCO द्वारा उठाए गए इस कदम से इसके सदस्य राष्ट्रों के बीच **पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा** जिससे **भारत का विकास होगा** क्योंकि पर्यटन राष्ट्रीय विकास का मुख्य वाहक होता है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

- 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' 182 मीटर ऊँची **सरदार वल्लभभाई पटेल** की प्रतिमा है जो गुजरात के नर्मदा ज़िले में सरदार सरोवर बाँध के पास **राजपीपला में साधुबेट नामक नदी द्वीप** पर स्थित है।
- 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' चीन के स्प्रिंग टेंपल में स्थित 153 मीटर ऊँची प्रतिमा (अब तक विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा का दर्जा प्राप्त था) से भी ऊँची है और न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (93 मी.) की ऊँचाई से करीब दोगुनी है।

SCO के आठ आश्चर्य

- **भारत: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी**
- **कज़ाखस्तान: तमगली के पुरातात्त्विक परिदृश्य (The Archaeological Landscape of Tamgaly)**
- **किर्गिज़स्तान: इसीक-कुल झील (Lake Issyk-Kul)**
- **चीन: डेमिंग पैलेस (Daming Palace)**
- **पाकिस्तान: मुगल विरासत, लाहौर (Mughals Heritage)**
- **रूस: द गोल्डन रिंग ऑफ सिटीज़ (The Golden Ring of Cities)**
- **ताजिकिस्तान: द पैलेस ऑफ नौरोज़ (The Palace of Nowruz)**
- **उज़्बेकिस्तान: द पोई कालोन कॉम्प्लेक्स (The Poi Kalon complex)**

रायसीना डायलॉग: एक बहुपक्षीय सम्मेलन ★★★

चर्चा में क्यों?

14-16 जनवरी, 2020 के मध्य **रायसीना डायलॉग के पाँचवें संस्करण** का आयोजन **नई दिल्ली** में किया गया। **विदेश मंत्रालय** और **ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन** की ओर से आयोजित इस तीन दिवसीय सम्मेलन में 100 देशों के 700 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हुए।

प्रमुख बिंदु

- रायसीना डायलॉग 2020 की थीम- **'नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी'** (Navigating the Alpha Century) थी।
- वैश्विक रूप से **प्रतिष्ठित कूटनीतिक संवाद कार्यक्रम** रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अफगानिस्तान, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, स्वीडन, डेनमार्क, भूटान और दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्र प्रमुख ने विश्व की मौजूदा चुनौतियों पर विचार साझा किये।
- इस वर्ष रूस, ईरान, डेनमार्क, हंगरी, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका और एस्टोनिया सहित 12 देशों के विदेश मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया जो वैश्विक कूटनीतिक पटल पर भारत की बढ़ती साख को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त शंघाई सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी इस सम्मेलन में शामिल हुए।
- इस सम्मेलन में **वैश्वीकरण से जुड़ी चुनौतियों, एजेंडा 2030, आधुनिक विश्व में प्रौद्योगिकी की भूमिका, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद का मुकाबला** जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।

रायसीना डायलॉग

- रायसीना डायलॉग की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य **एशियाई एकीकरण** के साथ-साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना है।
- यह **भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा** करने हेतु एक **वार्षिक सम्मेलन** है जिसका आयोजन **भारत के विदेश मंत्रालय** और **ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन** (Observer Research Foundation-ORF) द्वारा **संयुक्त रूप** से किया जाता है।
- रायसीना डायलॉग एक **बहुपक्षीय सम्मेलन** है जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय **रायसीना पहाड़ी** (साउथ ब्लॉक), नई दिल्ली में स्थित है, इसलिये इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अंतरिक्ष

इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम ★★★

चर्चा में क्यों?

इसरो अंतरिक्ष में एक **ऐसी नई उपग्रह प्रणाली** भेजने की योजना बना रहा है जो भविष्य के **अंतरिक्ष कार्यक्रमों के दौरान अंतरिक्ष और इसरो के मध्य बेहतर संपर्क** स्थापित करने में सहायक होगी।

प्रमुख बिंदु

- **इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम (IDRSS)** नामक **दो उपग्रहों वाली** इस **प्रणाली का उद्देश्य** इसरो को अंतरिक्ष में उपग्रहों से संपर्क स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है।
- 2000 किग्रा. भारवर्ग के दो उपग्रहों की इस प्रणाली को **GSLV प्रक्षेपक** द्वारा पृथ्वी की **भू-स्थिर कक्षा** (Geostationary Orbit-GEO) में लगभग 36000 की किमी. ऊँचाई पर स्थापित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि **पहले उपग्रह को वर्ष 2020 के अंत** तक तथा **दूसरे को वर्ष 2021 में** अंतरिक्ष में भेजने की योजना है।

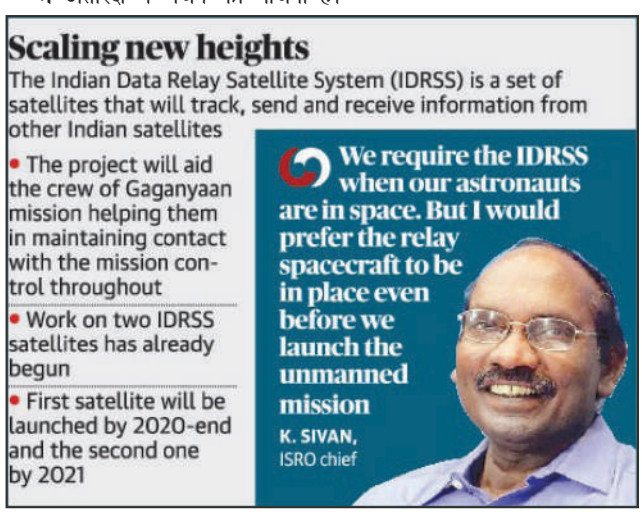

- भू-स्थिर कक्षा में स्थित एक उपग्रह धरती के एक-तिहाई (1/3) क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम होता है किंतु यदि इस कक्षा में तीन उपग्रह स्थापित कर दिये जाएँ तो वे धरती के 100% क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम होंगे।

आवश्यकता

- वर्तमान में भू-स्थिर कक्षा में स्थित उपग्रहों से संपर्क व इन उपग्रहों की **निगरानी में विभिन्न देशों में स्थित नियंत्रण केंद्रों की सहायता** ली जाती है। इस प्रणाली के तहत 24 घंटों में किसी भी उपग्रह से अनेक प्रयासों के बाद **कई टुकड़ों (Discontinuous Fragments) में औसतन 10-15 मिनट ही संपर्क** हो पाता है, जबकि IDRSS द्वारा इन उपग्रहों से 24 घंटे लगातार संपर्क स्थापित किया जा सकेगा।
- यह प्रणाली इसरो को अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की निगरानी करने में मदद के साथ ही **भविष्य की योजनाओं को नई शक्ति प्रदान करेगी**।
- इस प्रणाली द्वारा **निम्न भू-कक्षा के कार्यक्रमों** जैसे-स्पेस डॉकिंग (Space Docking), स्पेस स्टेशन तथा अन्य बड़े अभियानों जैसे- चंद्रयान, मंगल मिशन आदि में सहायता प्राप्त होगी।
- मानव मिशन के दौरान जब अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में 400 किमी. की दूरी पर चक्कर लगाता है तो **अंतरिक्षयान के लिये हर समय पृथ्वी पर किसी नियंत्रण केंद्र के संपर्क में रहना अनिवार्य होता है। ऐसे में IDRSS के अभाव में हमें कई अंतरिक्ष केंद्र बनाने पड़ेंगे** या महत्त्वपूर्ण सूचनाओं के लिये अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा।
- इस **प्रणाली का पहला लाभ वर्ष 2022 के गगनयान अभियान के दौरान** मिलेगा, परंतु इसरो के अनुसार, इस प्रणाली को गगनयान अभियान से पहले प्रयोग हेतु पूर्णरूप से सक्रिय करने की योजना है।

अन्य देश

- **अमेरिका और रूस** ने इस श्रेणी की प्रसारण उपग्रह प्रणाली की शुरुआत **1970-80 के दशक से ही** कर दी थी और वर्तमान में कुछ देशों के पास आज इस प्रणाली के अंतर्गत लगभग 10 उपग्रह हैं।
- **रूस ने इस तकनीकी का उपयोग** अपने अंतरिक्ष स्टेशन **मीर (MIR)** की निगरानी और संपर्क बनाए रखने तथा अन्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिये किया था।

मीर (MIR)

यह वर्ष 1986 में सोवियत संघ द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा गया एक स्पेस स्टेशन था। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वर्ष 2001 में इस कार्यक्रम के बंद होने तक इसका संचालन रूस द्वारा किया गया।

- **अमेरिका ने** इस तकनीकी की सहायता से ही **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन व हब्बल स्पेस टेलीस्कोप** जैसे अभियानों **में सफलता** पाई।
- वर्तमान में अमेरिका तीसरी पीढ़ी के ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट (TDRS) तैयार कर रहा है, जबकि रूस के पास सैटेलाइट डेटा रिले नेटवर्क (SDRN) नामक प्रणाली है।
- यूरोप भी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिये यूरोपियन डेटा रिले सिस्टम निर्मित कर रहा है तथा वर्तमान में चीन अपनी दूसरी पीढ़ी की टिआनलिआन-II सीरिज़ पर काम कर रहा है।

6 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2019 ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** के तहत कार्यरत संस्थान भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा **भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2019 (ISFR 2019)** जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिये **भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट-2** से प्राप्त आँकड़ों का प्रयोग किया गया है।
- वर्तमान रिपोर्ट में **'वनों के प्रकार एवं जैव-विविधता' (Forest Types and Biodiversity)** नामक एक नए अध्याय को जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को **16 मुख्य वर्गों** में विभाजित करके उनका **'चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण' (Champion & Seth Classification)** के आधार पर आकलन किया गया।
- **वर्ष 1987 से** भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को **द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा** प्रकाशित किया जाता है। यह इस श्रेणी की **16वीं** रिपोर्ट है।

चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण

- **हैरी जॉर्ज चैंपियन द्वारा वर्ष 1936 में** भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय एवं मान्य वर्गीकरण किया गया था। **वर्ष 1968 में चैंपियन एवं एस.के. सेठ (S.K Seth)** ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिये इसे पुनः प्रकाशित किया।
- यह वर्गीकरण **पौधों की संरचना**, **आकृति विज्ञान** और **पादप स्वरूप** पर आधारित है।

ISFR, 2019 से संबंधित प्रमुख तथ्य	
कुल वनावरण एवं वृक्षावरण	8,07,276 वर्ग किमी. (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56%)
केवल वनावरण	7,12,249 वर्ग किमी. (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67%)
केवल वृक्षावरण	95,027 वर्ग किमी. (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89%)
वनावरण में वृद्धि	3,976 वर्ग किमी. (0.56%)
वृक्षावरण में वृद्धि	1,212 वर्ग किमी. (1.29%)
वनावरण एवं वृक्षावरण में कुल वृद्धि	5,188 वर्ग किमी. (0.65%)

सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य	
मिज़ोरम	85.41%
अरुणाचल प्रदेश	79.63%
मेघालय	76.33%
मणिपुर	75.46%
नगालैंड	75.31%

सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य	
मध्य प्रदेश	77,482 वर्ग किमी.
अरुणाचल प्रदेश	66,688 वर्ग किमी.
छत्तीसगढ़	55,611 वर्ग किमी.
ओडिशा	51,619 वर्ग किमी.
महाराष्ट्र	50,778 वर्ग किमी.

वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य	
कर्नाटक	1,025 वर्ग किमी.
आंध्र प्रदेश	990 वर्ग किमी.
केरल	823 वर्ग किमी.
जम्मू-कश्मीर (राज्य पुनर्गठन के पूर्व)	371 वर्ग किमी.
हिमाचल प्रदेश	334 वर्ग किमी.

रिपोर्ट से संबंधित अन्य तथ्य

अभिलिखित वन क्षेत्र

- **अभिलिखित वन क्षेत्र (Recorded Forest Area-RFA)** ऐसी भूमि को कहते हैं, जिसे किसी सरकारी अधिनियम या नियम के तहत वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो या उसे सरकारी रिकॉर्ड में 'वन' के रूप में दर्ज किया गया हो। ISFR-2019 में आर्द्रभूमियों को भी RFA के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- ISFR-2019 के अनुसार, भारत के **RFA में 330 वर्ग किमी.** या कुल क्षेत्रफल में 0.05% की मामूली कमी आई है।
- भारत में लगभग 62,466 आर्द्रभूमियाँ हैं जो देश के RFA के लगभग 3.83% क्षेत्र को कवर करती हैं।
- भारतीय राज्यों में RFA के अंतर्गत सर्वाधिक **आर्द्रभूमि गुजरात में है** तथा **दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल** है।

कार्बन स्टॉक

- वर्तमान में भारत के वनों का **कुल कार्बन स्टॉक (Total Carbon Stock)** लगभग 7,124.6 मिलियन टन अनुमानित है। वर्ष 2017 की तुलना में इसमें लगभग 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।

7 भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

भूगोल

भारत में चीनी उत्पादन ★★★

चर्चा में क्यों?

चालू विपणन वर्ष 2019-20 के पहले तीन महीनों में देश का चीनी उत्पादन 30.22% घटकर 7.79 मिलियन टन हो गया।

प्रमुख बिंदु

केंद्र सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिये **'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP)** में बढ़ोतरी नहीं की है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं पंजाब आदि राज्य सरकारों ने भी **'प्रदेश परामर्शित मूल्य' (State Advised Price-SAP)** में बढ़ोतरी नहीं की है।

उचित और लाभप्रद मूल्य

चीनी मिलें जिस मूल्य पर किसानों से गन्ना खरीदती हैं उसे उचित और लाभप्रद मूल्य कहा जाता है। इसका निर्धारण **'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (CACP)** की सिफारिशों के आधार पर **'आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति' (CCEA)** द्वारा किया जाता है।

- बाढ़ से प्रभावित गन्ने की फसल में सुक्रोज़ की मात्रा कम होने से महाराष्ट्र में इस वर्ष चीनी का औसत उत्पादन वर्ष 2018-19 की तुलना में 10.5% से घटकर 10% हो गया।

भारत में चीनी उद्योग

- भारत, विश्व में गन्ना और गन्ना उत्पादों का अग्रणी देश है। वर्तमान में यह भारत में **सूती वस्त्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित** उद्योग है।
- **20वीं शताब्दी के प्रारंभ** में चीनी उद्योग की शुरुआत उत्तर प्रदेश और बिहार में **नील उत्पादकों** द्वारा **सिंथेटिक डाई** के प्रारंभ के कारण नील की मांग में कमी आने के बाद की गई थी।

भौगोलिक वितरण

- देश में अधिकांश चीनी उत्पादन **उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में होता** है। चीनी का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मेरठ, सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती एवं गोंडा आदि क्षेत्रों में होता है। इसके अतिरिक्त इस उद्योग **का संकेंद्रण बिहार** के दरभंगा, सारण, चंपारण और मुज़फ्फरपुर आदि क्षेत्रों में है।
- दक्षिण भारत में मुख्यत: महाराष्ट्र में **सहकारी क्षेत्र के** अंतर्गत चीनी मिलों एवं गन्ने की खेती का प्रबंधन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी सीमित मात्रा में गन्ने की खेती की जाती है।

उत्तर भारत में चीनी उद्योग के संकेंद्रण के कारण

- **चूना व पोटॉश** से समृद्ध **उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी**।
- सिंचाई के लिये उपयुक्त **समतल भूमि**।
- इस उद्योग की **कोयले पर कम निर्भरता**, ईंधन के लिये गन्ने की खोई का प्रयोग।
- निकटवर्ती क्षेत्रों में **यातायात सुविधाओं से जुड़ा बाज़ार**।
- **सस्ते श्रम** की उपलब्धता।
- **विस्तृत क्षेत्रों** में गन्ने की खेती।

- **दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के विकास की संभावनाएँ:**
  - उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में **उच्च उत्पादकता**।
  - दक्षिण भारत में उत्पादित गन्ने में **सुक्रोज़ की अधिक मात्रा** पाई जाती है।
  - उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में **पेराई सत्र अधिक लंबा** होता है।
- **उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की धीमी प्रगति के कारण:**
  - इस क्षेत्र में **नकदी फसल के लिये अधिक विकल्प** हैं, इसलिये किसान **कपास, मूँगफली, नारियल, तंबाकू इत्यादि** के उत्पादन में अधिक रुचि रखते हैं।
  - महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पानी की कमी के कारण **उच्च सिंचाई दरें**।
  - उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गन्ने की खेती कम विस्तृत क्षेत्रों में होती है।

भारत में चीनी उद्योग से संबंधित समस्याएँ

- **उचित एवं लाभकारी मूल्य** के निर्धारण से संबंधित समस्याओं के साथ ही किसानों को दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता को लेकर केंद्र और राज्यों के मध्य **समन्वय का अभाव**।
- अधिकांश चीनी मिलों की **पेराई क्षमता सीमित** है। **पुरानी मशीनरी, वसूली की न्यून** दर, **उत्पादन की उच्च लागत** लाभ को कम कर देते हैं।
- बिना किसी नियंत्रण के **गुड़/खांडसारी उद्योग** द्वारा गन्ना के एक-तिहाई भाग का उपयोग किया जाता है, जो चीनी मिलों में गन्ने की कमी का कारण बनता है।
- गन्ने की पेराई अवधि 4-6 महीने की होती है अत: इसकी प्रकृति मौसमी है, जो श्रमिकों के लिये वित्तीय समस्याएँ उत्पन्न करती है।

भारत में इस उद्योग पर निर्भर एक बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए **सरकार, किसानों और गन्ना मिल मालिकों के** मध्य समन्वय होना ज़रूरी है।

8 सामाजिक मुद्दे

मानसिक विकार ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **इंडिया स्टेट लेवल डिज़ीज़ बर्डन इनिशिएटिव** (India State-Level Disease Burden Initiative) **द्वारा पहली बार भारत में मानसिक रोगों के लिये ज़िम्मेदार कारणों का एक व्यापक अनुमान** लांसेट साइकैट्री (Lancet Psychiatry) में प्रकाशित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट को **'द बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ इंडिया: द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ स्टडी** 1990-2017 (The Mental Disorders Across the States of India: the Global Burden of Disease Study 1990-2017) नाम दिया गया है।
- यह रिपोर्ट भारत में **सभी प्रकार के मानसिक विकारों के प्रसार और बीमारी के बोझ का वर्णन** करती है।
- इंडिया स्टेट लेवल डिज़ीज़ इनिशिएटिव की **शुरुआत वर्ष 2015 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से स्थानीय स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रवृत्तियों में ज्ञात महत्त्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिये** की गई थी।
- यह इनिशिएटिव इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूशन और संपूर्ण भारत के लगभग 100 संस्थानों के विशेषज्ञों एवं हितधारकों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।

अध्ययन के निष्कर्ष

- **वर्ष 2017 में भारत में कुल 197 मिलियन (लगभग 14.3%) लोग विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों से ग्रसित थे अर्थात् प्रत्येक 7 में से 1 भारतीय इससे ग्रसित था।** इनमें से 45.7 मिलियन लोग अवसाद (Depression) और 44.9 मिलियन चिंता (Anxiety) संबंधी विकारों से ग्रसित थे।
- वर्ष 2017 में भारत में कुल **नि:सक्तता समायोजित जीवन वर्ष (Disability Adjusted Life Years-DALYs) में मानसिक विकारों का योगदान 4.7%** रहा, जबकि वर्ष 1990 में यह 2.5% था।
- **नि:सक्तता पीड़ित वर्ष (Years Lived with Disability-YLD) के संदर्भ में देखा जाए तो यह मानसिक विकारों का प्रमुख कारक रहा है वर्ष 2017 में इसका योगदान 14.5% था।**
- मुख्य रूप से **वयस्कता के दौरान प्रकट होने वाले मानसिक विकार आमतौर पर कम विकसित उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों में अधिक** देखे गए।
- दूसरी तरफ मुख्य रूप से **बचपन और किशोरावस्था में शुरू होने वाले मानसिक विकार दक्षिणी राज्यों की तुलना में उत्तरी राज्यों में अधिक** पाए गए।
- **अवसादग्रस्त विकारों का सर्वाधिक प्रसार तमिलनाडु** में था, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल का स्थान आता है।
- लैंगिक आधार पर देखा जाए तो कुल DALYs में अवसादग्रस्त विकारों एवं खानपान संबंधों विकारों का योगदान पुरुषों की तुलना में महिलाओं में काफी अधिक था, जबकि **ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर एवं अटेंशन डेफिसिट/हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD) का योगदान महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक** था।

मानसिक विकार के कारण

- दक्षिणी राज्यों में चिंता एवं अवसाद संबंधी विकारों का उच्च प्रसार अन्य कारकों के साथ **आधुनिकीकरण एवं शहरीकरण के उच्च स्तर** से संबंधित हैं। अवसादग्रस्तता एवं आत्महत्या के बीच एक सकारात्मक संबंध है, उल्लेखनीय है कि उत्तरी राज्यों की तुलना में **दक्षिणी राज्यों में आत्महत्या से होने वाली मौतों की दर अधिक** है।
- **महिलाओं में मानसिक विकारों के प्रमुख कारणों में लैंगिक भेदभाव, हिंसा, यौन दुर्व्यवहार के साथ प्रतिकूल सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड शामिल हैं।**
- पुरुषों में ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकारों और ADHD के उच्च प्रसार के लिये आनुवंशिक एवं हार्मोनल कारक ज़िम्मेदार हैं।
- इन सभी कारकों के अतिरिक्त **महिलाओं में खानपान संबंधी विकारों का काफी प्रचलन देखा गया है जो आनुवंशिक और जैविक कारकों के साथ सोशल मीडिया तथा सामाजिक-सांस्कृतिक दबावों से जुड़ा है।**

DALY एवं YLD में अंतर

- **एक विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (DALY) का तात्पर्य स्वस्थ जीवन के एक वर्ष की क्षति होने से है।** संपूर्ण जनसंख्या में DALYs का योग या रोग का बोझ (Burden of Disease) वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और एक आदर्श स्वास्थ्य स्थिति (जहाँ पूरी आबादी एक उन्नत उम्र तक बीमारी एवं नि:सक्तता से मुक्त रहती है) के बीच के अंतराल को दर्शाता है।
- **विकलांगता पीड़ित वर्ष (YLD) किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति (Health Condition) और उसके परिणामस्वरूप बिताये गए जीवन अवधि को प्रदर्शित करता है।**

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- समाज में मानसिक विकारों की गंभीरता एवं इससे निपटने हेतु बुनियादी ढाँचे की अपर्याप्तता को देखते हुए सरकार द्वारा **वर्ष 1982 में राष्ट्रीय**

9 कला एवं संस्कृति

संस्कृत शिलालेख ★★★

चर्चा में क्यों?

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की पुरालेख शाखा ने अब तक के **सबसे पुराने संस्कृत शिलालेख की खोज** की है। इस शिलालेख से **सप्तमातृका के बारे में जानकारी** मिलती है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि यह संस्कृत शिलालेख **आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले के चेब्रोलू गाँव** में खोजा गया है। इस स्थान पर **प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि** में एक अन्य शिलालेख भी प्राप्त हुआ है जिसे पहली सदी से संबंधित बताया जा रहा है।
- इस शिलालेख में संस्कृत और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया हैं, इसे **सातवाहन वंश के राजा विजय** द्वारा 207 ईसवी में जारी किया गया था।
- **राजा विजय सातवाहन वंश के 28वें राजा** थे, इन्होंने 6 वर्षों तक शासन किया था। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यत: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक था।
- इस शिलालेख में एक **मंदिर तथा मंडप के निर्माण के बारे में वर्णन** किया गया है।
- इस अभिलेख में **कार्तिक नामक व्यक्ति को ताम्ब्रापे** (चेब्रोलू गाँव का प्राचीन नाम) गाँव में **सप्तमातृका मंदिर के पास प्रासाद** (मंदिर) व **मंडप बनाने का आदेश** दिया गया है।

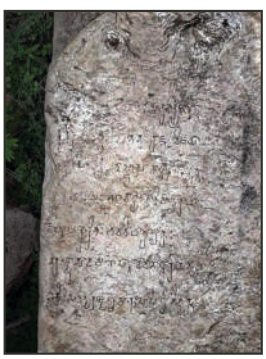

- चेब्रोलू संस्कृत शिलालेख से पूर्व इक्ष्वाकु राजा एहवाल चंतामुला (Ehavala Chantamula) द्वारा चौथी सदी में जारी **नागार्जुनकोंडा शिलालेख को दक्षिण भारत में सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख माना जाता था।**

सप्तमातृका (Saptamatrika)

- हिंदू धर्म में **सात देवियों के एक समूह को सप्तमातृका** कहा जाता है जिसमें ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, चामुण्डा और इंद्राणी शामिल हैं।
- सप्तमातृका की जानकारी कदंब ताम्र प्लेट, प्रारंभिक चालुक्य तथा पूर्वी चालुक्य ताम्र प्लेट से मिलती है।

बोज्जनकोंडा व लिंगलामेत्ता बौद्ध स्थल ★★★

चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश के शंकरम में स्थित **बोज्जनकोंडा** (Bojjannakonda) नामक बौद्ध स्थल पर पत्थर फेंकने की एक पुरानी प्रथा को रोकने में प्रशासन ने सफलता हासिल की है।

प्रमुख बिंदु

- यहाँ के ग्रामीण एक **प्राचीन प्रथा के तहत बोज्जनकोंडा स्थित मानव** के पेट के आकार की एक **आकृति को राक्षस का रूप मानते हुए** इस पर पत्थर फेंकते थे।
- हालाँकि **'इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज'** (INTACH) के हस्तक्षेप के बाद मकर संक्राति के बाद 16 जनवरी को **कनुमा दिवस** (Kanuma day) पर आयोजित होने वाली यह प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है।

बोज्जनकोंडा तथा लिंगलामेत्ता

- बोज्जनकोंडा तथा लिंगलामेत्ता **ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में स्थापित जुड़वाँ बौद्ध मठ** हैं।
- ये बौद्ध स्थल बौद्ध धर्म की तीन शाखाओं (थेरवाद, महायान, वज्रयान) से संबंधित हैं-
  - **थेरवाद:** बुद्ध को एक शिक्षक के रूप में मान्यता।
  - **महायान:** बौद्धधर्म अधिक भक्तिपूर्ण था।
  - **वज्रयान:** जहाँ बौद्ध परंपरा में तंत्र एवं गूढ़ रूप में अधिक विश्वास।
- यह स्थल स्तूपों, पत्थरों को काटकर बनाई गई गुफाओं, ईंट-निर्मित संरचनात्मक आकृतियों, प्रारंभिक ऐतिहासिक मृदभांडों और **पहली शताब्दी ई.पू. के सातवाहन काल के सिक्कों के लिये प्रसिद्ध** है।
- यहाँ स्थित मुख्य स्तूप चट्टान को तराशकर बनाया गया है और फिर इसे ईंटों से ढ़का गया है। यहाँ स्थित पहाड़ियों में **पत्थरों पर बुद्ध की छवियों को उकेरा गया** है।
- यहाँ स्थित **लिंगलामेत्ता में एकाश्म पत्थर से निर्मित स्तूपों** को देखा जा सकता है।

आकर्षक पर्यटन स्थल

- पर्यटक तीन **चौत्यगृह**, अवशेष मंजूषा (Relic Casket), स्तूप और वज्रयान मूर्तिकला को देखने के लिये बड़ी संख्या में इन बौद्ध स्थलों पर आते हैं।
- विशाखापत्तनम थोटलाकोंडा (Thotlakonda), एप्पिकोंडा (Appikonda) और बाविकोंडा (Bavikonda) जैसे बौद्ध स्थलों के लिये भी प्रसिद्ध है।

10 आंतरिक सुरक्षा

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद पर थलसेना **प्रमुख बिपिन रावत** की नियुक्ति की गई।

पृष्ठभूमि

वर्ष 2000 में **कारगिल समीक्षा समिति** की रिपोर्ट और वर्ष 2001 के मंत्रीसमूह की रिपोर्ट में सशस्त्र बलों के एकीकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास की सिफारिश की गई थी। एकीकरण की दिशा में प्रयास के रूप में CDS के पद की घोषणा 15 अगस्त, 2019 को की गई थी।

CDS से संबंधित प्रावधान

- CDS का वेतन और अतिरिक्त सुविधाएँ सेना प्रमुखों के **पद के समान होंगी।**
- किसी सेना प्रमुख को CDS बनाए जाने पर आयु सीमा का नियम बाधा न बने, इसलिये **CDS अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक** अपने पद पर रह सकेगा। वर्तमान में सेना प्रमुख अधिकतम 62 वर्ष या तीन वर्ष के कार्यकाल (दोनों में से जो पहले हो) तक अपने पद पर रह सकता है।
- केंद्र सरकार ने आयु की ऊपरी सीमा के निर्धारण के लिये **सेना के नियम 1954, नौसेना (अनुशासन और विविध प्रावधान) विनियम 1965, नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और विविध विनियम, 1963 तथा वायु सेना विनियम, 1964** में संशोधन किया है।
- CDS, सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद को धारण करने का पात्र नहीं होगा साथ ही उसे सेवानिवृत्ति के **बाद 5 वर्षों तक बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी निजी रोज़गार की अनुमति नहीं** होगी।
- CDS रक्षा मंत्रालय के तहत नवगठित **सैन्य मामलों के विभाग** (Department of Military Affairs-DMA) के सचिव के रूप में कार्य करेगा। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत चार विभाग पहले से ही कार्यरत हैं- **रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और DRDO।**

CDS के नेतृत्व में DMA निम्नलिखित का प्रबंधन करेगा

- संघ की सशस्त्र सेना अर्थात् सेना, नौसेना और वायु सेना।
- रक्षा मंत्रालय के समन्वित मुख्यालय जिनमें सेना, नौसेना, वायु सेना के मुख्यालय शामिल हैं।
- चालू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पूंजीगत प्राप्तियों को छोड़कर सेवाओं के लिये विशिष्ट खरीद।
- एकीकृत संयुक्त योजनाओं और आवश्यकताओं के माध्यम से सैन्य सेवाओं की खरीद, प्रशिक्षण तथा स्टॉफ की नियुक्ति की प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करना।
- सेनाओं में स्वदेश निर्मित उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना।

CDS के कार्य

- CDS सेना के तीनों अंगों के मामले में **रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य** करेगा, लेकिन इसके साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री को अपनी सेनाओं के संबंध में परामर्श देते रहेंगे।
- CDS **रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति** का सदस्य होगा तथा **परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।**
- CDS एकीकृत क्षमता विकास योजना के पश्चात् आगे के कदम के रूप में पंचवर्षीय **'रक्षा पूंजीगत सामान अधिग्रहण योजना'** और दो वर्षीय **वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं को कार्यान्वित** करेगा।
- अपव्यय में कमी करके सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिये तीनों सेनाओं के कामकाज में सुधार करेगा।

आवश्यकता

- कारगिल युद्ध के समय ही भारतीय सेनाओं के मध्य एकीकरण की समस्या सामने आई थी। इस युद्ध की समीक्षा समिति ने भी एकीकरण की समस्या को रेखांकित किया था।
- तीनों सेनाओं के मध्य इस प्रकार का समन्वय वर्तमान समय की **गतिशील सुरक्षा तथा प्रॉक्सी वार** जैसी स्थितियों के मद्देनज़र महत्त्वपूर्ण है।
- CDS के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं के साथ बेहतर समन्वय हेतु निर्णय लेने में तेज़ी आएगी। वर्तमान में विभिन्न देशों के साथ भारत **सैन्य समझौते एवं सैन्य अभ्यासों** का आयोजन करता है।
- भारत की भौगोलिक स्थिति अत्यधिक विविधता वाली है, इसके अतिरिक्त युद्ध के नए प्रकार जैसे- **साइबर युद्ध** आदि की स्थिति में भी सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा।
- साथ ही यह तीनों सेनाओं के बीच एक साझा रणनीति के **साथ एकीकृत सैन्य अभियान** के संचालन को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगा।
- प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स एवं परिचालनों के साथ-साथ खरीद को प्राथमिकता देने में संयुक्त रणनीति अपनाने के लिये समन्वित प्रयास करने से देश लाभान्वित होगा।

नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियाँ ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने **5G** और **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** जैसी नई तकनीकों के कारण उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु एक नए प्रभाग- **नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियाँ (New and Emerging Strategic Technologies-NEST)** की स्थापना की घोषणा की है।

11 संक्षिप्तियाँ

(यूपीएससी एवं राज्य पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाओं पर केंद्रित)

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

- **सक्षम 2020:** केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने **16 जनवरी, 2020 को पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ** (Petroleum Conservation Research Association-PCRA) **के वार्षिक जन केंद्रित ईंधन संरक्षण मेगा अभियान 'सक्षम 2020'** (SAKSHAM 2020) **का शुभारंभ किया। इसका पूरा नाम संरक्षण क्षमता महोत्सव** (Sanrakshan Kshamata Mahotsav-SAKSHAM) **है। इस अभियान का उद्देश्य जन केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से ईंधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है।**

- **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण: केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण** (Central Adoption Resource Authority-CARA) **ने 15 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में अपना 5वाँ वार्षिक दिवस समारोह मनाया। केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है।** केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत 15 जनवरी, 2016 को एक सांविधिक निकाय के रूप में नामित किया गया था। **यह भारतीय अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल एवं उन्हें गोद देने के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।** यह देश भर के विभिन्न बाल देखभाल संस्थानों (Child Care Institutions) में अधिक उम्र और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के पुनर्वास पर भी ज़ोर दे रहा है।

- **रोज़गार संगी एप: छत्तीसगढ़ सरकार ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से रोज़गार संगी एप (Rojgaar Sangi app) लॉन्च किया।** इस एप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre) की मदद से विकसित किया गया है। यह एप छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (Chhattisgarh State Skill Development Authority-CSSDA) द्वारा प्रस्तावित 705 पाठ्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित 7 लाख छात्रों को लाभ पहुँचाएगा।

- **दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों का फोरम: भारत निर्वाचन आयोग ने दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम** (FEMBoSA) **की नई दिल्ली में आयोजित 10वीं वार्षिक बैठक की मेज़बानी की।** भारत निर्वाचन आयोग के **मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को वर्ष 2020 के लिये दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकाय के अध्यक्ष के रूप चुना गया है।** इस अवसर पर 'संस्थागत क्षमता को मज़बूत करना' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में FEMBoSA के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के अलावा कज़ाखस्तान, केन्या, किर्गिज़स्तान, मॉरीशस, ट्यूनीशिया और तीन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों- सियोल स्थित विश्व निर्वाचन निकाय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम (IFES) तथा इंटरनेशनल आईडीईए (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस फोरम का गठन सार्क देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों की मई 2012 में आयोजित बैठक के दौरान किया गया था। इस फोरम का लक्ष्य सार्क के निर्वाचन निकायों के सामान्य हितों के संबंध में आपसी सहयोग को बढ़ाना है। भारत के अलावा इस फोरम के अन्य सात सदस्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के चुनाव प्रबंधन निकाय हैं।

- **राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली:** भारत निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली (Political Parties Registration Tracking Management System-PPRTMS) प्रारंभ की है। **इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदक दलों के पंजीकरण सबंधी आवेदनों की स्थिति का पता लगाया जा सकेगा।** PPRTMS के माध्यम से 1 जनवरी, 2020 से राजनीतिक दल के पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले आवेदक दल अपने आवेदनों की स्थिति का पता लगा सकेंगे। आयोग ने पिछले महीने पंजीकरण के लिये दिशा-निर्देशों में संशोधन किया था। इस प्रणाली से संबंधित नए दिशा-निर्देश 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी हैं। आवेदक को अपने आवेदन में दल/आवेदक का मोबाइल नंबर और ई-मेल पता दर्ज करना होगा ताकि इसके माध्यम से वह अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति के बारे में SMS एवं ई-मेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकें। **राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(A) के प्रावधानों के अंतर्गत होता है।** उपर्युक्त धारा के तहत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकरण करने वाले इच्छुक दल को अपने गठन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

आर्थिक घटनाक्रम

- **म्यूचुअल फंड में निवेश हेतु नए नियम:** हाल ही में **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड** (Securities and Exchange Board of India-SEBI) ने **अल्पवयस्कों** (Minors) के लिये **म्यूचुअल फंड में निवेश के नए नियम** बनाए हैं। सेबी द्वारा जारी नियमों में कहा गया है कि **यदि कोई अल्पवयस्क म्यूचुअल फंड में निवेश करता** है तो **वह निवेश उस अल्पवयस्क के खाते या उसके किसी संयुक्त खाते** से किया जाएगा। निवेश के लिये चेक, डिमांड ड्राफ्ट अथवा किसी अन्य माध्यम से किये गए भुगतान को अल्पवयस्क के खाते या अभिभावक के साथ उसके संयुक्त खाते से ही स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही जब अल्पवयस्क 18 वर्ष का हो जाता है तब उसे बैंक अकाउंट के अद्यतनीकरण हेतु के.वाई.सी. (Know Your Client-KYC) का पूरा

जिस्ट
उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं के लेखों का सार

खंड संयोजन- निधि सिंह

संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

पर्यावरण

संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

स्वास्थ्य और पोषण

राजव्यवस्था एवं समाज

- इंटरनेट शट डाउन
- आईएलओ कन्वेंशन 190
- एसिड बिक्री का विनियमन

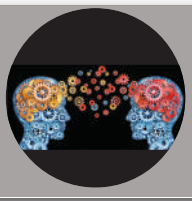

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- 'आभासी मानव' नियॉन
- व्योममित्र अंतरिक्ष में क्या काम करेगी?
- वर्ष 2019 के विज्ञान और तकनीकी संबंधी प्रमुख तथ्य

पर्यावरण

- एशिया में ऊर्जा का भविष्य
- जलवायु परिवर्तन: अतीत, वर्तमान और भविष्य
- वर्ष 2019 में हुए पर्यावरण संबंधी कन्वेंशन/सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा शासन व्यवस्था

- भारत और ईरान
- गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि
- 2020 में भारत की विदेश नीति

एथिक्स

- पृथ्वी को बचाने के लिये हमें आस्था, नैतिकता, विज्ञान और अर्थशास्त्र की ज़रूरत है।

संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

पर्यावरण

परिचय

भारत ने पर्यावरण के मुद्दों पर नेतृत्व और प्रतिबद्धता जताई है। पेरिस समझौते के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के लिये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये विद्युत-वाहनों और वाहन उत्सर्जन मानदंडों को लागू करना, आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कुछ ऐसे मोर्चे हैं जिनमें भारत ने नेतृत्व की मिसाल पेश की है।

कॉप के 25वें सम्मेलन में भारत

- 10 दिसंबर, 2019 को स्पेन के मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क संधि के कॉप-25 सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- भारत ने कार्बन उत्सर्जन में सकल घरेलू उत्पाद के 21 प्रतिशत की कमी की है।
- भारत के प्रधानमंत्री ने पेरिस समझौते में नवीकरणीय ऊर्जा के लिये 175 गीगावाट लक्ष्य की घोषणा की थी। हम 83 गीगावाट हासिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने हाल के संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन में यह लक्ष्य बढ़ाकर 450 गीगावाट कर दिया है।
- भारत में कोयले के उत्पादन पर प्रति टन 6 डॉलर की दर से कार्बन टैक्स लगाया गया है।
- वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक एथेनॉल के इस्तेमाल का लक्ष्य रखा गया है। हमने वाहन उत्सर्जन नियमों के आधार पर भारत मानक-IV से भारत मानक-VI की छलांग लगाई है। 1 अप्रैल, 2020 से सभी वाहन बीएस-VI के अनुपालन में होंगे।
- ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन समूह (बेसिक) के मंत्रियों की बैठक 10 दिसंबर, 2019 को स्पेन के मैड्रिड में कॉप-25 सम्मेलन के दौरान हुई। बैठक की अध्यक्षता चीन के पारिस्थितिकीय और पर्यावरण उप-मंत्री श्री झाओ यिंगमिन ने की।
- 2018 में चीन ने 2005 के मुकाबले कार्बन उत्सर्जन में सकल घरेलू उत्पाद के 45.8 प्रतिशत की कमी की। दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में कार्बन टैक्स लागू किया है और अपनी नवीनतम विद्युत योजना में व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम की घोषणा की है।
- ब्राज़ील राष्ट्रीय स्तर पर समुचित कार्रवाई के तहत 58 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है।
- भारत ने दिल्ली में मरुस्थलीकरण की रोकथाम से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के 14वें सम्मेलन के दौरान 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर अनुत्पादक भूमि को उपयोगी बनाने का लक्ष्य रखा है।
- प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल भूजल योजना (अटल जल) आरंभ की।

जलवायु वार्त्ता में भारत अडिग

- कॉप 25 सम्मेलन की बैठक में जलवायु वित्त से जुड़े जिन अहम मुद्दों को भारत की तरफ से रखा गया उनमें सबसे अहम था कार्बन कारोबार का। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म (सीडीएम) के तहत मौजूदा समय में एक **कार्बन बाज़ार** संचालित है। इस बाज़ार में देशों, संस्थाओं एवं निजी कंपनियों को अपने कार्बन क्रेडिट्स की खरीद-फरोख्त करने की इजाज़त है।
- पूर्व की परंपरागत तकनीक की तुलना में उत्सर्जन की कमी का आकलन कार्बन क्रेडिट्स के रूप में किया जाता है।
- यह बाज़ार शेयर बाज़ार की भाँति संचालित होता है तथा इसके मुताबिक कार्बन क्रेडिट्स की दरें भी घटती-बढ़ती रहती हैं। लेकिन एक जनवरी, 2021 से जब पेरिस समझौते के प्रावधान लागू हो जाएंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा। यह बाज़ार भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगा।
- भारत ने मांग रखी कि पेरिस समझौते के अनुच्छेद छह में कार्बन बाज़ार के मौजूदा स्वरूप को जारी रखा जाए। अनुच्छेद छह में कार्बन बाज़ार की बात तो कही गई है लेकिन उसका तौर-तरीका अभी तय नहीं है।
- **हरित पर्यावरण कोष:** भारत ने हरित पर्यावरण कोष में एक अरब डॉलर सालाना दिये जाने का मुद्दा उठाया। क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधानों के तहत 2020 से प्रत्येक वर्ष विकसित देशों को इस कोष में 100 अरब डॉलर की राशि देनी थी ताकि इस राशि से विकासशील एवं गरीब देशों में जलवायु खतरों से निपटने के लिये क्षमता का विकास किया जा सके। लेकिन इसकी दो फीसदी राशि ही विकसित देशों ने दी है।
- **हरित तकनीकों का मुद्दा:** पूर्व के समझौतों में यह भी तय हुआ है कि विकसित देश हरित तकनीकों का हस्तांतरण करेंगे, लेकिन इस मामले में प्रगति नहीं हो रही है। विकसित देशों के अपने तर्क हैं। वे कहते हैं कि तकनीकें निजी कंपनियों के पास हैं, वे उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं।
- **पेरिस समझौते पर सहमति:** भारत ने बताया कि उसका लक्ष्य पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन की तीव्रता में 35 फीसदी की कमी लाना है। यह लक्ष्य उसे 2030 तक पूरा करना है और इसमें वह 21 फीसदी की कमी हासिल कर चुका है। इसी प्रकार 28 देशों के यूरोपीय संघ ने कहा कि वह 2050 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य के स्तर तक लाकर कार्बन निरपेक्ष बन जाएगा। दरअसल, अमेरिका की संघीय सरकार के इनकार के बावजूद वहाँ की राज्य सरकारों, नगर प्रशासन और गैर-सरकारी संगठनों, कंपनियों आदि के द्वारा इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार पेरिस समझौते के क्रियान्वयन को लेकर सक्रिय टॉप-5 देशों की सूची में भारत को भी शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। दूसरे, एक अन्य रिपोर्ट में जलवायु सजग शीर्ष 10 देशों में भारत को नवाँ स्थान मिला है।

संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

स्वास्थ्य और पोषण

परिचय

- 'स्वास्थ्य' का अर्थ सिर्फ बीमारियों से मुक्त रहना नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवनशैली से है। एक स्वस्थ जीवन के साथ-साथ स्वस्थ जीवनशैली हेतु पर्याप्त जानकारी और सुविधाएँ प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। और इसे सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी सरकार पर है।
- भारत सरकार ने इस विषय पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और सरकार स्वास्थ्य देखभाल के चार प्रमुख आयामों पर कार्य कर रही है- रोगनिरोधी स्वास्थ्य देखभाल, किफायती स्वास्थ्य सुविधाएँ, आपूर्ति को बेहतर बनाना और मिशन मोड में कार्यान्वयन।

स्वास्थ्य और पोषण : देश की प्रगति के पहिये

परिचय

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में देश के प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अभिनिर्धारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों से लिया गया है और इसमें स्वास्थ्य की सुरक्षा शामिल है।
- संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार से संबंधित सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 25 में भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसे जीवन-स्तर का अधिकार है जो उसके परिवार और स्वयं उस व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण के लिये पर्याप्त हो। इसमें भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाएँ शामिल हैं।

नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

- स्वास्थ्य और पोषण को राष्ट्रीय विकास की पहली आवश्यकता मानते हुए 15 मार्च, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंज़ूरी दी गई।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में जन-स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को समयबद्ध आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा समय में यह खर्च जीडीपी का केवल 1.15 प्रतिशत है।
- इसमें जीवन-प्रत्याशा मौजूदा 67.5 वर्ष से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 70 वर्ष करने की बात कही गई है। इसी तरह राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर से वर्ष 2025 तक घटाकर 2.1 प्रतिशत पर लाने की योजना है। इस नीति में वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाकर 23 करने, नवजात शिशु मृत्यु दर वर्ष 2019 तक घटाकर 28 तक लाने तथा मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) के वर्तमान स्तर को वर्ष 2020 तक घटाकर 100 तक लाने पर ज़ोर दिया गया है।
- वर्ष 2025 तक नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 तक लाने और मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को घटाकर एक अंक में लाने की बात कही गई है। वर्ष 2017 तक कालाजार तथा वर्ष 2017 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने और इस स्थिति को बनाए रखने की बात भी स्वास्थ्य नीति में शामिल है।
- वर्ष 2025 तक दृष्टिहीनता के मामलों को घटाकर 0.25/1000 करने तथा ऐसे रोगियों की संख्या मौजूदा-स्तर से घटाकर एक तिहाई करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें हृदयवाहिका रोग, कैंसर, मधुमेह और श्वास रोग से होने वाली अकाल मौतों को वर्ष 2025 तक घटाकर 25 प्रतिशत करने और गैर-संचारी रोगों की उभरती चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में 50 प्रतिशत वृद्धि करने, एक साल तक की आयु के 90 प्रतिशत से अधिक नवजात शिशुओं के पूर्ण टीकाकरण और राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीयस्तर पर परिवार नियोजन से संबंधित 90 प्रतिशत आवश्यकताएँ पूरी करने का लक्ष्य है। इसी तरह, तंबाकू के इस्तेमाल के मौजूदा-स्तर को वर्ष 2020 तक 15 प्रतिशत और वर्ष 2025 तक 30 प्रतिशत घटाने पर ज़ोर दिया गया है।

आयुष्मान भारत योजना

- स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्त्वाकांक्षी योजना- 'आयुष्मान भारत' के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में दो प्रमुख पहलें की गई हैं। इनमें से एक पहल, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र खोलने से संबंधित है, तो दूसरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (एनएचपीएम) के बारे में है।
- योजना की शुरुआत के प्रथम वर्ष में ही करीब 47 लाख लोगों को 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के अंतर्गत भारतीय मुद्रा में 75 हज़ार मिलियन का इलाज उपलब्ध कराया गया। 10 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को लाभार्थी कार्ड जारी किये जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पूरे देश में 18 हज़ार 100 अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है। इनमें से 53 प्रतिशत अस्पताल निजी क्षेत्र के बहु-विशेषज्ञता (मल्टी-स्पेशियलिटी) अस्पताल हैं और 62 प्रतिशत इलाज की सुविधा इन्हीं अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई है।

अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ

- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना:** देश के विभिन्न भागों में विश्वसनीय और किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन दूर करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं से वंचित या कम सुविधा वाले राज्यों में चिकित्सा शिक्षा के प्रसार पर बल दिया जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स

राजव्यवस्था एवं समाज

इंटरनेट शट डाउन

संदर्भ

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इंटरनेट के माध्यम से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार और व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है। यह निर्णय कश्मीर में पिछले पाँच महीने से इंटरनेट पर जारी रोक की पृष्ठभूमि में आया था।

इस निर्णय में इंटरनेट बंद किये जाने के बारे में तर्क

- हालाँकि न्यायालय ने अपने निर्णय में यह नहीं कहा है कि इंटरनेट तक पहुँच एक मौलिक अधिकार है, लेकिन उसने कहा है कि एक माध्यम के रूप में इंटरनेट का उपयोग अन्य मौलिक अधिकारों का उपयोग करने के लिये किया जाता है।
- न्यायालय ने कहा, "इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति ने वर्तमान में प्रासंगिकता हासिल की है और यह सूचना के प्रसार का एक प्रमुख साधन है।" न्यायालय ने अपनी टिप्पणियों में अनिवार्य रूप से दिशा-निर्देश दिये कि इंटरनेट पर मनमाने ढंग से रोक नहीं लगाई जा सकती है और इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने वाले आदेशों में यह बताना ज़रूरी होगा कि कार्रवाई कैसे उचित थी तथा कानून और व्यवस्था के लिये आसन्न खतरे के अनुपात में थी।

इंटरनेट सेवाओं का निलंबन कैसे?

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 और टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 तीन ऐसे कानून हैं जो इंटरनेट सेवाओं के निलंबन से संबंधित हैं।
- **धारा 144:** 2017 से पहले, इंटरनेट सेवाएँ निलंबित करने के आदेश सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किये जाते थे। औपनिवेशिक युग के इस कानून को बनाए रखा गया है जो ज़िला मजिस्ट्रेट, सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस बारे में विशेष रूप से शक्तियाँ प्राप्त किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को खतरे या उपद्रव की आशंका के तत्काल मामलों को रोकने और उनका समाधान करने के लिये आदेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।

इंटरनेट बंद करना- भारत में यह कैसे, कब और कहाँ हो रहा है?

- मोबाइल इंटरनेट को निलंबित करने के लिये धारा 144 के उपयोग को 2015 में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, लेकिन न्यायालय ने मजिस्ट्रेट द्वारा इस तरह के आदेश जारी करने की शक्ति को बरकरार रखा।
- **निलंबन संबंधी नियम:** केंद्र सरकार ने इंटरनेट के निलंबन के विनियमन के लिये 2017 में टेलीग्राफ एक्ट के तहत दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (लोक आपात स्थिति या लोक सुरक्षा) नियम अधिसूचित किये। ये नियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, जो "भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों" में संदेशों (Messages) के इंटर्सेप्शन के बारे में हैं।
- 2017 के नियमों के बावजूद, सरकार ने अक्सर धारा 144 के तहत व्यापक शक्तियों का उपयोग किया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध के मद्देनज़र, यूपी के संभल में ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 के तहत इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया। 20 जून, 2019 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24-परगना में ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट, केबल सेवाओं और ब्रॉडबैंड को बंद कर दिया गया।
- सरकार ने तर्क दिया था कि "अस्थिर इतिहास, बाहरी आक्रामकता, नापाक अलगाववादी गतिविधियों और राजनीतिक नेताओं द्वारा दिये गए भड़काऊ बयानों के बारे में पब्लिक डोमेन में उपलब्ध भारी सामग्री ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी" कि कश्मीर में इंटरनेट सेवाएँ निलंबित करने के लिये धारा 144 के तहत आदेश पारित करना ज़रूरी हो गया था।

दृष्टि इनपुट: राइट टू एक्सेस इंटरनेट

- 'फाहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य' मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के एक भाग के रूप में इंटरनेट तक लोगों की पहुँच के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है।
- राइट टू एक्सेस इंटरनेट से तात्पर्य सभी लोगों की इंटरनेट तक पहुँच की सुनिश्चितता और उन्हें अपने अधिकारों, खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अन्य मौलिक मानवाधिकारों के उपयोग की स्वतंत्रता प्रदान करना है।
- सबू मैथ्यू जॉर्ज (Sabu Mathew George) केस, 2018 के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एक्सेस इंटरनेट को एक मूल मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी बशर्ते जब तक इसका उपयोग अवैध सीमा तक न किया गया हो।
- इसके अलावा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38(2) और 39 के अंतर्गत भी राइट टू एक्सेस इंटरनेट को अप्रत्यक्ष रूप से रेखांकित करता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका का चौथा संविधान संशोधन नागरिकों के निजता के अधिकार की रक्षा करता है और इसमें राज्य के अनुचित हस्तक्षेप से बचाता है।
- यूनाइटेड किंगडम का मानवाधिकार अधिनियम नागरिकों की निजता, पारिवारिक जीवन, घर और संचार की रक्षा करता है।
- डिजिटल असमानता (Digital Inequality) का संबंध सूचना, गरीबी, बुनियादी ढाँचे की कमी और डिजिटल साक्षरता में कमी के कारण लोगों द्वारा डिजिटल और सूचना तकनीकी (Technology) के उपयोग के क्षेत्र में असमानता से है।
- डिजिटल कौशल (Digital Skill) को यूनेस्को (UNESCO) के सतत् विकास लक्ष्य संख्या-4 (SDG-4) में स्थान दिया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

'आभासी मानव' नियॉन

संदर्भ

- सैमसंग के स्टार लैब्स (Star Labs) की पहली परियोजना 'नियॉन' को दुनिया का पहला कृत्रिम मानव (Artificial Human) कहा जा रहा है। नियॉन वास्तविक मनुष्यों की तरह दिखते और व्यवहार करते हैं और ये स्मृतियों और भावनाओं को विकसित कर सकते हैं- हालाँकि वे एक 4K डिस्प्ले के पीछे से ऐसा करेंगे। इन्हें हम मानव इंटरफेस (Human Interface) कह सकते हैं।
- स्टार लैब्स सैमसंग टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड रिसर्च लैब्स (Samsung Technology & Advanced Research Labs) कोरिया की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा वित्तपोषित एक स्वतंत्र परियोजना है।

नियॉन क्या हैं?

- कंपनी का कहना है कि नियॉन गणनाओं के माध्यम से निर्मित आभासी मानव हैं- यह शब्द NEO (नया) + Human (मानव) से मिलकर बना है। फिलहाल आभासी मानव (Virtual Human) उनके सृजनकर्त्ताओं द्वारा मैन्युअल रूप से नियंत्रित किये जाने पर भावनाएँ प्रदर्शित कर सकते हैं।
- लेकिन नियॉन को इतना बुद्धिमान बनाने का विचार है कि वे पूरी तरह से स्वायत्त हों, भावनाएँ प्रदर्शित कर सकें, कौशल सीख सकें, स्मृतियों का सृजन कर सकें और अपने दम पर बुद्धिमान बन सकें।

नियॉन कैसे काम करते हैं?

- आभासी मानव मुख्य रूप से दो प्रौद्योगिकियों पर आधारित है। सबसे पहले, यह सैमसंग की कोर (CORE) R3 प्रौद्योगिकी पर आधारित है, इसका तात्पर्य वास्तविकता (Reality), रियल टाइम (Real Time) और प्रतिक्रिया (Response) है। इस तकनीक के द्वारा नियॉन पल भर में प्रतिक्रिया देने में समर्थ है।
- CORE R3, "बिहेवियरल न्यूरल नेटवर्क्स, इवोल्यूशनरी जेनरेटिव इंटेलिजेंस एंड कम्प्यूटेशनल रियलिटी" के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और उसे इस बारे में गहन रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है कि मनुष्य कैसे देखते हैं, व्यवहार करते हैं और बातचीत करते हैं।
- लेकिन ये एक रेंडिशन इंजन (Rendition Engine) की तरह है जो गणितीय मॉडल को वास्तविक मानव की तरह दिखने के लिये परिवर्तित करता है। इसके द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया में मिलीसेकंड से भी कम समय लगता है। कोर R3 प्रौद्योगिकी भाषा किट जैसी अन्य डोमेन-विशिष्ट और मूल्यवर्धित सेवाओं के लिये उपयोग में लाई जा सकती है।
- अगला चरण स्पेक्ट्रा (SPECTRA) होगा, जो 'बुद्धि, ज्ञानार्जन, भावनाओं और स्मृति के स्पेक्ट्रम' के साथ कोर R3 का अनुपूरक होगा। लेकिन स्पेक्ट्रा अभी भी विकास की प्रक्रिया में है और इस वर्ष के अंत में नियॉनवर्ल्ड 2020 (NEONWORLD 2020) से पहले इसके आने की संभावना नहीं है।
- "कोर R3 फ्रंट-एंड (front-end) एक रियलिटी इंजन है जो वास्तविक अभिव्यक्ति देने में सक्षम है। अभी नियॉन को इस बारे में नहीं पता है कि उसे कब मुसकराना है।"

दृष्टि इनपुट: वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग

- हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) द्वारा जारी किये गए वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग में भारत को 44वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- इस रैंकिंग की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी।
- इस रैंकिंग में मुख्य रूप से तीन प्रमुख कारकों- ज्ञान, प्रौद्योगिकी और भविष्य की तैयारी का मूल्यांकन किया जाता है।
- रैंकिंग में भारत को वर्ष 2018 में 48वाँ स्थान प्राप्त था।
- रैंकिंग में विश्व के शीर्ष देशों की सूची में क्रमशः अमेरिका पहले, सिंगापुर दूसरे, स्वीडन तीसरे, डेनमार्क चौथे तथा स्विटज़रलैंड पाँचवे स्थान पर है।

नियॉन का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

- बैंक में आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, रेस्तरां में आपका स्वागत करेंगे या रात-बिरात टेलीविज़न पर ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ेंगे।
- नियॉन एक स्वत्वधारी प्रौद्योगिकी (Proprietary Technology) द्वारा संचालित है जिसे कोर R3 – "वास्तविकता (Reality), रियल टाइम (Real Time) और प्रतिक्रिया (Response)" कहा जाता है।

नियॉन वर्चुअल असिस्टेंट से अलग कैसे हैं?

- वर्चुअल असिस्टेंट (Virtual Assistants) अब उन सभी डेटा से सीखते हैं जिनके साथ उन्हें जोड़ा जाता है। नियॉन जो जानते हैं और सीखते हैं, उस तक सीमित रहेंगे। उनका झुकाव संभावित रूप से उस व्यक्ति और शायद उसके मित्र तक सीमित हो सकता है जिसे वे सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, लेकिन पूरे इंटरनेट के लिये नहीं।
- स्टार लैब्स का कहना है कि "डीपफेक (deepfake कृत्रिम बुद्धि आधारित प्रौद्योगिकी है) के विपरीत, कोर R3 किसी भी दृश्य, वीडियो या अनुक्रम (Sequence) में हेरफेर नहीं करती है, इसकी बजाय वास्तविक समय में अद्वितीय व्यवहारों और अंत:क्रियाओं का सृजन करती है। कोर R3 नई वास्तविकताओं का सृजन करती है।"

पर्यावरण

एशिया में ऊर्जा का भविष्य

संदर्भ

- हाल ही में अबू धाबी ने एक सौर परियोजना का निर्माण करने के लिये चीन और जापान की कंपनियों के साथ साझेदारी की है। वर्तमान परिदृश्य की यदि बात करें तो एशिया और अन्य राष्ट्रों की तुलना में चीन में सबसे अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और यहाँ विभिन्न उद्योगों में जीवाश्म ईंधन के स्थान पर नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा ईंधन का अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है।
- चीन और भारत सहित एशिया में वर्ष 2040 तक वैश्विक ऊर्जा की मांग में तकरीबन 43% तक की वृद्धि होने, और उस वर्ष तक इस क्षेत्र की मांग में 50% से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है।

प्रमुख बिंदु

- चीन जैसे देश पहले से ही गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के सबसे प्रमुख आपूर्तिकर्त्ताओं में शामिल हैं। 2017 तक, चीन के पास दुनिया के सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के 72% उत्पादन का स्वामित्व था; इसकी तुलना में, अमेरिका के पास 1% और यूरोप के पास 2% है। आठ शीर्ष निर्माता देशों में से छह एशिया में हैं।
- यदि जलविद्युत को शामिल न किया जाए, तो चीन के पास दुनिया की नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता का एक तिहाई हिस्सा है; यूरोपीय संघ के पास एक चौथाई से थोड़ा अधिक है; और अमेरिका के पास 14% की हिस्सेदारी है। जलविद्युत के उत्पादन में भी चीन अग्रणी है।
- चीन लिथियम आयन बैटरी के लिये दुनिया की उत्पादन क्षमता का कम-से-कम दो-तिहाई उत्पादन करता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), मोबाइल फोन और लैपटॉप तथा कंप्यूटर आदि में किया जाता है।
- चीन लिथियम आयन बैटरियों के उत्पादन में उपयोग होने वाले प्राथमिक कच्चे माल लिथियम का तीसरा सबसे बड़ा खनिक है। लिथियम के बढ़ते आर्थिक महत्त्व के कारण उसे प्राय: सफेद पेट्रोलियम कहा जाता है।

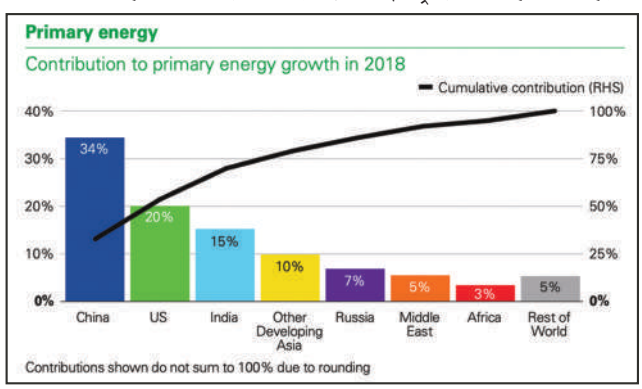

परिवर्तन संबंधी तथ्य

- स्विट्ज़रलैंड की ऊर्जा और कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी विटोल (Vitol) के मुताबिक, दुनिया भर में तेल की मांग 2034 के आसपास सर्वोच्च स्तर पर पहुँच जाएगी।
- दुनिया भर में विद्युतीकरण की दर में वृद्धि जारी रहेगी और 2030 तक एशिया में 100% कवरेज की उम्मीद है। इस बढ़ती मांग को जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न बिजली की बजाय नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा द्वारा पूरा किया जा सकता है।
- इस मांग को विद्युत उत्पादन क्षमता के विकेंद्रीकरण के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है, जैसे कि मलावी और बांग्लादेश जैसे देशों में हाल ही में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएँ शुरू की गई हैं जहाँ किसान और गाँव अपने स्वयं के लिये बिजली की व्यवस्था करने के लिये सौर पैनलों एवं छोटे जनरेटरों का उपयोग करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक वायु प्रदूषण और वैश्विक तापवृद्धि के कारण सामाजिक लागत जैसी अमूल्य बाह्यताओं के परिणामस्वरूप कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन पर 2017 में कुल 5.2 ट्रिलियन डॉलर की कर-पश्चात् सब्सिडी दी गई है।

निष्कर्ष

परिवर्तन की गति चाहे जो हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पहले से ही हो रहा है। इसीलिये संयुक्त अरब अमीरात (जिसका सबसे बड़ा शहर अबू धाबी है) जैसा देश विश्व का आठवाँ सबसे बड़ा तेल उत्पादक होने के बावजूद सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा सुविधाओं का निर्माण कर रहा है और एशियाई भागीदारों के साथ परिवर्तन कर रहा है।

Source: WEF

जलवायु परिवर्तन: अतीत, वर्तमान और भविष्य

2019

- स्पेन में 2 से 13 दिसंबर तक आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन विभिन्न देशों के लिये पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अपने उत्सर्जन के लक्ष्यों में संशोधन करने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर था।
- संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के कुल 197 सदस्य देश मैड्रिड में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (सीओपी) में भाग लेंगे। इस सम्मेलन को कॉप 25 नाम दिया गया है।
- दुनिया की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं या जी20 में से केवल छ: देश, 78 प्रतिशत वैश्विक उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार हैं, पेरिस समझौता एक स्पष्ट तापमान लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला कानूनी दस्तावेज़ था। यह देशों को पूर्व-औद्योगिक स्तर से औसत वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे रखने के लिये प्रेरित करता है और उन्हें इसे 1.5°C तक सीमित करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा शासन व्यवस्था

भारत और ईरान

संदर्भ

- 4 जनवरी, 2020 को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बगदाद में एक ड्रोन हमले की ज़िम्मेदारी लेते हुए प्रेस बयान जारी किया। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कुद्स (Quds) फोर्स के प्रमुख श्री कासिम सुलेमानी को मार दिया गया।
- इसी हमले में इराक में ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन के डिप्टी कमांडर अबु महदी अल-मुहंदिस को भी मार दिया गया, उसे क्रांतिकारियों को जुटाने के लिये जाना जाता था। कासिम को मध्य-पूर्व में ईरान एवं दुनिया के शिया समुदाय के धार्मिक और राजनीतिक नेता अयातुल्ला खोमैनी के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता था।

भारत की चिंता

- अमेरिका और ईरान के बीच अचानक इस सीधे टकराव ने भारत को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। भारत के लंबे समय से ईरान के साथ बहुत मज़बूत संबंध रहे हैं। हाल ही में, भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के निर्माण में भी भारी निवेश किया है। यह बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का एक रणनीतिक जवाब है, जो उससे 100 किलोमीटर दूर है और चीन द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- शिया मतावलंबी ईरान का खाड़ी के अन्य सुन्नी राजतंत्रों के साथ विरोध रहा है और इस संबंध में सऊदी अरब प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है जिससे खाड़ी देशों में भारत की स्थिति और अधिक अनिश्चित हो गई है।
- शीतयुद्ध के दौर में भारत सोवियत संघ का सहयोगी था जबकि खाड़ी देश संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थक थे। पिछले एक दशक से भारत कूटनीतिक दृष्टि से खाड़ी देशों में तथा खाड़ी देशों और ईरान के बीच की स्थिति में अपनी स्थिति जानने के लिये बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है।

निष्कर्ष

इस हमले ने इस क्षेत्र की भूराजनीति को और बदल दिया है और भारत अब तटस्थ या निष्क्रिय बने रहने का विकल्प नहीं चुन सकता है। भारत को न केवल अपने हितों की रक्षा के लिये बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय भूमिका निभाने के लिये एक स्पष्ट विदेश नीति तैयार करने और किसी एक गठबंधन का चयन करने की आवश्यकता है।

Source: Times of India

गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि

संदर्भ

- प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के नेताओं और 2019 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के सभी नेताओं को आमंत्रित किया था।
- वर्ष 2020 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- श्री बोल्सोनारो शस्त्र रखने के समर्थक हैं, समलैंगिकों के विरोधी हैं और दक्षिणपंथी पूर्व आर्मी कैप्टन हैं जो 2018 में सत्ता में आए थे। उनके प्रशासन के निर्णायक पहलू अमेरिका की ओर मज़बूत झुकाव और अमेज़न वर्षावनों को प्रभावित करने वाली हानिकारक नीतियाँ रही हैं।
- ब्राज़ील को एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया है जो जापान, इज़राइल और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिका के निकट सहयोगियों के पास है। श्री बोल्सोनारो ने वाशिंगटन का अनुसरण करते हुए अपने इज़राइल दूतावास को येरुशलम स्थानांतरित कर दिया है। इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच इस शहर को लेकर विवाद है।
- अमेज़न डेल्टा के बारे में उनकी नीति विनियमन और प्रवर्तन को वापस लेने की रही है जिससे कृषि-व्यवसाय, खनन और पशुपालन के लिये स्वदेशी लोगों की भूमि के उपयोग को आसान बनाया जा सके।
- उनके राष्ट्रपति-कार्यकाल में मारे गए अश्वेत और स्वदेशी लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। उनकी घरेलू स्वीकृति रेटिंग (Domestic Approval Rating) केवल 30% है।

ब्रिक्स समूह के भीतर असंतुलन

- राष्ट्रपति के रूप में श्री बोल्सोनारो के खराब रिकॉर्ड के अलावा एक बड़ा सवाल ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह 'ब्रिक्स (BRICS) के भविष्य से जुड़ा है। इसकी स्थापना बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ने के एक कदम के रूप में की गई थी; इसलिये इसका विस्तार तीन महाद्वीपों और दोनों गोलार्द्धों में है।
- ब्रिक्स देशों का वैश्विक उत्पादन में लगभग एक-तिहाई योगदान है, लेकिन जीडीपी तालिका और विकास दर पर एक नज़र डालने पर इस समूह की कमज़ोरियाँ दिखाई पड़ेंगी: जीडीपी के मामले में चीन दूसरे स्थान पर है; भारत पाँचवे; ब्राज़ील नौवें; रूस 11वें और दक्षिण अफ्रीका 35वें स्थान पर है।
- विकास दर के मामले में चीन 6% पर है; भारत 4.5%, रूस 1.7%, ब्राज़ील 1.2% और दक्षिण अफ्रीका 0.1% पर है। हाल के वर्षों में ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से पीछे रहे हैं।
- लेकिन इन पाँचों देशों के नेता अभी भी इस समूह को एकजुट रखने को फायदेमंद मानते हैं। इस समूह के प्रत्येक देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति अलग-अलग है तथा घरेलू और बाह्य मुद्दों का अलग-अलग बोझ है।

एथिक्स

पृथ्वी को बचाने के लिये हमें आस्था, नैतिकता, विज्ञान और अर्थशास्त्र की ज़रूरत है।

- जैसे-जैसे विश्व जलवायु परिवर्तन के संकटपूर्ण मोड़ पर पहुँच रहा है, अधिकांश लोग अंततः आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता हेतु जागरूक हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये सामान्य नीतियों के साथ एक नैतिक दृष्टि, ठोस विज्ञान और उम्दा आर्थिक नीतियों की आवश्यकता है। इन तीनों में से किसी एक की अनुपस्थिति भी हमारे प्रयास को असफल बना देगी।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक नैतिक दृष्टि की ज़रूरत है, जो गरीबों और भावी पीढ़ियों पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले गंभीर परिणामों पर विचार करे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा प्रभाव गरीबों पर होगा, अमीरों पर नहीं। जबकि अमीरों के धन से ही वैश्विक जलवायु परिवर्तन के परिणामों का उपशमन किया जा सकता है। एक उदारवादी दृष्टि, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना लाभ चाहता है, से किसी का लाभ नहीं होगा। साझा बेहतरी के लिये साझा प्रयास और साझा त्याग की आवश्यकता है।

नैतिक दृष्टि

- जलवायु सम्मेलन के लिये अपने वीडियो संदेश में पोप फ्राँसिस ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन की समस्या नैतिकता, समता और सामाजिक न्याय के मुद्दों से संबंधित है। हमें ईमानदारी, उत्तरदायित्व और साहस के साथ अपनी बुद्धिमत्ता को दूसरे प्रकार की प्रगति की सेवा में लगाना होगा। ऐसी प्रगति, जो स्वास्थ्यकर हो, अधिक मानवीय हो, अधिक सामाजिक हो, अधिक सत्यनिष्ठ हो, मानव मात्र की सेवा में अर्थव्यवस्था को प्रतिष्ठापित करने, शांति निर्माण और पर्यावरण की सुरक्षा करने में सक्षम हो।
- विश्वव्यापी छात्र हड़ताल की नेता ग्रेटा थनबर्ग ने यूएन में एकत्रित नेताओं को संबोधित करते हुए इसी नैतिक बोध का प्रतिनिधित्व किया, जब उन्होंने कहा, "अगर आपने वास्तव में स्थिति को समझा और तब भी कार्रवाई करने से चूके, तो फिर आप बुरे होंगे और मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करती हूँ।"
- किंतु जलवायु संकट को न केवल नैतिक दृष्टि की ज़रूरत है बल्कि एक धार्मिक दृष्टि की भी आवश्यकता है। पूरे मानव इतिहास के दौरान धर्म ने, कई बार बुरी किंतु कई बार अच्छी, असाधारण चीज़ें करने के लिये लोगों को प्रेरित किया है। यूरोप के मुख्य गिरजाघरों का निर्माण उन लोगों द्वारा आरंभ किया गया जो उन्हें कभी पूरा होते नहीं देख पाए। आप बिना धार्मिक प्रेरणा के लोगों को ऐसे भवन के निर्माण कार्य के लिये फावड़ा उठाने हेतु कैसे प्रेरित करेंगे, जो शताब्दियों तक पूरा नहीं होगा?

धार्मिक दृष्टि

- पोप फ्राँसिस, ऑर्थोडोक्स ईसाई चर्च के सार्वदेशिक पितामह बार्थोलोमीऊ, दलाई लामा और अन्य धार्मिक नेता अपने अनुयायियों को एक ऐसी धार्मिक दृष्टि, जो जलवायु परिवर्तन का सामना करने को प्रतिबद्ध है, के साथ नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका संदेश है कि अगर पृथ्वी ईश्वर की सर्जना है, तो इसका गलत फायदा उठाना ईश्वर के विरुद्ध अपराध है। अगर पृथ्वी एक ऐसी प्रतिमा है जहाँ हम ईश्वर का रूप देख सकते हैं, तो इसका विरूपण करना पाप है। अगर हम सब ईश्वर की संतान हैं तो हमें एक-दूसरे को नुकसान से अवश्य बचाना चाहिये। अगर आप वैश्विक तापवृद्धि में योगदान देते हैं तो आपको अवश्य नरक की आग में झोंका जाएगा।

वैज्ञानिक दृष्टि

- ठोस विज्ञान के बिना एक नैतिक और धार्मिक दृष्टि अपर्याप्त है। विज्ञान हमें बताता है कि वैश्विक तापवृद्धि का क्या कारण है- मानवीय गतिविधियों द्वारा सृजित CO_2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसें। विज्ञान हमें बताता है कि वैश्विक तापवृद्धि का क्या प्रभाव होगा- हिमानियों का पिघलना और बढ़ता समुद्री जल स्तर, पिघलते ग्लेशियर और मौसम प्रणाली एवं जलापूर्ति में अवरोध, कृषि में अवरोध तथा पशुओं, पादपों और कीटों की करोड़ों प्रजातियों का खात्मा।
- संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम संगठन द्वारा संकलित जलवायु परिवर्तन पर अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, 'व्यापक और दीर्घ-प्रभावी गर्म हवाएँ (लू), अग्नि तथा विनाशकारी घटनाओं ने सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव डाला है।'
- विज्ञान न केवल हमें यह बताता है कि समस्याएँ कितनी गंभीर हैं, बल्कि हमें इन समस्याओं को ठीक करने की राह भी दिखाता है। हम कैसे यात्रा करते हैं, कैसे खेती करते हैं और क्या उपभोग करते हैं, इनमें परिवर्तन करके बदलाव लाया जा सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान ऐसे नए समाधान भी खोज सकता है, जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं है।

आर्थिक नीतियाँ

- नैतिकता और विज्ञान पर्याप्त नहीं होंगे अगर विश्व की अर्थव्यवस्था गलत दिशा में जा रही हो। हमें बेहतर आर्थिक नीतियों की ज़रूरत है। कर और विनियामक नीतियाँ अब भी कार्बन-आधारित अर्थव्यवस्था को सब्सिडी प्रदान करती हैं। तेल, गैस और कोयला लॉबी इन सब्सिडियों की संरक्षा करती है जो जीवाश्म ईंधनों की खपत को प्रोत्साहित करती हैं। अर्थशास्त्री हमें बताते हैं कि वैश्विक तापवृद्धि को धीमा करने की श्रेष्ठ राह कार्बन पर कर लगाना है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संकेत भेजेगा कि जीवाश्म ईंधनों की खपत कम करना हमारे वित्तीय हित में है। सुनियोजित कार्बन कर वास्तव में कार्बन उत्सर्जन कम करने के साथ है। यह नौकरियों और सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी कर सकता है।
- अगर हमें अपनी भावी पीढ़ियों और पृथ्वी को तबाही से बचाना है तो एक नैतिक दृष्टि, ठोस विज्ञान और बेहतर आर्थिक नीतियाँ आवश्यक हैं।

Source: Santa Clara University

फैक्टशीट

महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित

वैश्विक असमानता पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट-2020

- अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन ऑक्सफैम (Oxfam) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 'टाइम टू केयर: अनपेड एंड अंडरपेड केयर वर्क एंड ग्लोबल इनइक्वलिटी क्राइसिस (Time to Care: Unpaid and Underpaid Care Work and the Global Inequality Crisis)' के अनुसार, भारत की शीर्ष 10% जनसंख्या के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 74.3% है।
- भारत की शीर्ष 1% जनसंख्या कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 42.5% रखती है जबकि निचली 50% जनसंख्या के पास राष्ट्रीय संपत्ति का केवल 2.8% है।
- भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास निचली 70% आबादी अर्थात् 953 मिलियन लोगों से चार गुना अधिक संपत्ति है।
- निचली 90% जनसंख्या के पास राष्ट्रीय संपत्ति का केवल 25.7% है। भारत के 9 खरबपतियों की संपत्ति निचली 50% जनसंख्या की संपत्ति के बराबर है।

वैश्विक स्तर पर असमानता

- वर्ष 2019 में दुनिया में 2,153 लोग अरबपति थे, उनके पास 4.6 बिलियन लोगों से अधिक संपत्ति है।
- दुनिया के 22 सबसे अमीर पुरुषों के पास अफ्रीका की सभी महिलाओं की संपत्ति की तुलना में अधिक संपत्ति है।
- दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास 6.9 बिलियन लोगों की तुलना में दोगुनी से अधिक संपत्ति है।
- यदि प्रत्येक व्यक्ति 100 डॉलर के नोटों में जमा किये गए अपने धन पर बैठे, तो ज़्यादातर लोग फर्श पर बैठे होंगे; एक अमीर देश के मध्यम वर्ग का व्यक्ति कुर्सी की ऊँचाई पर होगा; और दुनिया के दो सबसे अमीर आदमी बाह्य अंतरिक्ष में बैठे नज़र आएंगे।
- अगले 10 वर्षों में सबसे अमीर 1% लोगों की संपत्ति पर अतिरिक्त 0.5% कर लगाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुज़ुर्ग देखभाल आदि क्षेत्रों में 117 मिलियन लोगों के लिये नौकरियों का सृजन किया जा सकता है।
- वर्ष 2011 से 2017 के बीच जी-7 देशों में औसत मज़दूरी 3% बढ़ी, जबकि अमीर शेयरधारकों के लाभांश में 31% की वृद्धि देखी गई है।

पुरुषों की तुलना में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति

- वैश्विक स्तर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की चरम गरीबी दर 4% अधिक है। महिलाओं की चरम उत्पादक और प्रजनन आयु के दौरान यह अंतर 22% तक बढ़ जाता है; यही कारण है कि 25-34 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक 100 पुरुषों की तुलना में उसी आयु वर्ग की 122 महिलाएँ बेहद गरीब परिवारों में रहती हैं, इसका एक बड़ा कारण बच्चों की देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियाँ हैं।
- वैश्विक स्तर पर 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के अवैतनिक देखभाल कार्य का अनुमानित न्यूनतम वार्षिक मौद्रिक मूल्य 10.8 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है - यह दुनिया के तकनीकी उद्योग के आकार का तीन गुना है।
- दुनिया भर में छह प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कार्यशील आयु की 42 प्रतिशत महिलाएँ अवैतनिक देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियों के कारण वैतनिक श्रम बल से बाहर रह जाती हैं।
- दुनिया भर में अनुमानित 67 मिलियन घरेलू श्रमिकों में से 80% महिलाएँ हैं। अनुमानित रूप से 90% घरेलू श्रमिकों की मातृत्व संरक्षण और लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा तक कोई पहुँच नहीं है।

भारत में महिला असमानता

- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप 2020 के अनुसार भारत का स्थान 153 देशों में 112वाँ रहा है।
- वर्ल्ड बैंक के अनुसार महिला श्रम सहभागिता दर (FLFPR) में भारत केवल 9 देशों से ऊपर है, ये देश हैं- इजिप्ट, मोरक्को, सोमालिया, ईरान, अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक, सीरिया तथा यमन।
- एनएसएसओ द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार 2017-18 में श्रम बल में महिलाओं की सहभागिता केवल 23.3% थी जो दर्शाता है कि 15 वर्ष से ऊपर की महिलाओं में से 4 में से 3 महिलाएँ न तो कार्यशील हैं और न ही कार्य की तलाश में हैं।
- IMF तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर भारत की जीडीपी में 27% तक की वृद्धि की जा सकती है।
- ILO के अनुसार, भारत की महिलाएँ औसत रूप से प्रतिदिन 297 मिनट अवैतनिक कार्य करती हैं जबकि पुरुष अवैतनिक कार्यों पर केवल 31 मिनट खर्च करते हैं। इन अवैतनिक कार्यों का आकलन जीडीपी का 3.5% (3.1% महिलाओं के लिये तथा 0.4% पुरुषों के लिये) है।

वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2019 (Corruption Perception Index-2019)

- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (CPI-2019) के अनुसार भ्रष्टाचार के प्रति संवेदन के मामले में भारत का स्थान 80वाँ है जबकि वर्ष 2018 में यह 78वें स्थान पर था।
- भारत को भ्रष्टाचार बोध के लिये 100 में से 41 अंक प्राप्त हुए हैं जो वर्ष 2018 के अंकों के बराबर है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतंत्रों में अनुचित और अपारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण (Unfair and Opaque Political Financing), निर्णय लेने में अनुचित प्रभाव (Undue Influence in Decision-Making) और शक्तिशाली कॉर्पोरेट हित समूहों द्वारा पैरवी करने के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार के नियंत्रण में ठहराव या गिरावट आई है।

निबंध प्रतियोगिता

प्रिय पाठको,

इस प्रतियोगिता के अंतर्गत निबंध का एक विषय दिया जाता है। आप इस विषय पर अधिकतम 1500 शब्दों में निबंध टाइप कराकर निर्धारित तिथि तक हमें भेज सकते हैं। आपके प्रोत्साहन के लिये 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की तरफ से पुरस्कार का प्रावधान भी किया गया है जिसके अंतर्गत **प्रथम तीन विजेताओं को क्रमशः एक साल, 9 महीने एवं 6 महीने तक 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' पत्रिका निःशुल्क भेजी जाएगी।**

प्रतियोगिता के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ इस प्रकार हैं-

निबंध प्रतियोगिता क्रमांक-56

विषयः न्याय में विलंब दरअसल अन्याय है।

प्रतियोगिता के नियमः

1. निबंध अधिकतम 1500 शब्दों में ही होना चाहिये।
2. निबंध मुद्रित (टाइप) कराकर ही भेजें। ध्यान रखें कि हस्तलिखित निबंध स्वीकार नहीं किये जाएंगे। पिछली प्रतियोगिताओं में देखने में आया है कि कुछ प्रतिभागियों के विचार तो अच्छे होते हैं परंतु उनमें शाब्दिक अशुद्धियाँ प्रचुर मात्रा में होती हैं। आपसे निवेदन है कि इसका ध्यान रखें। निबंधों के मूल्यांकन में इसका भी ध्यान रखा जाता है।
3. निबंध की प्रविष्टि दिये गए पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही भेजें। प्रविष्टि भेजने का पता है- कार्यकारी संपादक, दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009. लिफाफे के ऊपर 'निबंध प्रतियोगिता के लिये प्रविष्टि' ज़रूर लिखें।
4. निबंध की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होनी चाहिये।
5. अपनी प्रविष्टि के साथ इसी पृष्ठ पर दिये गए फॉर्म में अपना व्यक्तिगत परिचय लिखकर अवश्य भेजें। ध्यान रखें कि इस फॉर्म के बिना भेजे गए किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. आपकी प्रविष्टि ***20 मार्च, 2020*** तक पहुँच जानी चाहिये। उसके बाद पहुँचने वाली प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रतियोगिता का परिणाम ***मई*** अंक में प्रकाशित होगा।
7. आपके विचार मौलिक होने चाहिये। किसी भी रूप में पूर्व-प्रकाशित व पुरस्कृत निबंधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. निबंध के परिणाम के संबंध में सर्वाधिकार 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के पास सुरक्षित हैं। पुरस्कार विजेताओं के नाम पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित किये जाएंगे और इसकी सूचना दिये गए टेलीफोन नंबर पर भी आपको दे दी जाएगी। प्रतियोगिता के परिणाम के संदर्भ में किसी भी किस्म का पत्राचार अथवा टेलीफोन न करें।

नोटः जो प्रतिभागी निबंध प्रतियोगिता हेतु प्रथम, द्वितीय और तृतीय में से कोई भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं उनकी प्रविष्टियों पर उस अंक से लेकर अगले एक वर्ष के अंक तक कोई विचार नहीं किया जाएगा।

निबंध प्रतियोगिता क्रमांक-54 के सभी विजेताओं को 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की तरफ से ढेरों बधाइयाँ। प्रथम तीन विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं- प्रथम पुरस्कार- प्रत्युष कुमार (वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली); द्वितीय पुरस्कार- दीपक कुमार त्रिपाठी (वज़ीराबाद गाँव, दिल्ली); तृतीय पुरस्कार- ऐश्वर्या भारती (छपरा, बिहार)।

निबंध प्रतियोगिता का फॉर्म

(कृपया इस फॉर्म को फाड़कर अपने निबंध के साथ संलग्न करें। मूल फॉर्म ही भेजें, फोटोकॉपी नहीं।)

प्रतिभागी का नाम ..... मोबाइल नंबर .....

पत्राचार हेतु पता .....

.....

ई-मेल पता .....

करेंट अफेयर्स से जुड़े

संभावित प्रश्न-उत्तर

(मुख्य परीक्षा के लिये)

खंड संयोजन- शशि भूषण (विवेक राही)

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

आधुनिक भारत

प्रश्न: महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर के बीच हुए पूना समझौते के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करें।

उत्तर: ब्रिटिश सत्ता ने वर्ष 1932 में, वर्ष 1909 के भारत अधिनियम में मुस्लिमों के लिये की गई पृथक् निर्वाचन व्यवस्था के समान ही, दलितों के लिये भी पृथक् निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का निर्णय लिया। इसे आधुनिक भारत के इतिहास में सांप्रदायिक निर्णय के शीर्षक से रेखांकित किया जाता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर दलितों के लिये पृथक् निर्वाचन मंडल की व्यवस्था के समर्थक थे। किंतु महात्मा गांधी द्वारा इस निर्णय को अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों की सामाजिक एकता को विखंडित करने के प्रयास के रूप में बताकर इसका पुरज़ोर विरोध किया गया। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने पूना जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया था। अंततः स्वाधीनता आंदोलन के कई नेताओं के प्रयासों के फलस्वरूप 24 सितंबर, 1932 को पूना में गांधीजी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। इस समझौते के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं-

- दलित वर्ग के लिये पृथक् निर्वाचक मंडल की व्यवस्था समाप्त तथा व्यवस्थापिका सभा में उनके लिये हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थान आरक्षित कर दिये गए।
- प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों की सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई।
- केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिये आरक्षित सीटों में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई।

सामाजिक मुद्दे

प्रश्न: हाल के वर्षों में भारत में ऑनलाइन शिक्षा के विकास में तेज़ी देखी जा रही है। इसके कारणों पर विचार करते हुए ऑनलाइन शिक्षा के सम्मुख विद्यमान चुनौतियों की चर्चा करें।

उत्तर: मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क केपीएमजी और गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का ऑनलाइन शिक्षा बाज़ार वर्ष 2016 के 1.6 मिलियन उपयोगकर्त्ताओं तथा 247 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021 तक 9.6 मिलियन उपयोगकर्त्ताओं तथा 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है। यह तथ्य भारत में ऑनलाइन शिक्षा के तीव्र विकास को प्रदर्शित करता है।

कारण

- भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली बाज़ार की मांग के अनुरूप नहीं है तथा कौशल विकास बाज़ार को सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में छात्र और छात्राएँ वैकल्पिक स्रोतों की ओर उन्मुख हैं।
- भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्त्ताओं तथा इंटरनेट सेवाओं के प्रसार में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। इससे ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है।
- सरकार के स्तर पर की गई ई-बस्ता, स्वयं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, पीएम दिशा, स्किल इंडिया तथा डिजिटल भारत जैसी डिजिटल पहलें शिक्षार्थियों हेतु ऑनलाइन शिक्षा के लिये आवश्यक अवसंरचना का निर्माण कर रही हैं। इससे ऑनलाइन शिक्षा की पहुँच का विस्तार हो रहा है।
- ऑनलाइन शिक्षा प्रदाता बाज़ार की मांग के अनुरूप रोज़गारपरक शिक्षा मुहैया करा रहे हैं। ऐसे में रोज़गार प्राप्ति की अधिक संभावना को देखते हुए शिक्षार्थी ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म से तेज़ी से जुड़ रहे हैं।
- ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म्स द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा ऑफलाइन शिक्षा व्यवस्था की अपेक्षा अधिक गुणवत्तापरक है।
- ऑनलाइन शिक्षा की कम लागत भी इसकी बढ़ती लोकप्रियता का एक कारण है।

चुनौतियाँ

- इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही शिक्षा में सामग्रियों की बहुलता है। ऐसे में लाभपरक शिक्षण सामग्री की खोज एक दुष्कर कार्य है।
- देश के विभिन्न हिस्सों में अभी भी इंटरनेट सुविधाएँ या तो उपलब्ध नहीं हैं या उन्नत नहीं हैं। ऐसे में यह सबकी पहुँच से अभी बाहर है।
- विनियमन के सुदृढ़ ढाँचे के अभाव के कारण इसकी प्रामाणिकता संबंधी चुनौती बरकरार है।
- ऑनलाइन शिक्षा शिक्षार्थी को कक्षा में प्राप्त व्यावहारिक अनुभव व समूह शिक्षण, व्यावहारिक कौशल आदि से वंचित करती है।

प्रश्न: हाल ही में संसद द्वारा पास किये गए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इससे संबंधित मुद्दों की पड़ताल करें।

उत्तर: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव व हिंसा से बचाने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में संसद द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पास किया गया है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-

- इस अधिनियम की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ट्रांसजेंडर को परिभाषित किया गया है। अधिनियम के अनुसार ट्रांसजेंडर वे हैं, जिनका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है। इस श्रेणी में ट्रांसजेंडर पुरुष, ट्रांसजेंडर महिलाएँ, मध्यलिंगी भिन्नताओं वाले व्यक्ति, समलैंगिक तथा किन्नर व हिजड़ा जैसे सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति सम्मिलित किये गए हैं।
- इस अधिनियम के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरुद्ध आठ प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध किया गया है-

माइंड मैप

सामान्य अध्ययन के टॉपिक्स पर सटीक व बिंदुवार सामग्री

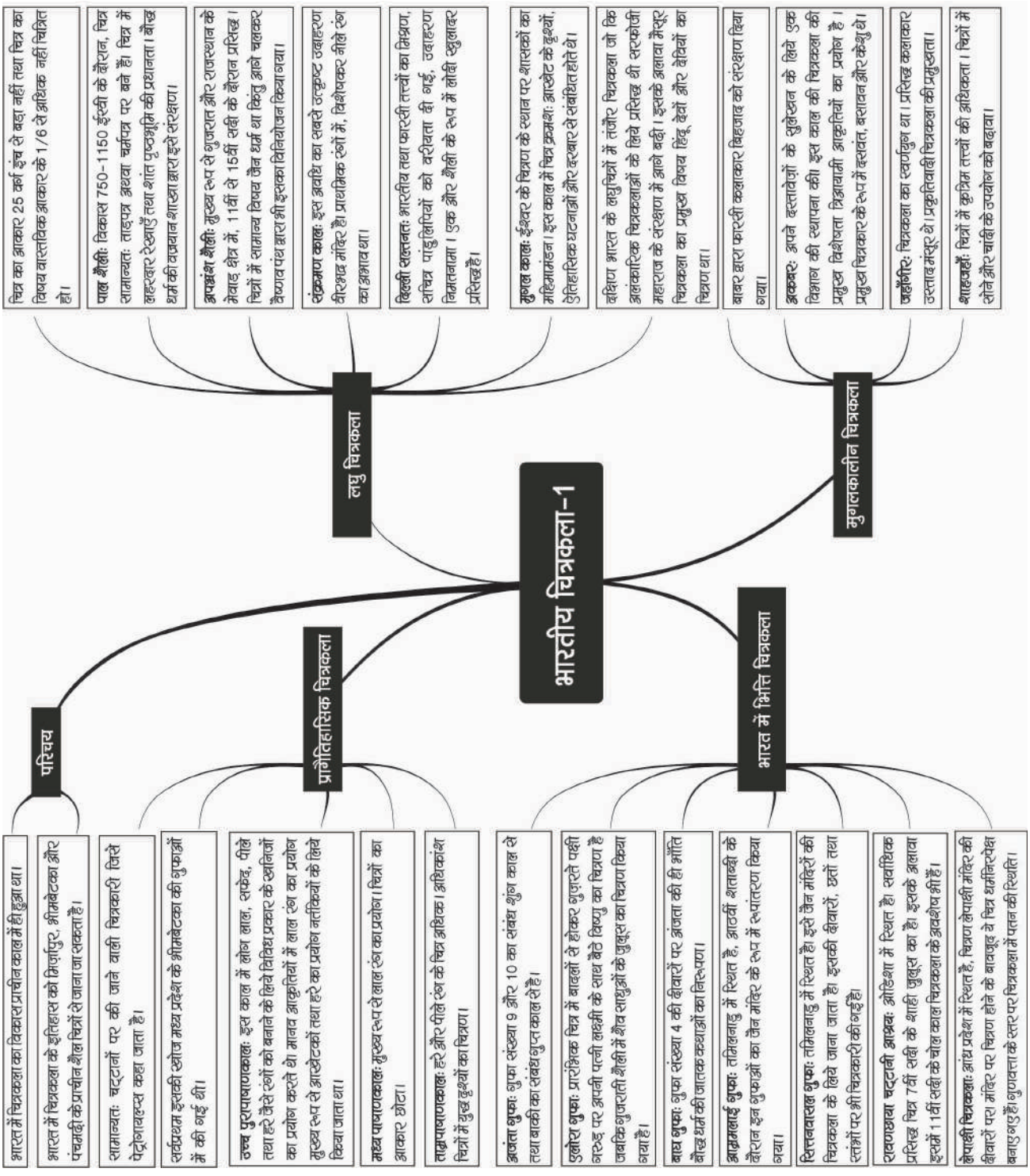

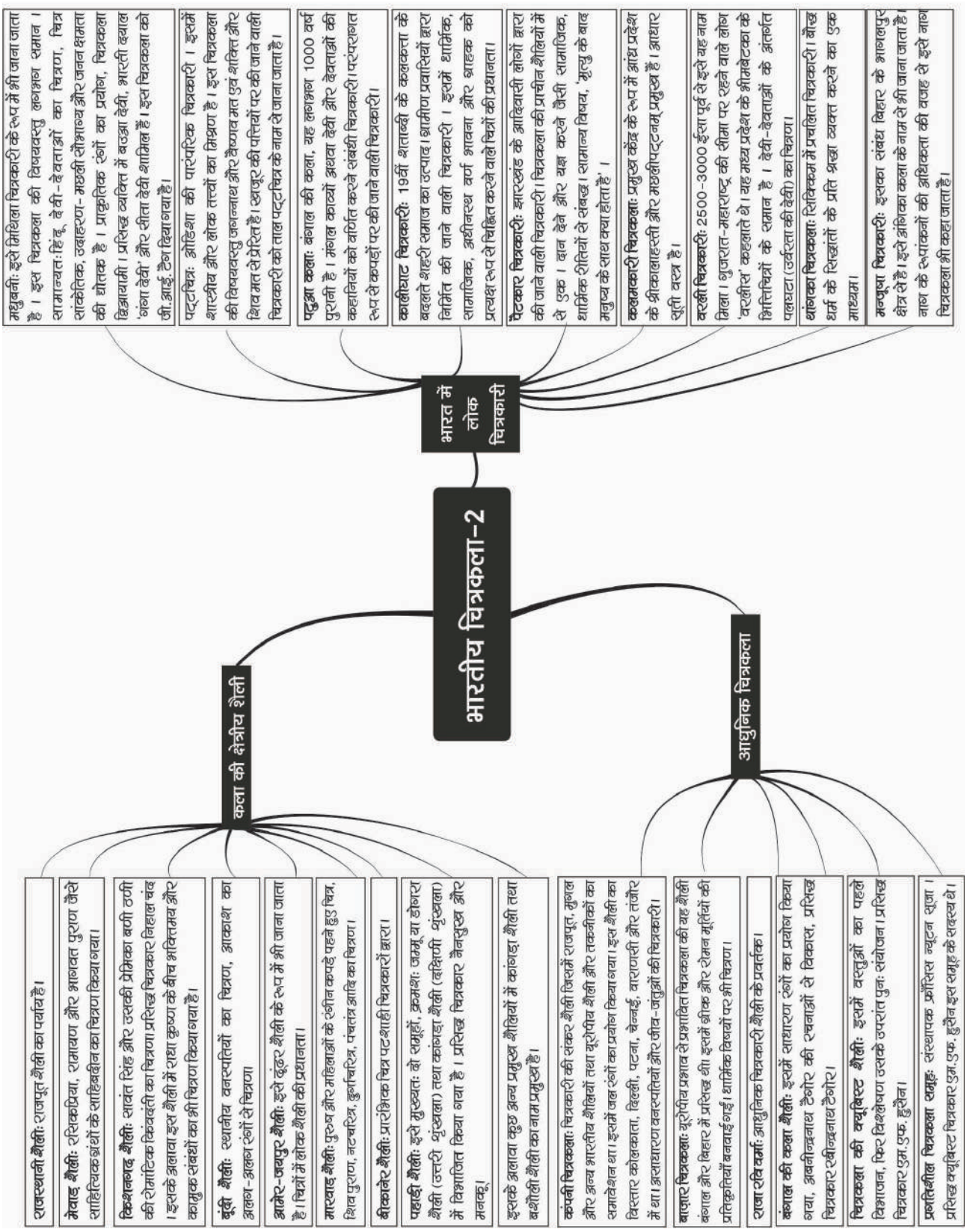

भारतीय चित्रकला-2

भारत में लोक चित्रकारी

- **मधुबनी:** इसे मिथिला चित्रकारी के रूप में भी जाना जाता है। इस चित्रकला की विषयवस्तु लगभग समान। सामान्यतः हिंदू देवी-देवताओं का चित्रण, चित्र सांकेतिक, उदाहरण- मछली सौभाग्य और जनन क्षमता की द्योतक है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, चित्रकला द्विआयामी। प्रसिद्ध व्यक्ति में बउआ देवी, भारती दयाल 'गंगा देवी' और सीता देवी शामिल हैं। इस चित्रकला को जी.आई. टैग दिया गया है।
- **पट्टचित्र:** ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी। इसमें शास्त्रीय और लोक तत्त्वों का मिश्रण है। इस चित्रकला की विषयवस्तु जगन्नाथ और वैष्णव मत एवं शक्ति और शिव मत से प्रेरित है। खजूर की पत्तियों पर की जाने वाली चित्रकारी को ताल पट्टचित्र के नाम से जाना जाता है।
- **पटुआ कला:** बंगाल की कला, यह लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। मंगल काव्यों अथवा देवी और देवताओं की कहानियों को वर्णित करने संबंधी चित्रकारी। परंपरागत रूप से कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी।
- **कालीघाट चित्रकारी:** 19वीं शताब्दी के कलकत्ता के बदलते शहरी समाज का उत्पाद। ग्रामीण प्रवासियों द्वारा निर्मित की जाने वाली चित्रकारी। इसमें धार्मिक, सामाजिक, अधीनस्थ वर्ग भावना और ग्राहक को प्रत्यक्ष रूप से चिह्नित करने वाले चित्रों की प्रधानता।
- **पैटकार चित्रकारी:** झारखंड के आदिवासी लोगों द्वारा की जाने वाली चित्रकारी। चित्रकला की प्राचीन शैलियों में से एक। दान देने और यज्ञ करने जैसी सामाजिक, धार्मिक रीतियों से संबद्ध। सामान्य विषय, 'मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है'।
- **कलमकारी चित्रकला:** प्रमुख केंद्र के रूप में आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम् प्रमुख हैं। आधार सूती वस्त्र है।
- **वरली चित्रकारी:** 2500-3000 ईसा पूर्व से इसे यह नाम मिला। गुजरात-महाराष्ट्र की सीमा पर रहने वाले लोग 'वरलीस' कहलाते थे। यह मध्य प्रदेश के भीमबेटका के भित्तिचित्रों के समान है। देवी-देवताओं के अंतर्गत पलघटा (उर्वरता की देवी) का चित्रण।
- **थांगका चित्रकला:** सिक्किम में प्रचलित चित्रकारी। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम।
- **मन्जूषा चित्रकारी:** इसका संबंध बिहार के भागलपुर क्षेत्र से है। इसे अंगिका कला के नाम से भी जाना जाता है। नाग के रूपांकनों की अधिकता की वजह से इसे नाग चित्रकला भी कहा जाता है।

कला की क्षेत्रीय शैली

- **राजस्थानी शैली:** राजपूत शैली का पर्याय है।
- **मेवाड़ शैली:** रसिकप्रिया, रामायण और भागवत पुराण जैसे साहित्यिक ग्रंथों के साहिबदीन का चित्रण किया गया।
- **किशनगढ़ शैली:** सावंत सिंह और उसकी प्रेमिका बणी ठणी की रोमांटिक किंवदंती का चित्रण। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद। इसके अलावा इस शैली में राधा कृष्ण के बीच भक्तिमय और कामुक संबंधों का भी चित्रण किया गया है।
- **बूंदी शैली:** स्थानीय वनस्पतियों का चित्रण, आकाश का अलग-अलग रंगों से चित्रण।
- **आमेर-जयपुर शैली:** इसे ढूंढर शैली के रूप में भी जाना जाता है। चित्रों में लोक शैली की प्रधानता।
- **मारवाड़ शैली:** पुरुष और महिलाओं के रंगीन कपड़े पहने हुए चित्र, शिव पुराण, नटचरित्र, दुर्गाचरित्र, पंचतंत्र आदि का चित्रण।
- **बीकानेर शैली:** प्रारंभिक चित्र पटशाही चित्रकारों द्वारा।
- **पहाड़ी शैली:** इसे मुख्यतः दो समूहों, क्रमशः जम्मू या डोगरा शैली (उत्तरी श्रृंखला) तथा कांगड़ा शैली (दक्षिणी श्रृंखला) में विभाजित किया गया है। प्रसिद्ध चित्रकार नैनसुख और मनकू।
- इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख शैलियों में कांगड़ा शैली तथा बशौली शैली का नाम प्रमुख है।

आधुनिक चित्रकला

- **कंपनी चित्रकला:** चित्रकारी की संकर शैली जिसमें राजपूत, मुगल और अन्य भारतीय शैलियों तथा यूरोपीय शैली और तकनीकों का समावेशन था। इसमें जल रंगों का प्रयोग किया गया। इस शैली का विस्तार कोलकाता, दिल्ली, पटना, चेन्नई, वाराणसी और तंजौर में था। असाधारण वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की चित्रकारी।
- **बाज़ार चित्रकला:** यूरोपीय प्रभाव से प्रभावित चित्रकला की यह शैली बंगाल और बिहार में प्रसिद्ध थी। इसमें ग्रीक और रोमन मूर्तियों की प्रतिकृतियाँ बनवाई गईं। धार्मिक विषयों पर भी चित्रण।
- **राजा रवि वर्मा:** आधुनिक चित्रकारी शैली के प्रवर्तक।
- **बंगाल की कला शैली:** इसमें साधारण रंगों का प्रयोग किया गया, अबनीन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं से विकास, प्रसिद्ध चित्रकार रवीन्द्रनाथ टैगोर।
- **चित्रकला की क्यूबिस्ट शैली:** इसमें वस्तुओं का पहले विभाजन, फिर विश्लेषण उसके उपरांत पुनः संयोजन। प्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन।
- **प्रगतिशील चित्रकला समूह:** संस्थापक फ्रॉंसिस न्यूटन सूजा। प्रसिद्ध क्यूबिस्ट चित्रकार एम.एफ. हुसैन इस समूह के सदस्य थे।

करेंट अफेयर्स

पर आधारित प्रिलिम्स अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. चंद्रमा की धरती को छूने वाला भारत का पहला मिशन चंद्रयान-2 है।
2. इसरो द्वारा चंद्रयान-2 मिशन की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करने की योजना थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. ग्राम मानचित्र एप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. इसे राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र (NIC) द्वारा विकसित किया गया है।
2. इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
3. यह पंचायतों के लिये एक एकीकृत भू-स्थानिक (Geo Spatial) आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिये:

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. उम्मीद (UMMID) पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. चिकित्सकों के मध्य आनुवंशिक विकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना।
2. इस पहल की शुरुआत जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन तर्कसंगत प्रतीत होते है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

4. वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, 2020 (Global Economic Prospects Report-2020) निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है?

(a) विश्व बैंक
(b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(c) विश्व आर्थिक मंच
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

5. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) भारत के किस शहर में अवस्थित है?

(a) चेन्नई (b) बंगलूरू
(c) हैदराबाद (d) नई दिल्ली

6. कोरोना वाइरस (Corona Virus) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह वाइरस की एक नई प्रजाति है।
2. यह वाइरस गंभीर श्वसन तथा आँतों की बीमारियों का कारण बन सकता है।
3. इससे केवल मनुष्य ही संक्रमित होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यकाल सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है।
2. सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम की धारा 8(1)(J) में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि व्यक्तिगत सूचना, जिसका किसी भी लोक क्रियाकलाप से संबंध नहीं है अथवा जिसकी वजह से व्यक्ति की निजता का अनुचित अतिक्रमण हो सकता है, ऐसी सूचना केवल तभी सार्वजनिक की जा सकती है जबकि अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट हो जाए कि व्यापक लोकहित में ऐसी सूचना का प्रकटीकरण उचित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

8. H9N2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह इनफ्लुएंज़ा A वाइरस का एक उपप्रकार है जो कि मनुष्य में बर्ड फ्लू और इनफ्लुएंज़ा (Infulenza) के संक्रमण का कारण बनता है।
2. भारत के पोल्ट्री फॉर्म में इस वाइरस को पहली बार जनवरी 2020 में देखा गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

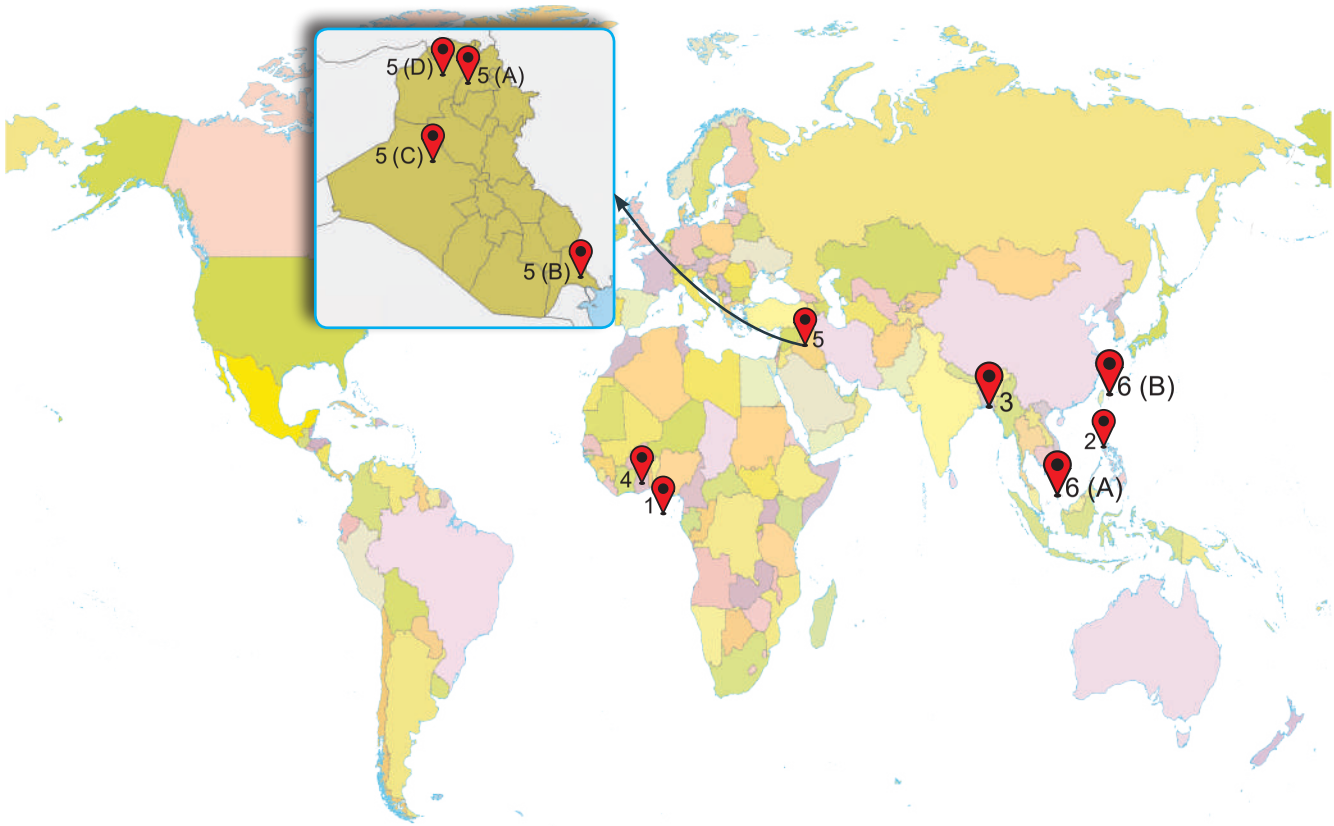

मानचित्र-1 (विश्व)

प्रश्न

1. उस खाड़ी की पहचान कीजिये जो दुनिया के जलदस्युता (Piracy) केंद्र के रूप में उभरी है।
2. मनीला के पास स्थित ज्वालामुखी की पहचान कीजिये जिसका हाल ही में विस्फोट हुआ है।
3. उस द्वीप की पहचान कीजिये जहाँ बांग्लादेश रोहिंग्याओं को बसा रहा है।
4. उस देश की पहचान कीजिये जिसने अपनी राष्ट्रीय एलपीजी संवर्धन नीति को लागू करने के लिये भारत से सहायता मांगी है।
5. इराक के उन स्थानों की पहचान कीजिये जो अक्सर समाचारों में दिखाई देते हैं।
6. चीन से जुड़े इन विवादित द्वीपों की पहचान कीजिये।

(इस मानचित्र के उत्तर पेज-205 पर देखें)

मानचित्र

जाँचिये कि क्या आप इन नक्शों में

से सीखें

रेखांकित स्थानों को पहचानते हैं?

मानचित्र-2 (भारत)

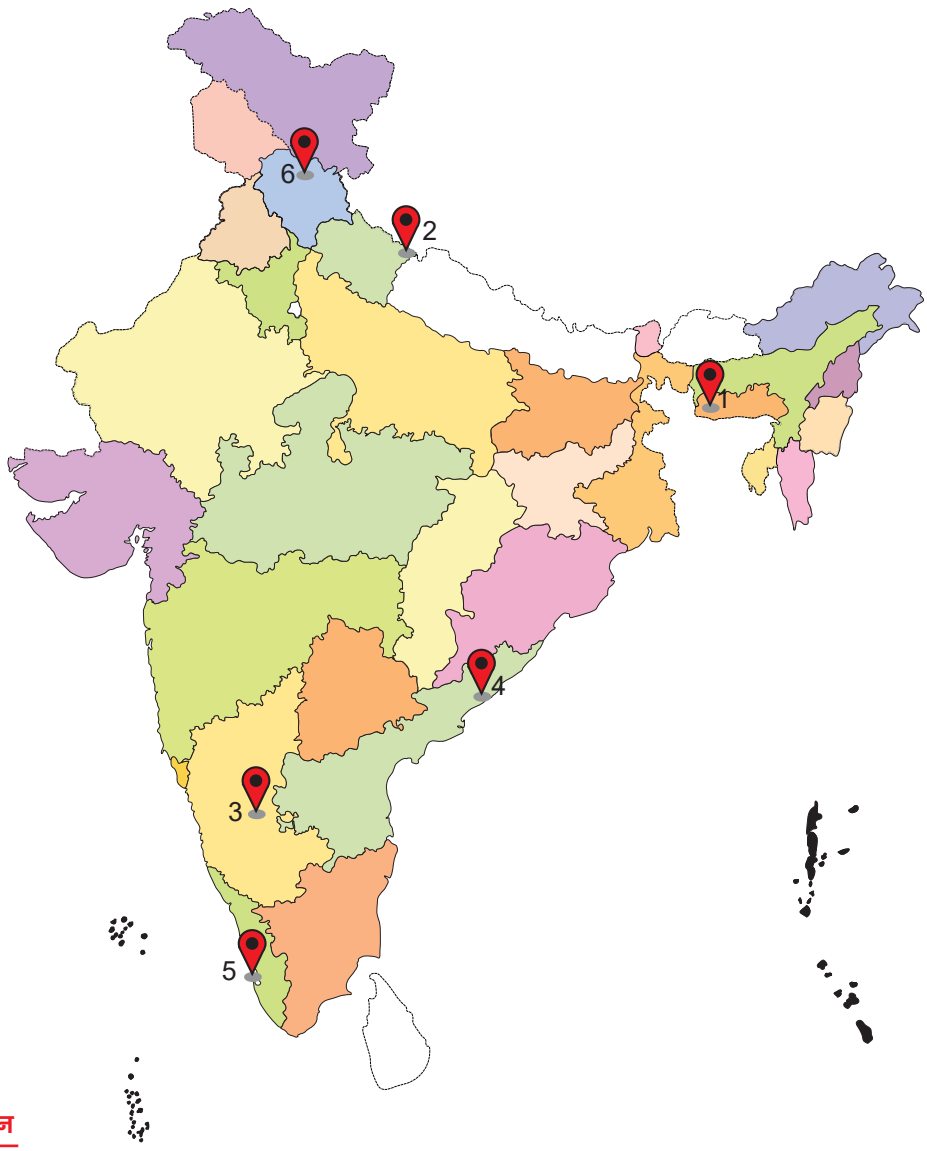

प्रश्न

1. मेघालय में स्थित बायोस्फीयर रिज़र्व की पहचान कीजिये।
2. भारत और चीन को जोड़ने वाले दर्रे की पहचान कीजिये।
3. इसरो द्वारा अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (Human Space Flight Centre, HSFC) के लिये चयनित स्थान की पहचान कीजिये।
4. उस शहर की पहचान कीजिये जहाँ मिलन 2020 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा।
5. भारत के सबसे बड़े कृत्रिम द्वीप की पहचान कीजिये।
6. उस दर्रे की पहचान कीजिये जिससे होकर अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग का निर्माण किया जाना है।

(इस मानचित्र के उत्तर पेज-205 पर देखें)

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

BASIC ENGLISH CLASSES

5000+ Vocabes, Parts of Speech (Noun, Pronoun, Preposition etc.) और Tenses से लेकर English Grammar के अन्य टॉपिक्स के नियमों एवं व्यावहारिक उपयोग सहित Essay, Reading Comprehension, Precis Writing की चर्चा एवं अभ्यास हेतु समग्र कक्षा कार्यक्रम

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

- 40–50 क्लासेज़ (प्रत्येक कक्षा 2 घंटे की)
- सप्ताह में 3 दिन (सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार) क्लासेज़
- वर्कशीट्स के माध्यम से प्रतिदिन प्रैक्टिस सत्र और कक्षा-आधारित गृह-कार्य (Home Work)
- प्रत्येक क्लास के बाद आधे घंटे का अतिरिक्त सेशन कमजोर छात्रों के लिये
- Spoken English (Conversation and Group Discussion)
- English Newspaper Reading and Understanding
- प्रत्येक सत्र में लगभग 10 सेक्शनल टेस्ट
- Essay और Precis Writing पर विशेष अभ्यास सत्र

मैथडोलॉजी

- आसान भाषा में वैज्ञानिक तरीके से अंग्रेज़ी भाषा के नियमों की समझ
- जटिल नियमों को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास
- थ्योरी और प्रैक्टिस पर बराबर बल

ओरिएन्टेशन क्लास के साथ सत्र प्रारंभ

17 फरवरी

सायं 3:00 - 5:00 बजे

फीस

- दृष्टि के छात्रों के लिये : ₹5000 (GST सहित)
- अन्य छात्रों के लिये : ₹8000 (GST सहित)

कक्षा स्थल

707, प्रथम तल, मुखर्जी नगर (बत्रा सिनेमा के सामने), दिल्ली-110009

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें:

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 फोन: 87501 87501, 011-47532596

टारगेट प्रिलिम्स-2020
चौथी कड़ी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

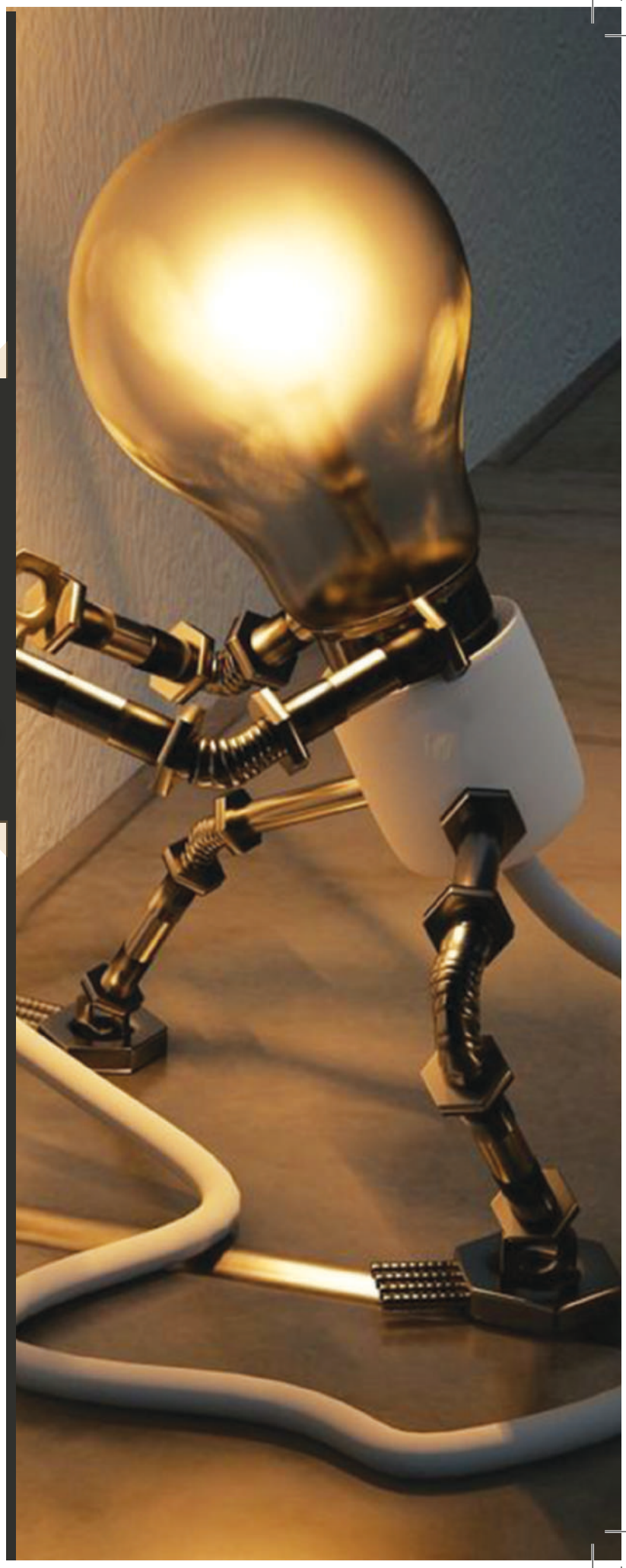

प्रिय अभ्यर्थियो,

'सुपरफास्ट रिवीज़न' की चौथी कड़ी में हम 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी' खंड पर सामग्री दे रहे हैं। आप जानते ही हैं कि यह खंड न केवल आई.ए.एस. प्रारंभिक परीक्षा बल्कि विभिन्न पी.सी.एस. परीक्षाओं के लिये भी अत्यंत महत्त्व रखता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस विषय पर सरल, संक्षिप्त व बिंदुवार सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह सामग्री आपकी तैयारी को समग्रता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी।

अभ्यास प्रश्न

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय से संबंधित प्रिलिम्स अभ्यास प्रश्न-पत्र

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ संघ (IDF) द्वारा जारी किये गए डायबिटीज़ एटलस के नौवें संस्करण में भारत डायबिटीज़ से पीड़ित मरीज़ों की संख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा।
2. अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ संघ (IDF) 168 देशों और प्रदेशों के कुल 240 राष्ट्रीय डायबिटीज़ संस्थाओं का एक संगठन है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. क्वांटम कम्प्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसमें सूचनाओं की एनकोडिंग के लिये क्यूबिट का इस्तेमाल किया जाता है।
2. क्वांटम कम्प्यूटिंग के इलेक्ट्रॉन स्पिन अप तथा स्पिन डाउन दोनों करते हैं।
3. यह एक डिस्ट्रिब्यूटेड कम्प्यूटिंग प्रणाली है जो कि लॉन्ग रूट डेटा सेंटर या क्लाउड की बजाय नज़दीकी नेटवर्क पर कार्य करती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रकाश को उसके घटक तरंगदैर्ध्य में विभाजित करने संबंधी एक तकनीकी है।
2. इस तकनीकी का इस्तेमाल किसी भौतिक परिघटना के दौरान निकले उसके वर्णक्रमीय घटकों की पहचान एवं उसके पृथक् मापन के लिये किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

4. फास्टैग (FASTag) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली है।
2. इसे भारत के राष्ट्रीय हाइवे प्राधिकरण (NHAI) के माध्यम से संचालित किया जाता है।
3. यह प्रणाली रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीकी के माध्यम से कार्य करती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

5. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते है/हैं?

1. यह नासा के लिविंग विद् स्टार प्रोग्राम का हिस्सा है।
2. यह सूर्य के कोरोना से निकलने वाली ऊष्मा तथा ऊर्जा का अध्ययन करेगा।
3. हालाँकि यह सूर्य के पास भेजे जाने वाले मानव निर्मित सौर मिशन का परीक्षण तो नहीं कर पाएगा किंतु यह सूर्य से संबंधित व्यापक जानकारियों को एकत्रित कर पृथ्वी पर भेजने का कार्य करेगा।

नीचे दिये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:

(a) केवल 1 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

6. निम्नलिखित में से किसका संबंध फेडोर (Fedor) से है?

(a) यह रूस का एक ह्यूमैन्वॉयड रोबोट है।
(b) अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी (ISS) के लिये नासा और जाक्सा (Jaxa) का एक संयुक्त मिशन।
(c) नासा द्वारा तैयार की गई एक रोबोटिक कार।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

7. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये:

अंतरिक्ष में भेजे गए ह्यूमैन्वॉयड रोबोट		**देश**
1. फेडोर	–	रूस
2. रोबोनॉट-2	–	नासा
3. किरोबो	–	जापान

उपर्युक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

8. लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह एक रिचार्जेबल बैटरी होती है।
2. हाल ही में इस बैटरी के विकास के लिये वैज्ञानिक जॉन गुडइनफ़, स्टेनली व्हिटिंगम तथा अकीरा योशिनो को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

'आपके पत्र'

मैं दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे का विगत 2 वर्ष से पाठक हूँ। इस पत्रिका को पढ़ने से मैं स्वयं को काफी अद्यतित पाता हूँ, क्योंकि इस पत्रिका में प्रारंभ से अंत तक जो खंड निहित हैं वे एक सिविल सर्विस के अभ्यर्थी की सारी जिज्ञासाओं को शांत कर पाने में सक्षम हैं। हिंदी माध्यम में पहले एक अनूठी प्रतिभा का अभाव था, वहीं यह इस अंतर को भरने में सक्षम है। 'संपादक की कलम से' खंड जो हमें समग्र व संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करने के साथ-साथ परीक्षोपयोगी सलाह को पहुँचाने का काम करता है। 'टॉपर से बातचीत' एक ऐसा खंड है कि कोई भी अभ्यर्थी टॉपर्स की बातों का अनुसरण कर अपने कॅरियर को नई दिशा दे सकता है। लेख-खंड के द्वारा हाल-फिलहाल के चर्चित एवं परीक्षोपयोगी मुद्दों पर सोच का दायरा विकसित होकर एक विस्तृत दृष्टिकोण बनता है। करेंट अफेयर्स जो कि इस परीक्षा के लिहाज़ से महत्त्वपूर्ण खंड है का वरीयतानुसार प्रस्तुतीकरण इसे अनूठा बनाता है तथा संबंधित विषय के सभी आयामों से अभ्यर्थियों को परिचित करा दिया जाता है। 'जिस्ट' खंड जो योजना, कुरुक्षेत्र और अन्य महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार समाहित किये है इससे हमारे समय और धन की भी बचत सुनिश्चित होती है। इसके अलावा 'निबंध' खंड जो हमें नए टॉपिक प्रदान कर हमारी लेखन शैली को और निखारता है।

'माइंड मैप' खंड से जहाँ हमें किसी भी विषय के बारे में सारी सूचनाएँ और तथ्य सुगम तरीके से स्मरण पटल पर स्थायी और अविस्मरणीय हो जाते हैं। 'मानचित्रों से सीखें' खंड हमारी मानचित्र पर पकड़ मज़बूत करने के साथ ही जीएस के लिये काफी फायदेमंद है। इसके इतर समय-समय पर परीक्षा-विशेष सामग्रियाँ रोचक तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं।

-अभिषेक यादव बिल्हौर, कानपुर नगर (पुरस्कृत पत्र)

मैं दृष्टि 'करेंट अफेयर्स टुडे' का पिछले तीन वर्षों से नियमित पाठक रहा हूँ और यह पत्रिका न केवल मेरे सामान्य अध्ययन को अद्यतन रखने में मेरी भरपूर सहायता करती है अपितु विभिन्न नवीन मुद्दों पर संक्षिप्त नोट्स, माइंड मैप आदि के माध्यम से क्विक रिवीज़न में भी अत्यंत लाभकारी है। मुझे इस पत्रिका की सबसे बड़ी विशेषता 'विकास सर' का संपादकीय पृष्ठ लगता है जिसको पढ़ना मेरे लिये सबसे उत्साहित करने वाला क्षण होता है, जो न केवल विभिन्न मनोवैज्ञानिक विषयों पर मेरी समझ को विकसित करता है अपितु मुझे प्रेरणा भी प्रदान करता है। ***-लकी कुमार, हाथरस (उत्तर प्रदेश)***

मैंने दृष्टि की करेंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका पहली बार ही पढ़ी है। और पहली बार में ही इसमें इतना ज़बरदस्त मैटर पाया कि उसे व्यक्त करने के लिये मेरे पास शब्द कम पड़ गए। दृष्टि टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद।

-प्रशन कुमार अवस्थी

मैं इस मैगज़ीन को दो सालों से नियमित पढ़ता हूँ। टॉपर से बातचीत में जो संवाद दिया जाता है इसमें कई सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। संपादक की कलम से पढ़ने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले स्टूडेंट के सामने अच्छे लेख की समस्या हमेशा दंश मारती है जिसमें दृष्टि मैगज़ीन के आलेख खंड का सराहनीय योगदान रहता है। बहुत-बहुत साधुवाद दृष्टि टोली को। ***-रोहित पटेल, झाँसी (UP)***

मैं दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे का अध्ययन पिछले एक वर्ष से कर रहा हूँ। सिविल सेवा परीक्षा का वर्तमान दौर करेंट अफेयर्स पर निर्भरता वाला है। ऐसे में परीक्षा के लिये कई अखबार व पत्रिकाओं का अध्ययन करना उपलब्धता व समय की दृष्टि से दुष्कर है परन्तु दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे सभी पत्रिकाओं व समाचार पत्रों से आवश्यक खबरें स्वत: उपलब्ध करा देती है जो सराहनीय है।

-श्रीधर मिश्रा गुजौली, बहराइच, (उत्तर प्रदेश)

मैं दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे का पिछले 3 वर्षों से नियमित पाठक हूँ। तैयारी की शुरुआत से ही यह मैगज़ीन बहुत उपयोगी साबित हुई है। संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए इस मैगज़ीन में 'संपादक की कलम' से जो शब्द लिखे जाते हैं वे बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं। दिव्यकीर्ति सर द्वारा लिखा हुआ एक-एक शब्द परीक्षा के दौरान महत्त्व का होता है। ***-इंद्रदेव यादव***

मैंने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और मुझे दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे की एक मैगज़ीन मिली जिसे पढ़कर मैं तैयारी के लिये और मज़बूत हो गया। डॉ. विकास दिव्यकीर्ति सर के 'संपादक की कलम से' लेख ने अभूतपूर्व छाप छोड़ी है जिसे पढ़कर मन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। वास्तव में दृष्टि आई.ए.एस. जैसा और कोई हो नहीं सकता। ***-मो. इमरान***

हम प्रयागराज शाखा में बैच 5 तथा हिंदी साहित्य और भूगोल वैकल्पिक विषय के विद्यार्थी हैं। हम पिछले 6 माह से इस मैगज़ीन के पाठक हैं। इसमें दृष्टि टीम द्वारा लिखित अत्यन्त सहज लेखों और नए विचारों ने हमें काफी मनोबल एवं उत्साह के साथ पढ़ाई करने में अहम भूमिका निभाई।

रोहित कुमार पटेल, बांदा (उत्तर प्रदेश)

दिग्विजय सिंह मौर्य, काशीपुर (उत्तराखंड)

मुकेश कुमार यादव, जयपुर (राजस्थान)

शशांक सैनी, उन्नाव (उत्तर प्रदेश)

सर्वप्रथम मैं 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे टीम' और संपूर्ण दृष्टि टीम को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपनी नवप्रवर्तनकारी पहल तथा आकर्षक रूपरेखा के माध्यम से संपूर्ण मासिक घटनाक्रम को प्रस्तुत करने के साथ-साथ हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में एक उमंग और उत्साहवर्द्धन की क्षमता अद्वितीय है।

'संपादक की कलम से' एक ऐसी नवप्रवर्तनकरी पहल है जो उच्च व्यक्तित्व के साथ-साथ आदर्श नज़रिये को भी बढ़ाती है। धन्यवाद।

-अतुल पवार (इंदौर, मध्य प्रदेश)

दृष्टि की मासिक पत्रिका हमारे आदर्श विकास दिव्यकीर्ति सर के आदर्श वाक्य के साथ शुरू होती है। इसमें समाहित खंड, जैसे- करेंट अफेयर्स, जिस्ट और टारगेट जो आपके प्रिलिम्स के लिये कारगर साबित होते हैं। इसका संकलित लेख खंड इसे विचारणीय बनाता है। नि:संदेह यह मासिक पत्रिका अन्य मासिक पत्रिकाओं से बेहतर साबित होती है।

-अमरजीत सिंह तोमर (नुमर, जमुई)

मैं जुलाई 2018 के अंक से दृष्टि करेंट अफेयर्स का नियमित पाठक हूँ। मैगज़ीन काउंटर से पत्रिका प्राप्त करने के साथ 'संपादक की कलम से' पढ़े बिना मैं अंदरूनी पृष्ठों पर आगे बढ़ ही नहीं पाता हूँ। इसके लेख खंड, करेंट अफेयर्स व एथिक्स अनुभाग से गुणवत्तापूर्ण तर्कों और सुझावात्मक विचारों के माध्यम से केस स्टडी में बिंदुओं को शामिल करने तथा उत्तर लेखन के निष्कर्षों में पक्षों को समाहित करने में काफी सकारात्मक सफलता मिली। इसके अतिरिक्त, मैगज़ीन की संपूर्ण सुस्पष्ट विषयवस्तु व डिज़ाइन 'गागर में सागर' के समान है जो जीवन एवं पढ़ाई के अनुभवों से सरोकार कराती है और इसी का परिणाम है कि जब भी मित्र या सहपाठी मुझसे पूछते है कि करेंट अफेयर्स कैसे व कहाँ से कवर कर रहा है? तो, जुबां पे एक ही नाम- 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे'।

-शेरसिंह मीणा (राजस्थान) दृष्टि की पूरी टीम को हमारा प्रणाम।

मैं दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे का 2017 से नियमित पाठक हूँ। यह पत्रिका पढ़ने वालों के लिये अत्यंत रुचिकर है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिये तो यह मैगज़ीन एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ डाटा सहित उपलब्ध कराती ही है, साथ ही यह हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिये रामबाण सिद्ध हो सकती है। इसके अलावा, यह मैगज़ीन शासकीय सेवकों, जनप्रतिनिधियों को विशेषकर पढ़नी चाहिये क्योंकि यह उक्त लोगों को व उनके काम करने के तरीके को ज़्यादा प्रभावशाली और लोककल्याणकारी बना सकती है। मैं शासकीय सेवक होते हुए भी इस पत्रिका का नियमित अध्ययन करता हूँ और भविष्य में ऐसे ही इस पत्रिका से विश्वसनीय और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करता रहूंगा।

-धर्मेन्द्र अटल, ज़िला- भिंड (मध्य प्रदेश)

मैं दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे का जनवरी 2019 से नियमित पाठक हूँ। यह निःसंदेह हिंदी माध्यम की सिविल सेवा के परीक्षार्थियों हेतु सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका है। हर महीने की शुरुआत में इसके नए अंक व डॉ. विकास दिव्यकीर्ति सर के लेख का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे पर चल रहे 'टारगेट प्रिलिम्स 2020' से किसी विषय की शुरुआत करने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। 'जिस्ट' पढ़ने पर कई पत्र-पत्रिकाओं के सामान्य सार की जानकारी हो जाती है तथा हर महीने मानचित्रों को देखकर न चाहते हुए भी 'एटलस' उठ जाता है। 'लेख खंड' पढ़कर लिखने व सोचने की क्षमता में वृद्धि महसूस हो रही है।

-सूरज कुमार (उत्तर प्रदेश)

मैंने दृष्टि आईएएस में 2015 बैच में पढ़ाई की थी, विकास दिव्यकीर्ति सर के द्वारा पॉलिटी, एथिक्स और निबंध पढ़ाया गया था जिससे मेरा आधार मज़बूत हुआ था, और उसके बाद निरंतर मैं दृष्टि की मैगज़ीन की पढ़ाई करता रहा और आज उसी की बदौलत छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा 2018 के घोषित परिणाम में 54वाँ रैंक प्राप्त हुआ है। विकास दिव्यकीर्ति सर और पूरी दृष्टि टीम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से आज मैंने सफलता प्राप्त की है। धन्यवाद

-प्रकाश पटेल

सबसे पहले मैं आपको तहेदिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैंने इस पत्रिका को पहली बार 2018 में उपहारस्वरूप प्राप्त किया, तब से मैं इसकी नियमित पाठिका हो गई हूँ।

इस पत्रिका ने मेरे सपनों को पंख लगा दिये और मुझे मेरी मंज़िल के करीब लाने में सहायक साबित हुई है। इस पत्रिका की सबसे खास बात है कि जटिल-से-जटिल विषयवस्तु का सहजता से प्रस्तुतीकरण। पत्रिका की शुरुआत में विकास दिव्यकीर्ति सर द्वारा कॉलम 'संपादक की कलम से' विद्यार्थियों के लिये नए विचार प्रस्तुत करता है। इसके सभी कॉलम, जैसे- टॉपर से बातचीत, निबंध खंड, माइंड मैप आदि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिये समान रूप से उपयोगी होते हैं। दृष्टि पत्रिका की एक सबसे अहम एवं खास बात है जो इसे अन्य किसी भी पत्रिका से बेहतर बनाती है, वह है- परीक्षा की मांग के अनुरूप परिवर्तन करना। यह पत्रिका अब हम जैसे दूरदराज़ तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के लिये मददगार साबित हो रही है।

-महिमा राज दीघवादूबौली (गोपालगंज) बिहार

मैं इस पत्रिका का वर्ष 2017 से निरंतर पाठक रहा हूँ। कई और स्रोत पढ़े परन्तु दृष्टि मैगज़ीन सर्वोत्तम लगी। न सिर्फ तैयारी के स्तर पर अपितु आत्मबल भी निरतंर बढ़ता रहता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिये अंत में दिये गए प्रश्न व मुख्य परीक्षा के लिये भी सर्वोत्तम कंटेंट मिलता है। धन्यवाद दृष्टि टीम व दिव्यकीर्ति सर।

-अभिनय सिंह (शाहजहाँपुर)

मैं 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' पत्रिका की अप्रैल 2019 से नियमित पाठिका रही हूँ। दृष्टि पत्रिका मुझ जैसी हिंदी माध्यम की छात्राओं के लिये एक विश्वसनीय आधार उपलब्ध कराती है जो अन्य कहीं सुलभ नहीं है। विभिन्न संस्करणों में विकास सर के नए-नए लेखों से मैं स्वयं को सिविल सेवाओं के लिये मानसिक रूप से तैयार कर पाती हूँ। पत्रिका के टॉपर से बातचीत वाले अंश से मैं हर बार कुछ नया सीखती हूँ। लेख खंड और कुरुक्षेत्र एवं योजना जैसी पत्र-पत्रिकाओं का एडिशन विभिन्न मुद्दों पर मेरी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मानसिकता को स्पष्ट करता है। साथ ही, माइंड मैप और टारगेट प्रिलिम्स जैसी विशेष सामग्रियाँ मेरे रिवीज़न को नियमितता प्रदान करती हैं जो निश्चित रूप से सभी छात्र-छात्राओं के लिये एक नियोजित सामग्री है। मेरी सफलता में इस विशेष सामग्री लिये मैं दृष्टि और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ।

-रजनी राय, सारण

मैं वर्ष 2018 से दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे पत्रिका का नियमित पाठक रहा हूँ। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिये यह पत्रिका किसी पारसमणि से कम नहीं है जो प्रत्येक विषय पर न केवल अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराती है बल्कि अभ्यर्थियों की उत्तर लेखन शैली को भी परिमार्जित करती है। प्रश्न पत्रों की प्रकृति और मांग के साथ जिस प्रकार यह पत्रिका तारतम्यता स्थापित करती है वह अपने आप में अनूठा है। और सबसे बड़ी बात, इसके लेखन संबंधी नवोन्मेष इसकी महत्ता को प्रबल बनाते हैं। धन्यवाद टीम दृष्टि!

-मोहित द्विवेदी

इनके भी पत्र मिले- अभिलाष राय, बलिया, (उत्तर प्रदेश), भारती कुशवाहा, निमेश श्रीवास्तव, नीरज कुमार (अयोध्या)।

आप सभी पाठकों की बहुमूल्य प्रतिक्रिया के लिये हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएँ हमें हौसला देती हैं एवं निरंतर बेहतर करने के लिये प्रोत्साहित करती हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कार्यकारी संपादक की ई-मेल आईडी *purushottam@groupdrishti.com* पर भेजें। आपकी चुनिंदा प्रतिक्रियाओं को हम आपके नाम के साथ मैगज़ीन में छापेंगे तथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया भेजने वाले को उपहारस्वरूप अगले तीन महीने की मैगज़ीन भेजेंगे।

धन्यवाद

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

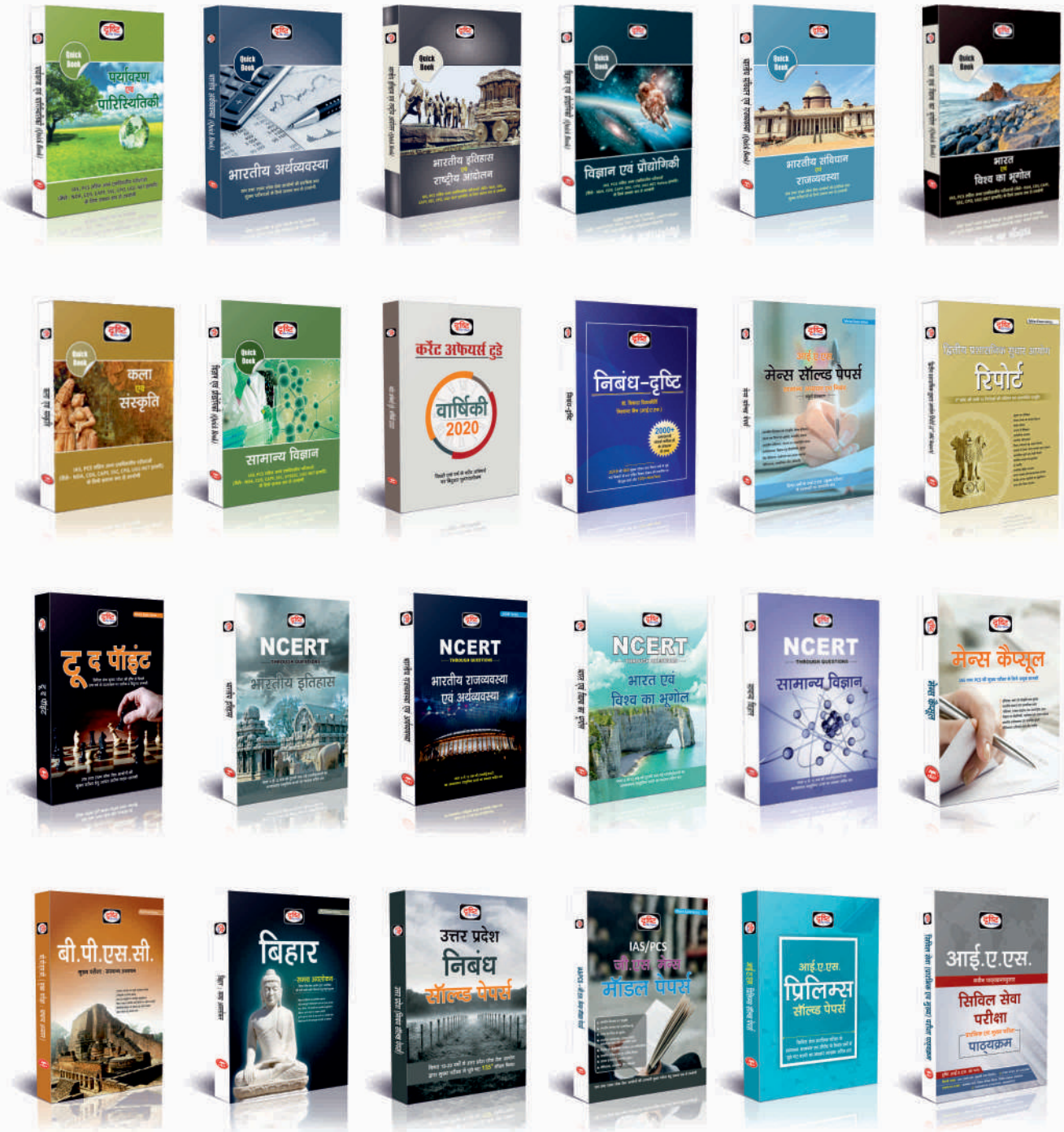

641, Ist Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9 Ph.: 87501 87501, 011-47532596

E-mail: online@groupdrishti.com, *Website: www.drishtiias.com